

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



अगस्त 2017
खंड 71 अंक 8

संपादन समिति
जनक राज
गौतम चैटर्जी
अमिताभ सरदार
राजीव रंजन

संपादक
सुनील कुमार

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादन समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेख में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2017

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से <http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषयवस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18	1
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य	7

भाषण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - वर्तमान स्थिति, समस्याएं और आगे की कार्ययोजना एस.एस. मूंदड़ा	9
भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री विरल वी. आचार्य	17

लेख

भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह लेखे : 2015-16	23
वर्तमान सांख्यिकी	35
हाल के प्रकाशन	72

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो को 6.25 से 25 आधार अंक कम करके दर 6.00 प्रतिशत किया जाए।

इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है जो वृद्धि को सहारा देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति का 4% का उद्देश्य +/- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर हासिल करने के मध्यावधि लक्ष्य के अनुरूप है। इस निर्णय को रेखांकित करने वाले मुख्य विचारों को नीचे वक्तव्य में दिया गया है।

आकलन

2. एमपीसी की जून 2017 की बैठक के समय से, वृद्धि की इच्छा वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ी है, हालांकि फिर भी स्व-संधारणीय सुधार की ताकत का अभाव दिखाई दे रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में, अमेरिका में पहली तिमाही की कमजोरी के बाद दूसरी तिमाही में तेज गति से वृद्धि हुई है, जिसमें स्थिर रूपसे उन्नत हो रही बाजार स्थिति, बढ़ते उपभोक्ता खर्च, प्रत्याशा से अधिक नरम मुद्रास्फीति की सहायता से हासिल सकारात्मक उपभोक्ता विश्वास और उन्नत हो रहे औद्योगिक उत्पादन से मदद मिली है। तथापि, नीति और राजनीतिक जोखिम इस संभावना पर मंडराए हुए

हैं। यूरो क्षेत्र में कम होती बेरोजगारी और निजी उपभोग में वृद्धि के सहारे संघटक अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक सुधार हुआ है, राजनीतिक अनिश्चितता उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। जापान में, नरम किंतु स्थिर बढ़ोतरी हो रही है जिसे मजबूत होते निर्यात, त्वरित औद्योगिक उत्पादन और मजदूरी में वृद्धि से सहायता मिली है।

3. उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, दूसरी तिमाही में चीन में वृद्धि पुनः प्राप्त हो रही है जहां खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन स्थिर गति से बढ़ रहा है। फिर भी, डिलीवरेजिंग वित्तीय संस्थाओं और भूसंपदा में मंदी के कारण सख्त वित्तीय स्थिति का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। रूसी अर्थव्यवस्था दो वर्ष की मंदी से उभर आई है जिसे कम होती बेरोजगारी, बढ़ती खुदरा बिक्री और मजबूत औद्योगिक उत्पादन से सहायता मिली। ब्राजील में नरम सुधार राजनीतिक अनिश्चितता और अब भी दबावग्रस्त श्रम बाजार के कारण कमजोर बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक गतिविधि संरचनागत और संस्थागत बाधाओं से घिरी हुई है तथा तकनीकी मंदी में है।

4. वैश्विक मांग और पण्य-वस्तुओं की कीमतों के उदार रूप से बढ़ने से वैश्विक व्यापार मात्रा में सहायता मिली है जो मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते निर्यात और आयात में प्रतिलक्षित हुई है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में कच्चे तेल की कीमतों में मंदी के बावजूद थोड़ी वृद्धि हुई जो अमेरिका में इन्वेंटरी में कमी आने के कारण हुई, किंतु आपूर्ति का अभी भी झुकाव है। चीनी मांग ने धातुओं की कीमतों को, विशेषकर कॉपर बढ़ा दिया है। बुलियन की कीमतें उन्नत जोखिम आघात सहनीयता के कारण कई महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई किंतु भौगोलिक-राजनीतिक वातावरण में बदलावों के प्रति कमजोर बनी हुई हैं। इन गतिविधियों के बावजूद, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है और अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मंद है।

5. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार राजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रति लचीले बने हुए हैं और केवल प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा तुलनपत्र समायोजनों के संकेतों के प्रति छिटपुट प्रतिक्रियाओं को छोड़कर अस्थिरता कम हुई है। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों में बढ़ोतरी दर्ज हुई

* 02 अगस्त 2017 को जारी।

इसमें अमेरिका में सूचकांक पहले के उच्चतम स्तर को पार कर गए किंतु यूरोपीय बाजारों में ब्रेजिट वार्तालाप और मजबूत होते यूरो के कारण गिरावट आई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजार में बढ़ती वैश्विक जोखिम सहनीयता क्षमता के कारण बढ़ोतरी देखी गई है जिसमें उन्नत होते समष्टि आर्थिक मूल तत्वों से सहायता मिली जो पूंजी अंतर्वाह को आकर्षित कर रहे हैं। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रत्याशाओं से सख्त हो गए, जिसमें जर्मन बॉन्ड वर्ष के अंदर उच्च सीमा पर पहुंच गए। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, स्थिति विविध रही और ऐसा घरेलू कारकों के कारण हुआ तथा स्थायी आय बाजारों को सामान्य रूप से बॉन्ड सेल-ऑफ से सुरक्षित किया गया। मुद्रा बाजारों में अमेरिकी डॉलर और कमजोर हो गया और कम मुद्रास्फीति तथा अमेरिकी प्रशासन की नीतियों की अनिश्चितता से जुलाई में कई महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। यूरो जो मजबूत बना रहा है, उसमें सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के कारण और मजबूती आई। जापानी येन सुरक्षित आश्रय मांग क्षणिक मूल्यवृद्धि द्वारा सामान्य रूप से सहज, छितराया हुआ है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं मुख्य रूप से स्थिर रही और मूल्यवृद्धि पूर्वाग्रह के साथ इनका कारोबार किया गया।

6. घरेलू मोर्चे पर लगातार दूसरे वर्ष दक्षिण-पश्चिमी मानसून के सामान्य और सही वितरण से कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों और ग्रामीण मांग की संभावनाएं उज्ज्वल हुई हैं। 1 अगस्त तक, दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 1 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई और देश के भौगोलिक क्षेत्र के 84 प्रतिशत हिस्से में अधिक से सामान्य बारिश हुई है। खरीफ की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेज गति से हुई है जहां गन्ने, पटसन और सोयाबीन की पूरे मौसम की बुआई पूरी हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में तुर को छोड़कर दलहन और चावल की बुआई के बारे में प्रारंभिक अनिश्चितता भी मुख्य रूप से छितराई हुई है। कपास और मोटे अनाज की बुआई पिछले वर्ष के स्तर से अधिक हुई है किंतु तिलहन की बुआई पिछड़ी हुई है। कुल मिलाकर, इन गतिविधियों से वर्ष 2017-18 के लिए फसल उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष में हासिल शीर्ष स्तर की अपेक्षा उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया है। इसी बीच रबी विपणन मौसम के दौरान

चावल और गेहूं के संबंध में खरीद परिचालन रिकार्ड स्तर तक बढ़ गए हैं जो अप्रैल-जून 2017 में 36.1 मिलियन टन थे और स्टॉक सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बढ़कर बफर मानदंड के 1.5 गुणा हो गए हैं।

7. औद्योगिक कार्यनिष्पादन अप्रैल-मई 2017 में कमजोर रहा है। इससे मुख्य रूप से विनिर्माण में व्यापक आधारित हानि प्रतिलक्षित हुई। कोयला की अधिक इन्वेंटरी और कच्चे तेल तथा रिफाइनरी उत्पादों का लगभग स्थिर आउटपुट ने मिलकर खनन गतिविधि को मंदा कर दिया। विद्युत उत्पादन, मांग में कमी बाध्यकारी प्रतिबंध प्रतीत होता है। उपयोग के मामले में, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन तेज हुआ और ग्रामीण मांग के लचीलेपन को रेखांकित किया। तथापि, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में कमी द्वारा काबू पा लिया गया जो अभी भी सुस्त पड़ी शहरी मांग और आवक पूंजीगत माल की ओर संकेत करता है, और यह अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के निरंतर छूटनी की तरफ इशारा करता है। कैपेक्स चक्र में कमजोरी नई निवेश घोषणाओं में भी देखी गई जहां निवेश घोषणाएं पहली तिमाही में 12 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई, रूकी हुई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पकड़ के अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर माल के आउटपुट में कमी और कॉर्पोरेट क्षेत्र में चालू डिलीवरेजिंग में देखी गई। मुख्य उद्योगों का आउटपुट भी विद्युत, कोयला और उर्वरकों के उत्पादन में कमी के कारण जून में नीचे आ गया जिसका कारण अधिक इन्वेंटरी और धीमी मांग रहा। सकारात्मक पक्ष पर, प्राकृतिक गैस ने लंबी गिरावट के बाद उत्पादन में वृद्धि दर्ज की और इस्पात का उत्पादन मजबूत रहा। रिजर्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 78वें दौर ने दूसरी तिमाही में विभिन्न पैरामीटरों में, विशेषकर क्षमता उपयोग, लाभ मार्जिन और रोजगार में मांग स्थिति के बारे में सकारात्मकता में कमी दिखाई। विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) क्रमिक रूप से जून में चार महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और भावी आउटपुट सूचकांक भी थोड़ा सहज हो गया। जुलाई में, नए आदेशों की कमी और कारोबारी स्थिति में गिरावट के साथ पीएमआई संकुचन जोन में चला गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी की शुरुआत को प्रतिलक्षित करत है, तथापि निर्यात के नए आदेश और भविष्य का आउटपुट सूचकांक दोनों में बढ़ोतरी हुई जो संभावना में आशावाद को प्रतिलक्षित करती है।

8. विनिर्माण के विपरीत, सेवा क्षेत्र की गतिविधि का उच्च आवर्ती वास्तविक सूचकांक पहली तिमाही में मिश्रित तस्वीर की ओर संकेत करता है। परिवहन उप-क्षेत्र में हवाई माल-भाड़े ने क्रमिक और वार्षिक आधार पर मजबूत कार्यनिष्पादन दर्ज किया। भारत मानक (बीएस)-IV उत्सर्जन अनुपालन स्वचालित के जवाब में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री लगातार दो महीने के संकुचन के बाद बढ़ गई। यात्री कारों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में जून में क्षणिक अव्यवस्था रही, हालांकि मोटरसाइकिल बिक्री में लगातार तीसरे महीने में वृद्धि जारी रही जो ग्रामीण मांग की दृढ़ता को दर्शाती है। वाइस और डेटा सेवा के उपभोक्ता आधार में मजबूत और संधारणीय वृद्धि के कारण मई में संचार उप-क्षेत्र में गतिविधि तेज रही। आतिथ्य उप-क्षेत्र को विदेशी पर्यटकों के आगमन और वायु यात्रा ट्रैफिक से मजबूत वृद्धि द्वारा सहायता मिली। अप्रैल-मई में इस्पात उपभोग में अभिवृद्धि पहली तिमाही में निर्माण गतिविधि में बढ़ोतरी का अग्रदूत हो सकती है, किंतु सीमेंट उत्पादन संकुचित मोड में रहा है। सेवा क्षेत्र के लिए पीएमआई बाजार स्थिति में सुधार की संभावनाओं पर मई-जून में विस्तार मोड में बना रहा।

9. जून में, सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष में होने वाले बदलावों से मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति, 2011-12 के आधार पर श्रृंखला में अपनी सबसे कम रीडिंग में पाई गई। यह मुख्य रूप से बड़े अनुकूल प्रभावों का नतीजा था जिसके नष्ट होने की तथा अगस्त से पलटने की उम्मीद है। अप्रैल से महीने के महीने आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वे गर्मियों में उतार-चढ़ाव वाले खासतौर के खाद्य कीमतों वाले के मुकाबले कमजोर थे। अप्रत्यक्ष कर संशोधन में देरी और वस्तुओं में क्लियरेंस बिक्री का वास्तविक साक्ष्य, गति को कम कर सकता था।

10. खाद्य और पेय पदार्थों की कीमत, जो नई सीपीआई श्रृंखला में पहली बार मई 2017 में अपस्फीति में आई, जून में दालों, सब्जियों, मसाले और अंडों की कीमतों में साल दर साल गिरावट दर्ज की गई और ज्यादातर अन्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति कम हो गई। हालांकि, सामान्य मौसमी मूल्य बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, भले ही विलंब से हो, और विशेषकर टमाटर, प्याज और दूध के मामले में।

11. लगातार दूसरे महीने के लिए ईंधन मुद्रास्फीति में गिरावट आई क्योंकि तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिर गईं और कोक, लकड़ी और चिप्स के मामले में कीमतों में बढ़ोतरी हुई। एलपीजी और केरोसीन के प्रशासकीय मूल्य सब्सिडी में अंशकित कमी के साथ वृद्धि के लिए तैयार हैं। हाल की कम मुद्रास्फीति के कारण में घरों में रियायती दिखाई देती है; रिजर्व बैंक के जून 2017 के सर्वेक्षण के दौर में किए गए तीन महीने आगे और एक वर्ष आगे मुद्रास्फीति की उम्मीदें कुछ हद तक कठोर हैं।

12. भोजन और ईंधन को छोड़कर, सीपीआई मुद्रास्फीति जून में लगातार तीसरे महीने के लिए, शिक्षा के संबंध में फीस संशोधन चक्र में देरी, और स्वास्थ्य, कपड़े और जूते के संबंध में भी, के कारण अन्य सभी के साथ मूल्य गति में 4 प्रतिशत की नरमी आई। परिवहन और संचार सेवाओं में मुद्रास्फीति दूरसंचार क्षेत्र में मूल्य-निर्धारण टकराव के कारण दबी हुई थी। उद्योग और खेतों दोनों से संबंधित इनपुट लागत अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर अच्छी नज़र रखे हुए हैं। रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण में किए गए सर्वे और पीएमआई विनिर्माण और सेवाओं में मूल्य निर्धारण शक्ति अभी भी कमजोर है।

13. अधिशेष चलनिधि की स्थिति सिस्टम में बनी हुई है, जो कि सरकार द्वारा बजटीय खर्चों के फ्रंट लोडिंग से विकट हो गई है। मुद्रा प्रचलन में (सीआईसी) वृद्धि की गति में कुछ नरमी भी थी जो कि वर्ष के इस दौरान सामान्य है- 2017-18 के पहले दो महीनों में सीआईसी में ₹1.5 ट्रिलियन की वृद्धि के मुकाबले, यह क्रमशः जून और जुलाई के दौरान ₹436 बिलियन और ₹95 बिलियन थी। सामान्यतः, मुद्रा इन महीनों में बैंकिंग प्रणाली में वापस आती है और इससे सीआईसी में गिरावट परिलक्षित होता है; फलस्वरूप, इस वर्ष सीआईसी में वृद्धि में पुनर्मुद्रीकरण की निरंतर गति और सिस्टम से चलनिधि से संबंधित अवशोषण को दर्शाता है। बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत खजाना बिलों (टीबी) के माध्यम से ₹1 ट्रिलियन की और अब तक इस वित्तीय वर्ष में संचयी आधार पर नकद प्रबंध बिल (सीएमबी) के माध्यम से ₹1.3 ट्रिलियन की अधिशेष चलनिधि को अवशोषित किया गया था। जून और जुलाई में दो मौकों पर

₹100 बिलियन प्रत्येक की खुली बाजार बिक्री के लिए निरंतर अधिशेष शर्तें पूरी तरह से समर्थित हैं। एक समकक्ष राशि की एक और नीलामी की घोषणा की गई है और यह 10 अगस्त 2017 को आयोजित की जाएगी। इन परिचालनों के अलावा, एलएएफ के तहत चलनिधि का सकल औसत अवशोषण जून में ₹3.1 ट्रिलियन और जुलाई में ₹3.0 ट्रिलियन था। इस सक्रिय चलनिधि प्रबंधन के परिणामस्वरूप, भारत औसत कॉल रेट (डब्ल्यूएसीआर) में तेजी आई और जून और जुलाई के दौरान औसतन रेपो रेट से लगभग 17 बीपीएस नीचे पर - मार्च-अप्रैल में 29-32 आधार अंकों (बीपीएस) और मई में 21 बीपीएस से नीचे - एलएएफ कॉरीडोर के भीतर कारोबार किया।

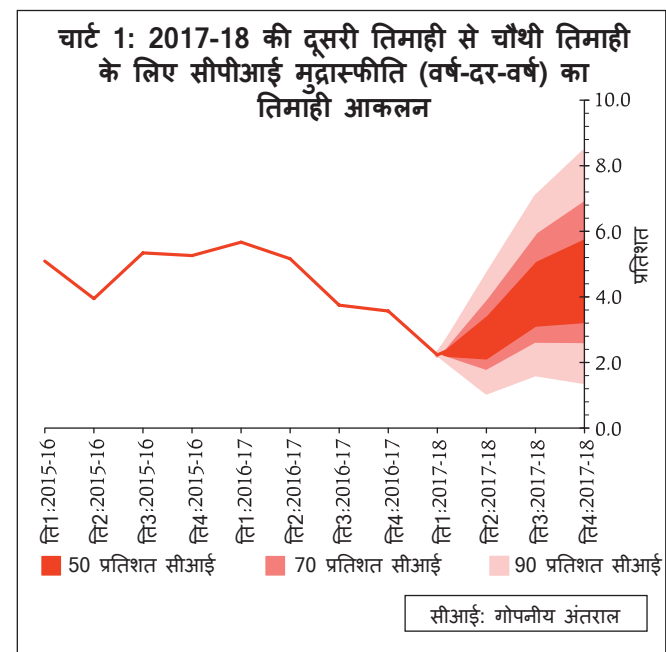
14. बाहरी क्षेत्र की ओर मुड़ते हुए, अप्रैल की उंचाई से व्यापार के निर्यात में मई और जून में गिरावट आई क्योंकि कमोडिटी समूह में शिपमेंट का मूल्य या तो धीमा हुआ या तो उसमें गिरावट आई है। इसके विपरीत, आयात वृद्धि दो अंकों में रही, मुख्य रूप से तेल के आयात में बढ़ोतरी और जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले सोने के आयात के भंडार के कारण थी। कोयला, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोती और कीमती पत्थरों, वनस्पति तेलों और मशीनरी का आयात भी तेज हो गया है। जैसा कि आयात वृद्धि निर्यात के विकास को आगे बढ़ा रही है, पहली तिमाही में व्यापार घाटा 40.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो एक साल पहले के अपने स्तर से दोगुने से अधिक था। अप्रैल-मई 2017 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक साल पहले के अपने स्तर से दोगुना हो गया, विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार और व्यापार सेवाओं में मुख्य रूप से बढ़ रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अब तक घरेलू ऋण और इक्विटी बाजार में 15.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की सकल खरीद (31 जुलाई तक) की है, भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के लिए पर तेजी पर बना हुआ है। 28 जुलाई 2017 को विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर 392.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

ऑउटलुक

15. दूसरे द्वि-मासिक वक्तव्य में अनुमान लगाया गया कि वर्ष की पहली छमाही में तिमाही औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.0-3.5 प्रतिशत की सीमा में और दूसरे छमाही में 3.5-4.5 प्रतिशत की सीमा में रहेगी। पहली तिमाही के वास्तविक परिणामों से अनुमानों का पता लगाया गया। आधार प्रभाव

फीका होने के कारण, मुद्रास्फीति की उभरती हुई गति को निम्न से निर्धारित किया जाएगा (ए) 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत मकान किराया भत्ते (एचआरए) के कार्यान्वयन का सीपीआई पर प्रभाव; (बी) जीएसटी से सामने मूल्य संशोधन के प्रभाव की रोकथाम; और (सी) खाद्य मुद्रास्फीति को आकार देने वाले संरचनात्मक और क्षणभंगुर कारकों का विच्छेदन। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति की गति को अद्यतन किया गया है और केन्द्र द्वारा एचआरए एवॉर्ड के कार्यान्वयन के पहले दौर के प्रभाव को शामिल किया गया है। (चार्ट 1)

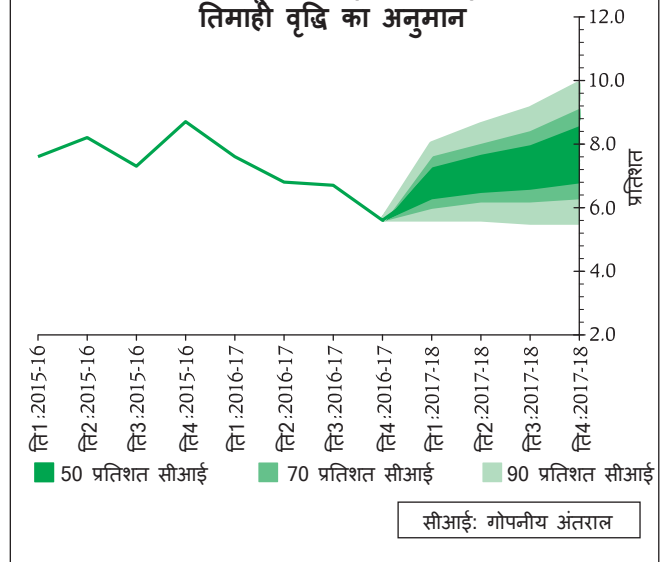
16. इस बेसलाइन मुद्रास्फीति की गति के आसपास अनिश्चितता में योगदान करने वाले कई कारक हैं। राज्यों द्वारा कृषि ऋण छूट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संभावित वित्तीय गिरावट आ सकती है और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को कमजोर कर सकती है, जो कि मुद्रास्फीति के प्रभाव-विस्तार (स्पिलओवर) को अपरिहार्य बनाती है। इसके अलावा, वेतन और भत्ते के अधिनिर्णय के राज्यों के कार्यान्वयन का समय महत्वपूर्ण है - उनकी योजनाओं के बारे में सूचना के अभाव के मद्देनजर आधारभूत प्रक्षेपण में यह फैक्टर नहीं है। यदि राज्य चालू वित्त वर्ष में केंद्र की तरह वेतन और भत्ता बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो प्रमुख मुद्रास्फीति 18-24 महीनों में आधार रेखा से अनुमानतः



अतिरिक्त 100 आधार अंकों से अधिक बढ़ सकती है। इसके अलावा, उच्च आवृत्ति संकेतक संकेत देते हैं कि निकटतम महीनों में सब्जियों और पशु प्रोटीन में मूल्य दबाव बढ़ रहे हैं। हालांकि, कुछ सुधारात्मक बल भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले, लगातार दूसरा सामान्य मॉनसून प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन उपायों के साथ मिलकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकता है। दूसरा, अगर सीपीआई में खाद्य और ईंधन को छोड़कर कीमतों में सामान्य बढ़ोतरी जारी रहती है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति पर अच्छा दबाव बढ़ जाएगा। तीसरा, वर्तमान समय पर अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मूल्य दृष्टिकोण काफी स्थिर है।

17. विनिर्माण क्षेत्र में पाया जाने वाला कारोबारी माहौल 2017-18 की दूसरी तिमाही में पूर्ववर्ती तिमाही से गतिविधि में सुधार की अपेक्षाओं को दर्शाता है। इसके अलावा, बैंकों और निगमों के दोहरे तुलनपत्रों में उच्च स्तर के तनाव नए निवेश को रोक सकते हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियामक छत्र के तहत आने के साथ, नई परियोजना की शुरुआत में निर्माण-पूर्व अवधि विस्तारित हो सकती है और साथ ही इस क्षेत्र में अनुमानित समेकन के साथ निर्माण और सहायक गतिविधियों के लिए प्रभाव-विस्तार के साथ विकास की रोकथाम संभव है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा बाजार उधार और करों को बढ़ाने पर सीमा लगाने से, पहले से अवमन्दित पूंजीगत चक्र के प्रतिकूल प्रभाव के साथ, कृषि ऋण छूट से पूंजीगत व्यय पर ठोस कटौती की संभावना है। साथ ही, एक अन्य अच्छी खरीफ की फसल की बढ़ती संभावना, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए उच्च बजटीय आवंटन से ग्रामीण मांग में वृद्धि, सड़कों और पुलों के लिए बजटीय आवंटन में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम और जीएसटी के विकास बढ़ानेवाले प्रभाव, जैसेकि व्यापार का असंगठित से संगठित खण्ड में अंतरण; टैक्स कैसकेड की कमी; लागत, क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ; और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग आधारभूत अनुमान के लिए अच्छे पहलुओं का निर्माण कर रहे हैं। बदले में, ये अच्छे बल निवेश को प्रेरित कर सकते हैं। बाहरी मांग की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और उससे घरेलू अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलना चाहिए, हालांकि वैश्विक राजनीतिक जोखिम भी महत्वपूर्ण हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2017-

चार्ट 2: 2017-18 की पहली तिमाही से चौथी तिमाही के लिए बेसिक मूल्य पर (वर्ष-दर-वर्ष) जीवीए में तिमाही वृद्धि का अनुमान



18 के लिए वास्तविक जीवीए वृद्धि का अनुमान समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ जून 2017 में 7.3 प्रतिशत के रूप में प्रक्षेपित किया गया है।

18. एमपीसी ने पाया है कि जबकि मुद्रास्फीति एक ऐतिहासिक स्तर तक कम हो गई है, अवस्फीतिकारक विस्थापन और संरचनात्मक कारकों का निर्णायक पृथक्करण अभी भी पकड़ में नहीं आया है। मुद्रास्फीति-संवेदनशील सब्जियों के संबंध में कीमतें स्पाइक रिकॉर्ड कर रही हैं। अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति दालों और अनाज की कीमतों को निरंतर रूपसे नियंत्रित कर रही है। एमपीसी मुद्रास्फीति की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखेगी कि हाल ही के नरम आंकड़ें क्षणिक हैं या अधिक टिकाऊ अवस्फीति जारी है। वास्तविक गतिविधि के अपने मूल्यांकन में, एमपीसी ने उल्लेख किया कि जब कृषि के लिए दृष्टिकोण मजबूत दिखता है, उद्योग और सेवाओं में अंतर्निहित विकास आवेगों को कॉर्पोरेट डिलीवरेजिंग और निवेश की मांग के कमी कमजोर कर रहे हैं।

19. एमपीसी ने कहा कि मुद्रास्फीति के कुछ उर्ध्वगामी जोखिमों या तो कम हुए हैं या प्रभावहीन हो गए हैं - (i) एचआरए प्रभाव को छोड़कर प्रमुख मुद्रास्फीति का आधारभूत मार्ग जून में किए गए अनुमान के मुकाबले कम रहते हुए 4थी

तिमाही में 4 प्रतिशत से कुछ अधिक रहा है ; (ii) खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में पिछले तीन महीनों में काफी गिरावट आई है; और, (iii) जीएसटी का रोल-आउट सुचारू रहा है और मानसून सामान्य है। नतीजतन, आउटपुट अंतर की गतिशीलता को देखते हुए मौद्रिक नीति आवास के लिए कुछ स्थान बन गया है। तदनुसार, एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह ध्यान रखते हुए कि बेसलाइन प्रक्षेपण में मुद्रास्फीति की गति मौजूदा कम स्तर से बढ़ने की उम्मीद है, एमपीसी ने नीति के रुख को तटस्थ रखने और आने वाले आंकड़ों को देखने का फैसला किया है। एमपीसी टिकाऊ आधार पर प्रमुख मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के करीब रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर केंद्रित है।

20. अर्थव्यवस्था की स्थिति पर, एमपीसी का मानना है कि निजी निवेश को पुनर्जीवित करने, बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने और सभी की आवास आवश्यकताओं के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना को मुख्यतः बल देने

की आवश्यकता है। यह राज्यों द्वारा परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी पर निर्भर करता है। अपनी ओर से, सरकार और रिजर्व बैंक बड़े तनावग्रस्त कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के हल के लिए और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए निकट समन्वय में काम कर रहे हैं। इन प्रयासों से उत्पादकता के क्षेत्रों में क्रेडिट प्रवाह की पुनः शुरुआत करने में मदद मिलनी चाहिए क्योंकि मांग में तेजी आई है।

21. डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पमी दुआ, डॉ. विरल वी. आचार्य और डॉ. उर्जित आर.पटेल मौद्रिक नीति के फैसले के पक्ष में थे, जबकि डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने नीति दर में 50 आधार अंकों की कमी के लिए मतदान किया और डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा ने यथास्थिति के लिए मतदान किया। एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त अगस्त 16, 2017 तक प्रकाशित किया जाएगा।

22. एमपीसी की अगली बैठक 3 और 4 अक्टूबर 2017 को तय की गई है।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य, भारतीय रिज़र्व बैंक

1. मौद्रिक नीति अंतर में सुधार करने के लिए उपाय

मौद्रिक अंतरण में सुधार करने के लिए अप्रैल 2016 में शुरू की गई सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) का अनुभव पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा है, हालांकि यह आधार दर प्रणाली की तुलना में प्रगति है। मौद्रिक अंतरण में सुधार करने के दृष्टिकोण और बैंक उधार दरों को सीधे बाजार निर्धारित बेंचमार्क से जोड़ने के तरीकों को खोजने के लिए एमसीएलआर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक आंतरिक अध्ययन समूह गठित किया गया है। यह समूह 24 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इसके अतिरिक्त, एमसीएलआर की शुरुआत के बाद कुछ बैंकों द्वारा आधार दर की तीव्र संवीक्षा सुझाती है कि यह एमसीएलआर की अपेक्षा काफी कम बढ़ी है। जबकि आधार दर में बदलाव की सीमा से जरूरी नहीं है कि एमसीएलआर में संशोधन नहीं दर्शाता है, आधार दर की कठोरता वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के सक्षम अंतरण के लिए चिंता का विषय है। बैंकों के अस्थिर दर ऋण पोर्टफोलियो के बड़े भाग को देखते हुए जो अभी भी आधार दर पर संचालित है, भारतीय रिज़र्व बैंक निकट भविष्य में विभिन्न विकल्पों की तलाश करेगा जिससे कि आधार दर को बैंकों की निधि लागत में बदलावों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके।

2. एलसीआर दिशानिर्देशों में संशोधन

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, नकदी जिसमें अपेक्षित न्यूनतम सीआरआर से अधिक प्रारक्षित नकदी शामिल है, उसे स्तर 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में मान्यताप्राप्त है। तथापि, अन्य केंद्रीय बैंकों के पास धारित आवश्यकता से अधिक प्रारक्षित निधियों को स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं है।

अनुदेशों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी केंद्रीय बैंक में धारित प्रारक्षित निधियां जो मेजबान देश की प्रारक्षित निधियों

की आवश्यकता से अधिक हैं को कतिपय शर्तों के अधीन एचक्यूएलए माना जाना चाहिए।

परिपत्र आज जारी किया जा रहा है।

3. भारत के लिए सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्च स्तरीय कार्यदल

उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के बीच सूचना विषमता का समाधान करने और क्रेडिट बाजार को अधिक सक्षम बनाने के लिए सामान्य रूप से केंद्रीय बैंक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा परिचालित निजी क्रेडिट ब्यूरो और सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) अधिकांश देशों में एक साथ कार्य करते हैं। भारत में आज की तारीख में चार क्रेडिट ब्यूरो या क्रेडिट सूचना कंपनी (अर्थात् सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और सीआरआईएफ हाईमार्क) चालू हैं जिन्हें क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए 2005) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अंदर बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी) बनाई गई है जो बड़े एक्सपोजरों को ट्रैक करके पर्यवेक्षी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। भारतीय रिज़र्व बैंक में व्यापक मूलभूत सांख्यिकी रिटर्न (बीएसआर-1) डेटाबेस है जो क्रेडिट पर लेखा स्तर की सूक्ष्म से सूक्ष्म सूचना रखता है।

एक पीसीआर संभावित रूप से बैंकों को क्रेडिट मूल्यांकन और क्रेडिट मूल्य निर्धारण के साथ ही जोखिम आधारित, गतिशील और काउंटरसाइकल प्रावधान करने में मदद कर सकता है। पीसीआर, आरबीआई को यह जानने में मदद कर सकता है कि मौद्रिक नीति संचरण काम कर रहा है या नहीं और यदि नहीं, तो बाधाएं कहां हैं। इसके अलावा, यह पर्यवेक्षकों, नियामकों और बैंकों को शुरुआती हस्तक्षेप द्वारा तनावग्रस्त बैंक क्रेडिट के प्रभावी पुनर्गठन में मदद कर सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, विशेषज्ञों और साथ ही प्रमुख हितधारकों के एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन करने का निर्णय लिया गया है जो (i) भारत में क्रेडिट के बारे में उपलब्ध वर्तमान जानकारी की समीक्षा करेगा; (ii) अंतराल का मूल्यांकन करेगा जिसे व्यापक पीसीआर से भरा जा सकता है; (iii) अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करेगा; और, (iv) भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक और निकट-तत्काल समय पीसीआर विकसित करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित एक रोडमैप का सुझाव देगा।

4. ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा व्यापक ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) जारी किया जाना

यह देखा गया है कि ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) क्रेडिट इंस्टीट्यूशन (सीआई) को वाणिज्यिक डेटा, उपभोक्ता डेटा या एमएफआई डेटा जैसे विशिष्ट मॉड्यूलों में उपलब्ध क्रेडिट जानकारी के आधार पर ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) के सीमित संस्करण देने की प्रथा का पालन कर रहे हैं।

क्रेडिट संस्थानों द्वारा कुशल ऋण मूल्यांकन की सुविधा के लिए और उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सूचना असमानता को कम करने के लिए, सीआईसी को क्रेडिट इंस्टीट्यूशन (सीआई) में प्रस्तुत सीआईआर में सीआईसी डेटाबेस में सभी मॉड्यूलों में उपलब्ध सभी क्रेडिट जानकारी को शामिल करने का निदेश देने का निर्णय लिया गया है।

परिपत्र आज जारी किया जा रहा है।

5. रिज़र्व बैंक के पारिवारिक सर्वेक्षण

आरबीआई नियमित रूप से मौद्रिक नीति के लिए कई सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षणों पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) जिसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों के सदस्यों होते हैं, इन सर्वेक्षणों का संचालन करने के लिए आरबीआई का मार्गदर्शन करती है। जबकि पारिवारिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का सर्वेक्षण (आईईएसएच) 18 शहरों में आयोजित किया जाता है जिसमें 5,500 परिवारों को कवर किया जाता है, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) 6 शहरों में आयोजित किया जाता है जिसमें करीब 5,400 परिवारों को कवर किया जाता है। उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता में सुधार के लिए, टीएसीएस की सिफारिशों के मुताबिक, आईईएसएच के कवरेज का विस्तार ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और, सीसीएस के मामले में, कवरेज 6 शहरों से बढ़ाकर 13 शहरों तक कर दिया जाएगा।

6. त्रिपक्षीय रिपो

त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत से कॉर्पोरेट बांड रेपो बाजार में बेहतर तरलता के लिए योगदान मिलेगा, जिससे बाजार

को सरकारी प्रतिभूति रेपो के लिए एक वैकल्पिक रेपो साधन उपलब्ध कराया जाएगा। 11 अप्रैल 2017 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर त्रिपक्षीय रेपो की शुरुआत के बारे में ड्राफ्ट दिशानिर्देश दिए गए थे। प्रतिक्रिया की जांच की गई है और इसके बारे में अंतिम परिपत्र अगस्त 2017 के मध्य में जारी किया जाएगा।

7. सरलीकृत हेजिंग सुविधा

सरल हेजिंग सुविधा की योजना को पहली बार आरबीआई ने अगस्त 2016 में घोषित किया था और प्रारूप योजना 12 अप्रैल 2017 को जारी की गई थी। इस योजना का उद्देश्य हेजिंग विनिमय दर की प्रक्रिया को दस्तावेजों की आवश्यकताओं को कम करके और उत्पादों, उद्देश्य और हेजिंग लचीलेपन के बारे में अनुशासनिक शर्तों से बचने को सरल बनाने का है। इससे अधिक गतिशील और कुशल हेजिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस योजना को लागू करने के लिए परिपत्र को अंतिम रूप दिया गया है और सरकार द्वारा फेमा अधिसूचना जारी करने के बाद जारी किया जाएगा।

8. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स (आईएफआर) की अलग सीमा

वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एफपीआई सीमा प्रतिभूतियों में निवेश और बॉन्ड फ्यूचर्स में निवेश के बीच प्रतिस्थापित है। आगे बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब सरकारी प्रतिभूतियों पर एफपीआई सीमाएं नीलामी के अधीन हैं उस दौरान एफपीआई के फ्यूचर्स तक पहुंच निरंतर बनी रहती है, आईआरएफ में बिक्री से अधिक खरीद के लिए एफपीआई को अलग से ₹5000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश के लिए निर्धारित सीमाएं ऐसी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपलब्ध होगी। हेजिंग प्रयोजनों के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स की एफपीआई की पहुंच पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार के साथ परामर्श के बाद इस संबंध में आरबीआई द्वारा परिपत्र जारी किया जाएगा।

भाषण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - वर्तमान स्थिति,
समस्याएं और आगे की कार्ययोजना
एस.एस. मूंदड़ा
भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री
विरल वी. आचार्य

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - वर्तमान स्थिति, समस्याएं और आगे की कार्ययोजना*

एस.एस. मूंदड़ा

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) के मेरे साथियों, यहाँ एकत्रित हुए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी कारोबार के प्रभारी अधिकारीगण और रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के मेरे सहयोगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमसे जुड़े हैं- सभी को सुप्रभात ! प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) के प्रवाह के संबंध में सीएबी द्वारा इस सेमिनार का आयोजन बहुत ही उपयुक्त समय पर किया जा रहा है। इस प्रकार के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एक प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जहाँ विचारों का आदान-प्रदान होता है और फीडबैक मिलता है जो नीति निर्धारण के लिए इनपुट का कार्य करता है। मेरा मानना है कि सबसे अलग-थलग रहते हुए तैयार की गयी नीतियाँ कागज़ पर तो अच्छी लग सकती हैं, परंतु वास्तविक कार्यान्वयन के समय ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अधिक सक्षम नहीं रहेंगी।

भूमिका

2. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने के पीछे निहित सोच यह है कि समाज के उन तबकों को मजबूत बनाया जाए जिन्हें ऋण के लिए पात्र होने के बावजूद औपचारिक व्यवस्था के तहत समय पर ऋण-सुविधा नहीं मिल पाती या पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कुछ क्षेत्रों/ उधारकर्ताओं को पर्याप्त ऋण न मिलने के कई कारण हैं। किसी समय विशेष पर संस्थानों के पास उधार देने के लिए संसाधन सीमित होते हैं और ऐसे में, इस बात में तालमेल बिठाने की कशमकश चलती रहती है कि कितना समय और श्रम लगाना उचित है और नये कारोबार से किस प्रकार की टॉपलाइन या बॉटमलाइन पैदा होगी। यदि कारोबार इस तरह से चलेगा तो इस बात की संभावनाएं तो रहेंगी ही कि जिन

क्षेत्रों को क्रेडिट की वास्तव में आवश्यकता है, वे इससे वंचित रह जाएं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के लिए बनाए गए मानदण्डों की मूल प्रेरणा यहीं से मिली है। अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के मद्देनज़र इन दिशानिर्देशों में भी समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार : एक कारोबारी अवसर

3. मूल विषय पर आने से पहले मैं कुछ नीतिगत और कारोबारी योजना से जुड़ी बातें करना चाहूंगा। पीएसएल दिशानिर्देशों को लागू हुए एक लंबा अरसा गुज़र चुका है- लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके तहत उप लक्ष्य बने हैं लेकिन दुःख की बात यह है कि प्रायः इन मानदण्डों को केवल अनुपालन के नज़रिए से देखा जाता है। यहाँ उपस्थित बैंकों के पीएसएल प्रमुखों से जो सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि वे अपने वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र और बोर्ड के निदेशकों तक यह संदेश पहुंचाएं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना एक अच्छा कारोबार है और इसके उचित और तर्कसंगत कारण मौजूद हैं। इसके पक्ष में आपके द्वारा दिए जाने वाले तर्क पहले की तुलना में अब शायद ज्यादा विश्वसनीय लगेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि बैंकों ने बड़े कॉर्पोरेट्स को आवश्यकता से अधिक ऋण दिया और उसके परिणाम सबके सामने हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण देना उस दृष्टिकोण का परिचायक है जिसे मेरे विचार से 'न्यूनतम इनपुट और अधिकतम आउटपुट' वाला नज़रिया कहा जा सकता है। बहुत थोड़े से प्रयास से अत्यधिक बड़ा ऋण संविभाग तैयार हो जाता है जबकि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में उतने ही बड़े ऋण के लिए बड़ी संख्या में बैंक स्टाफ और परिचालन से जुड़े अन्य लोगों को मेहनत से काम करना पड़ता।

4. अब छोटे-छोटे ऋणों पर ध्यान केंद्रित करना और अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह है विनियामकीय पक्ष। हाल के दिनों में कुछ ध्यान देने योग्य परिवर्तन देखने को मिले हैं (क) एकल और सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण की सीमा में संशोधन हुआ है; और (ख) किसी भी इकाई का पूरी बैंकिंग प्रणाली में कितना ऋण जोखिम को एक निर्धारित सीमा के भीतर रखना अनिवार्य बना दिया गया है। इन परिवर्तनों के बाद कॉर्पोरेट्स की यह मजबूरी होगी कि वे अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए धीरे-धीरे बाजार का रुख करें। बीते समय के कड़वे अनुभवों और जोखिम विशाखन की आवश्यकता को छोड़ दें तो भी

* कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 27 जून 2017 को 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण का प्रवाह - नीति और उसका कार्यान्वयन' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में निहित आय-अर्जन की संभाव्यता एक और कारण है जो बैंकों को बेहतर कारोबारी संभावनाओं की तलाश में अन्यत्र देखने पर बाध्य कर रही है। इतना ही नहीं, हम यह देख रहे हैं कि बैंकों ने कॉर्पोरेट से रिटेल संविभाग की ओर रुख करने की नीति अपना ली है। मैं यह नहीं कहता कि 'रिटेल' की ओर बढ़ने की नीति सही नहीं है, लेकिन यदि समग्र आर्थिक और ऋण परिदृश्य की बात की जाए तो 'रिटेल' ऋण का उपयोग उधारकर्ताओं द्वारा प्रायः ऐसे कार्यों में किया जाता है जिनसे न तो कोई आय अर्जित होती है और न ही किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं दूसरी ओर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋण आर्थिक गतिविधियों में मददगार साबित होते हैं, आय के स्रोत बनते हैं और इनसे लाभ भी कमाया जाता है। इस प्रकार के उधारकर्ता बाद में 'रिटेल ऋण' के लिए पात्र ग्राहक बनते हैं। यही कारोबारी संभावनाओं की तलाश में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की ओर बढ़ने के पीछे निहित सोच है और कारण भी।

क्या कोई वास्तविक प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल है?

5. मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो कि सरकारी बैंकों के लिए और कुछ हद तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शायद कुछेक निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी अधिक प्रासंगिक है। यह प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल के कामकाज के तरीकों से संबंधित है। सभी सरकारी बैंकों में प्राथमिकता क्षेत्र की जिम्मेदारी विभिन्न वर्टिकल्स में बांट देने की प्रथा है। ग्रामीण ऋण अथवा कृषि वित्त वर्टिकल बना हुआ है, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक अलग से वर्टिकल है, किफायती आवास संविभाग हो सकता है रिटेल का ही एक भाग हो और पिछले संशोधन के तहत प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल नवीकरणीय ऊर्जा और मझोले उद्योग जैसे क्षेत्रों को ज्यादा संभावना है कि मिड कॉर्पोरेट अथवा बड़े क्रेडिट या कॉर्पोरेट समूह में रखा गया हो। हो सकता है कि इनसे भिन्न एक वित्तीय समावेशन वर्टिकल भी बना हो। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु कोई समग्र कार्यनीति तैयार करने के उद्देश्य से इन अलग-अलग वर्टिकलों के बीच समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयास किया भी जाता है या नहीं - मुझे नहीं पता। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल एक आंकड़ा संग्रहण और विवरण तैयार करने वाले वर्टिकल में तब्दील होकर रह गया है। इसके अलावा, ऐसे कितने बैंक हैं जो अपने बोर्ड की बैठकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कार्यनीति पर चर्चा करते हैं।

6. यह आवश्यक है कि ये सभी वर्टिकल स्वयं को थोड़ा विस्तार दें और पारस्परिक सामंजस्य से सामूहिक रूप से एक कार्ययोजना तैयार करें और फिर इस कार्ययोजना को व्यापक चर्चा और मार्गदर्शन हेतु बोर्ड के समक्ष रखें। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ आंकड़ा संग्रहण की कवायद मात्र बन कर न रह जाएं।

राज्य-स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) द्वारा अनुमोदित योजना और प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में किसी प्रकार का संबंध होता है?

7. बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र गतिविधियों से बहुत सी एजेंसियाँ जुड़ी रहती हैं। एसएलबीसी का गठन किया गया है जहाँ जिला स्तरीय ऋण योजना (डीसीपी) तैयार की जाती है और जिला स्तर पर अग्रणी बैंक कार्यालय कार्य करते हैं। नाबाई क्षमता आधारित ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है। एसएलबीसी इसे अपनाती है और फिर इसे सभी बैंकों में बांटा जाता है। मुझे इस बात में संदेह है कि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए बनी समग्र कार्यनीति और एसएलबीसी और डीसीपी द्वारा किए जा रहे कार्य में कोई तार्किक संबंध होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक एसएलबीसी के ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तन के बारे में सोच रहा है जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कुछ में बदलाव आएगा।

आंकड़े जुटाना और प्राथमिकता क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ

8. वर्तमान में हम भारतीय रिज़र्व बैंक के भीतर ही एक परियोजना पर काम कर रहे हैं जिससे कोर बैंकिंग समाधानों (सीबीएस) के जरिये ही आंकड़े जुटाने का कार्य किया जा सकेगा। ऋण आयोजना की समग्र प्रक्रिया में आंकड़ों की अविश्वसनीयता एक बड़ा मुद्दा है और किन्हीं अर्थों में यह एक ऐसी बाधा बना हुआ है जिसके कारण बैंक सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते और सही नीतियाँ नहीं बना पाते। इस परियोजना का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन यह जरूरी है कि लागू होने के बाद यह भी आँकड़ेबाजी और अनुपालन की औपचारिकता पूरी करने के एक माध्यम के रूप में न देखा जाए। यह बैंकों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है क्योंकि वे इसमें उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे, विश्लेषण की तकनीकों के जरिए उनकी व्याख्या कर सकेंगे और सही कार्यनीति तैयार कर सकेंगे। ठोस आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर उनके लिए प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों की पहचान करना आसान हो जाएगा। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठ तंत्र में कार्यरत लोग इस कार्य को उसकी सही भावना के अनुरूप लेते हुए सराहें।

अनुसंधान

9. व्यापक नीति और कार्ययोजना तैयार करने के पहलू पर एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि बैंक निजी तौर पर भी अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ निवेश करें- मैं बहुत गहन अकादमिक अनुसंधान की बात नहीं कर रहा बल्कि ऐसा अनुसंधान जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीतियां बनाने और कारोबारी योजनाएं तैयार करने में सहायक हो।

10. अब मैं प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में हाल के समय में हुए कुछ बदलावों और इस क्षेत्र में उभरती कारोबारी संभावनाओं के बारे में बात करना चाहूंगा।

विविधताओं से भरा क्षेत्र

11. पिछले संशोधन में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का काफी विस्तार कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, मँझोले उद्यम, एगो-प्रोसेसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई नये क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इस प्रकार कई नई गतिविधियों को भी इसके तहत अनुमति दी गयी है, लेकिन साथ-ही-साथ इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस विशाल कैनवस के भीतर छोटे और सीमांत किसान तथा सूक्ष्म उद्यमों को नुकसान न पहुंचे, इनके लिए कुछ उप-सीमाएं भी तय की गयी हैं। इस प्रकार के संशोधन करने से और ऐसा ढाँचा तैयार करने से आप में से हर किसी को इस बात की आजादी मिलती है कि आप अपने मजबूत पक्ष की पहचान कर सकें और उस क्षेत्र में अपना अधिकतम प्रयास कर सकें। इस प्रकार से आप अधिशेष उत्पन्न कर सकेंगे और उसे प्राथमिकता क्षेत्र उधार बाजार (पीएसएलसी) में उसके जरिए उन क्षेत्रों के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं जिनमें दूसरों ने अधिशेष उत्पन्न किया है। पीएसएलसी का पूरा कारोबार इसी सिद्धांत पर चलेगा। मैं पीएसएलसी बाजार में हाल के दिनों में हुए परिवर्तनों की बात थोड़ी देर बाद करना चाहूंगा।

रोजगार सृजन, स्वरोजगार की क्षमता और प्राथमिकता क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ

12. इस क्षेत्र में अवसर काफी कम हैं। एक अवसर तो जनांकिकीय परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता दिखता है। नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में युवाओं के इस प्रणाली में शामिल हो रहे हैं। यह उम्मीद करना कि इनमें से हर किसी को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिल जाएगा, वास्तविकता से परे होगा। उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो विनिर्माण, सेवा क्षेत्र की छोटी-छोटी गतिविधियों में लगे होंगे या छोटे उद्यम चलाते

हुए लाभ कमा रहे होंगे। इस प्रकार स्वरोजगार की क्षमता वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी होगी। इसके मायने हुए कि बैंकों के लिए कारोबार के अच्छे अवसर बनेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई अभिनव योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदि इस पारिस्थितिकी को प्रोत्साहित कर रही हैं। लेकिन जब तक इस दिशा में अनुसंधान नहीं किया जाता, प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता और तदनुसार नीति और कार्ययोजना नहीं तैयार की जाती, तब तक इस अवसर का पूरा लाभ लेना संभव नहीं है।

शहरीकरण की तेज रफ्तार और प्राथमिकता क्षेत्र पर इसका असर

13. व्यापक स्तर पर प्रभावित करने वाली एक अन्य घटना जिसकी रफ्तार निकट भविष्य में और बढ़ने वाली है, वह है तीव्र शहरीकरण। वर्तमान में देश की लगभग 32 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आगामी 10-15 वर्षों में यह आंकड़ा 42 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस घटना के मद्देनजर एक बार पुनः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विभिन्न वर्टिकलों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए और पूरे बैंक को इस संबंध में एक सामूहिक कार्यनीति बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, गाँवों से शहरों में आकर शिफ्ट हो रहे लोग हो सकता है कि बैंक की ग्रामीण शाखा के ग्राहक रहे हों। परंतु जब वे शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं तो क्या बैंकों के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे उनकी ग्रामीण शाखाएं शहरी या अर्धशहरी शाखाओं को यह जानकारी दे सकें कि ये ग्राहक किस स्थान के लिए पलायन कर रहे हैं। सूचना के इस नेटवर्क का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है क्योंकि जब लोग नई जगह पर आकर बसते हैं तो उनकी नई-नई ज़रूरतें होती हैं और यह भी संभव है कि वे कोई नया कारोबार शुरू करें जिसके लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता हो। इसीलिए मेरा यह मशविरा है कि इस समन्वित दृष्टिकोण को बैंक अपनी कारोबारी नीति का अभिन्न अंग बनाएं। पलायन कर रही इस बड़ी जनसंख्या में निहित कारोबारी संभावनाओं के दोहन के लिए उन्हें समुचित संचार माध्यम विकसित करने ही होंगे।

वित्तीय समावेशन (एफ आई) क्या प्राथमिकता क्षेत्र का ही एक हिस्सा है ?

14. जैसा कि मैं कह चुका हूँ, कई बैंकों में वित्तीय समावेशन एक अलग वर्टिकल है। ऐसी स्थिति में आपसी समन्वय का अभाव होगा ही। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित

बात आपसे कहना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप जब इस सम्मेलन से वापस जाएं तो इस बात पर चिंतन-मनन करें। हम एक विशेष प्रकार के संगठनात्मक ढाँचे में कार्य करने के आदी हो जाते हैं जहाँ हम एकाकी रूप से अपने काम में लगे रहते हैं। हमारे दिमाग में यह बात शायद आती ही नहीं कि संगठन की विभिन्न गतिविधियों के बीच एक समन्वय होना चाहिए जिससे एक बेहतर नया ढाँचा खड़ा हो सके। मेरा यह सुझाव है कि यदि आपके बैंक में वित्तीय समावेशन एक अलग वर्टिकल हो तो उसे प्राथमिकता क्षेत्र में ही शामिल कर लें।

प्रौद्योगिकी के सहारे कम लागत पर ऋण वितरण

15. अंततः आपको यह ध्यान में रखना है कि छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्यम, किफायती आवास मिलकर प्राथमिकता क्षेत्र का आधा या आधे से भी अधिक हिस्सा बनाते हैं। फिर भी, यदि इस हिस्से के तहत दी जा रही सेवा को लाभप्रद बनाना है तो ऐसा केवल तभी संभव है जब प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उनका ऋण वितरण मॉडल कम लागत वाला हो। कुछ सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने प्रौद्योगिकी आधारित कम लागत वाले ऋण वितरण मॉडल विकसित किए हैं और काफी अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं।

वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडलों का उपयोग

16. अगर आप माइक्रो उद्यम आदि वाले ऋण संविभाग को सामान्य क्रेडिट रेटिंग / स्कोरिंग मॉडल में फिट करने का प्रयास करेंगे तो वह उचित नहीं। अगर आप उनको कर्ज-इक्विटी अनुपात, कर्ज सेवा कवरेज अनुपात आदि जैसे सामान्य मानदण्डों पर आंकने का प्रयास करेंगे तो यह गलत प्रयास साबित होगा। अतः आपको क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमारी वित्तीय प्रणाली में इस संबंध में काफी प्रयास किए गए हैं और बहुत से ऋणदाता अब ऐसे क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का उपयोग करने लगे हैं जिसमें भुगतान का इतिहास, धन-प्रेषण का इतिहास, बिल भुगतान का इतिहास आदि जैसी बातों से संबंधित आंकड़े भी इकट्ठा किए जाते हैं ताकि उधारकर्ताओं की ऋण चुकौती क्षमता का विश्लेषण किया जा सके। आजकल इस प्रकार के आंकड़े किसी न किसी प्रकार उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ बैंकों ने छोटे उधारकर्ताओं को देय ऋण-राशि की सीमा के अग्रिम अनुमोदन हेतु इनका इस्तेमाल किया है। ऐसा वे पहले से ही करके रखते हैं और ऋण के लिए उधारकर्ताओं को बैंक के पास आने की

आवश्यकता नहीं होती बल्कि बैंक खुद ही उनसे संपर्क करते हैं। हम बड़ी-बड़ी ऋणराशियाँ कॉर्पोरेटों को देते रहे हैं, परंतु अब समय आ गया है कि हम छोटे उधारकर्ताओं और आम आदमी को ऋण मुहैया कराएं।

17. प्राथमिकता क्षेत्र में व्यवसाय करने से जुड़े ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें मैं आपसे शेर करना चाह रहा था। हमें इस क्षेत्र में उभरती संभावनाओं के प्रति सचेत रहना है और इन संभावनाओं का लाभ लेते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण कारोबार को सफल बनाना है।

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कार्यनिष्पादन

18. अब मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के प्रवाह से संबंधित कुछ मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा। जब मैं वर्ष 2016-17 के लिए अभी हाल ही में लाए गए उप-लक्ष्यों के तहत किए गए कारोबार को देखता हूँ, तो मुझे कुछ रोचक रुझान देखने को मिलते हैं, हालांकि आंकड़े अभी अनंतिम हैं। प्राथमिकता क्षेत्र को समग्र उधार हेतु निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से सरकारी और निजी - दोनों क्षेत्रों के बैंकों ने अच्छा कारोबार किया है। सरकारी क्षेत्र का सामूहिक कारोबार 40% के लक्ष्य से थोड़ा ही नीचे रहा जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने 40% से काफी अधिक कारोबार किया है। ऐसे विदेशी बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं वे भी अपनी निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार चल रहे हैं क्योंकि उनसे भी यह अपेक्षित है कि वे भी धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जिन विदेशी बैंकों की 20 से कम शाखाएं हैं, वे भी वर्तमान में सही दिशा में बढ़ते लग रहे हैं।

19. छोटे और सीमांत कृषकों के मामले में सरकारी बैंकों ने निर्धारित उप सीमा से थोड़ा अधिक कारोबार किया जबकि निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्य से पीछे रहे और उनका कार्यनिष्पादन 2015-16 के दौरान लगभग 5% रहा। वर्ष 2016-17 में भी इसमें अधिक सुधार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में सरकारी बैंक उप लक्ष्य हासिल नहीं कर सके जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक कारोबार (8% से अधिक) किया। इसमें एक अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण तथ्य छिपा है कि यद्यपि निजी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क बना लिया है, और जहाँ नहीं है, वहाँ उनका हब एण्ड स्पोक मॉडल काम कर रहा है, तथापि, अभी भी उनका ध्यान मुख्य रूप से शहरी जनसंख्या पर ही है। बैंक किन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करें इस क्षेत्र में कार्ययोजना बनाने का कार्य मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ, तथापि हमें सावधान

रहना होगा कि किसी संविभाग विशेष में यदि समग्र घाटे की स्थिति बनी रहती है तो पीएसएल सार्टिफिकेटों की आपूर्ति रोकੀ भी जा सकती है। शायद एक अच्छी कारोबारी योजना यह होगी कि घाटे को बड़े प्रतिशत में नहीं बल्कि कम से कम स्तर पर छोड़ा जाए अन्यथा बाद में यह बहुत महंगा साबित हो सकता है।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार में प्रोत्साहक तत्त्व

20. अब मैं आपसे कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करना चाहूंगा जो ऋण प्रवाह, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह, में तेजी लाने के लिए किए गए हैं क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि रोजगार के अवसर पैदा करने में निर्णायक भूमिका निभाता है और सभी के लिए रोजगार आज की प्रमुख आवश्यकता के साथ-साथ राष्ट्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

क) एमएसएमई क्षेत्र

(i) फैक्ट्रिंग लेन-देन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा 'विद रिकोर्स' आधार पर किए जाने वाले फैक्ट्रिंग लेनदेन को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने की अनुमति दी थी ताकि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक से अधिक चलनिधि उपलब्ध करायी जा सके। इसके अलावा, व्यापारिक प्राप्ति बढाकरण प्रणाली (ट्रेड्स) के ज़रिये किए जा रहे फैक्ट्रिंग लेनदेन भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं। इस संबंध में हम यह भी जानते हैं कि बहुत से बैंक ऐसे हैं जिनके पास खुद का वेंडर फिनांस प्लैटफॉर्म है जिन पर वे एमएसएमई क्षेत्र को 'विदाउट रिकोर्स' आधार पर और कॉर्पोरेट को 'विद रिकोर्स' आधार पर फैक्ट्रिंग लेन-देन कर रहे हैं। चूंकि ट्रेड्स के तहत लाइसेंस प्राप्त दो इकाइयों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, यह आशा की जा रही है कि इससे बेहतर मूल्य तक पहुंच बढ़ेगी और एमएसएमई के लिए ज्यादा उपयुक्त दरें मिल सकेंगी। अब बैंक ट्रेड्स के माध्यम से 'विदाउट रिकोर्स' फैक्ट्रिंग लेन-देन को बढ़ावा देंगे क्योंकि इसके प्राथमिकता क्षेत्र से जुड़े होने का लाभ भी उन्हें मिल सकेगा।

(ii) क्षमता निर्माण

पिछले दो वर्षों से एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में बैंकों की क्षमता निर्माण करने के क्षेत्र में सीएबी एक

बड़ा अभियान चला रहा है जिसे बैंकों की क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय मिशन (नैमकैब्स) कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि अब तक इसके तहत 5 हजार से अधिक बैंकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो नैमकैब्स ने तीन प्रकार के सहभागियों पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया है, (1) कॉर्पोरेट कार्यालयों में कार्य कर रहे नीति निर्माता, (2) विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं में कार्यरत अधिकारी और (3) अलग-अलग बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत प्रशिक्षक। फिर भी, हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि सीएबी पूरे बैंकिंग समुदाय को प्रशिक्षित कर सकता है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य यही था कि बैंक के भीतर एक लक्षित समूह तैयार किया जाए जो इस अभियान को बढ़ाए। लेकिन यदि इन प्रशिक्षित अधिकारियों का नियोजन इस प्रकार नहीं किया जाएगा जिससे उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल का लाभ मिल सके तो क्षमता निर्माण की दिशा में सीएबी द्वारा किए जा रहे ये समस्त प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे।

(iii) क्लस्टर दृष्टिकोण

अब तक के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाए तो एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देना कहीं अधिक सार्थक और सुरक्षित है। अलग-अलग इकाइयों को एकाकी रूप से ऋण देने के बजाय यदि बैंकों को कारोबारी संभावनाएं तलाशनी हैं और ऐसी इकाइयों को ऋण प्रदान करना है जिनकी चुनौती क्षमता मजबूत है, तो क्लस्टर दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी राय तो यह है कि बैंकों को चाहिए कि वे न केवल मौजूदा क्लस्टरों को ऋण प्रदान करें बल्कि ऐसे नए क्लस्टर बनाने को भी प्रोत्साहन दें। ऐसा करने के लिए बैंकों को मजबूत डाटाबेस की आवश्यकता होगी और ऐसे क्षेत्रों, ऐसी गतिविधियों पर आंतरिक अनुसंधान करते हुए एक डिलीवरी मॉडल विकसित करना होगा।

(iv) संयुक्त ऋण व्यवस्था (को-ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स)

एक और बात कहना चाहता हूँ जो एमएसएमई एवं उससे भी अधिक माइक्रो इकाइयों से संबद्ध है और जिसे मैं पिछले काफी समय से अलग-अलग मंचों पर दोहराता रहा हूँ। यह संयुक्त ऋण व्यवस्था के बारे में है जिस पर रिज़र्व बैंक में काम चल रहा है। अगर हम इस बात पर

गौर करें कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसने बैंकों से सबसे ज्यादा ऋण लिया है तो हम पाएंगे कि यह वित्तीय मध्यस्थता वाला क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि बैंक गैर बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी) / सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) / आवासीय वित्त कंपनियों को जो ऋण हम देते हैं उसका इस्तेमाल वे अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए करती हैं। मैं इसे ढीली- ढाली बैंकिंग कहूंगा जिसमें अंततः न तो बैंक को और न ही अंतिम ग्राहक को फायदा होता है। तो, क्या हम कोई ऐसा स्थायी संयुक्त ऋण ढाँचा विकसित कर सकते हैं ? बैंक और एमएफआई आपसी तालमेल से संयुक्त रूप से ऋण देने की ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें जोखिम और ऋण से जुड़ी हुई अन्य बातों में पारस्परिक सहमति से साझेदारी हो ? इससे बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में विस्तार करने और अपने जोखिम के विशाखीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) का अच्छा अवसर मिल सकेगा। यह एक प्रकार से पारिश्रमिक भी देगा और साथ ही, प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में बैंकों के लिए सहायक होगा। रिज़र्व बैंक में इस पर विचार-विमर्श चल रहा है और हम कुछ ही समय में इस पर एक अंतिम राय बना लेंगे।

ख) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

पीएसएलसी ट्रेडिंग का उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। पहले ही साल में लगभग रु.1265 बिलियन मूल्य के कारोबारी प्रस्ताव पीएसएलसी प्लैटफॉर्म पर प्राप्त हुए हैं जिनमें से लगभग रु.498 बिलियन मूल्य के प्रस्तावों का निपटान किया गया। यह एक अच्छी शुरुआत है। पीएसएलसी ट्रेडिंग की चार श्रेणियों में से पीएसएलसी - छोटे और सीमांत किसान और पीएसएलसी-सामान्य श्रेणी में अधिक ट्रेडिंग देखी गयी। लेन-देन की राशि की दृष्टि से देखें तो पीएसएलसी ट्रेडिंग की चार श्रेणियों में से पीएसएलसी - छोटे और सीमांत किसान श्रेणी में रु.230 बिलियन और पीएसएलसी-सामान्य श्रेणी में रु.200 बिलियन का लेन-देन हुआ और शेष राशि का कारोबार अन्य दो श्रेणियों में मिलाकर किया गया। जैसी कि आशा थी, अधिकांश कारोबार तिमाहियों के आखिरी दिनों में हुआ चूंकि वर्तमान में प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों की मॉनिटरिंग तिमाही आधार पर की जाती है। ऐसे पीएसएलसी जिनकी खरीद-फरोख्त पहली तिमाही में हुई वे अधिक प्रीमियम पर थे और ऐसा तो होना ही था

क्योंकि पीएसएल अधिकारों की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। पीएसएलसी प्लैटफॉर्म एक आदेश मिलान प्लैटफॉर्म है लेकिन इसका एक दुखद पहलू जो हमारे देखने में आया है वह यह है कि कुछ इकाइयां द्विपक्षीय ट्रेडिंग कर लेती हैं और फिर इसे इस प्लैटफॉर्म पर रखती हैं जिससे अनाम आदेश मिलान की भावना को क्षति पहुंचती है। पीएसएलसी का इस्तेमाल मात्र एक रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म के तौर पर न करके उसी अनुरूप किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे तैयार किया गया है और केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही।

21. अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा जो कि सभी श्रेणियों के बैंकों के लिए प्रासंगिक हैं चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों, निजी क्षेत्र के हों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों या लघु वित्त बैंक।

(i) कम लागत पर आवास और स्वच्छता

प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कम लागत पर आवास एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं और बैंकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पिछले संशोधन में हमने निजी स्वच्छता ढाँचे हेतु ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है और हर घर में निजी टॉयलेट बनाने का आंदोलन भी चल रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए समग्र नीति बनाते समय बैंकों को चाहिए कि वे स्वच्छता संबंधी आधारीक अवसंरचना हेतु ऋण प्रदान करने पर ध्यान दें।

(ii) कृषि मूल्य शृंखला वित्तपोषण

दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने का है। कृषि मूल्य शृंखला को वित्त उपलब्ध कराने के प्रयास जब तक एक संगठित आंदोलन का रूप नहीं लेते, तब तक यह अनुपालन के लिए किया जाने वाला एक कार्य मात्र बना रहेगा और इससे अर्थव्यवस्था को जैसा लाभ होना चाहिए वह नहीं प्राप्त हो सकेगा। जब तक कृषि ऋण को मूल्य शृंखला से जोड़ा नहीं जाता, तब तक इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह एक अनुपालनात्मक कार्रवाई मात्र बना रहेगा।

(iii) जल संरक्षण और सौर ऊर्जा पम्पों को आर्थिक गतिविधियाँ मानते हुए उनके लिए वित्त उपलब्ध कराना

तीसरा क्षेत्र जल संरक्षण का है। वाणिज्यिक बैंक में पहले के मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता

हूं कि देश के कई भागों में जल संरक्षण के कार्य को आर्थिक गतिविधि मानते हुए से इसके लिए ऋण मुहैया कराकर हम अच्छा कारोबार कर सकते हैं। सूखे के समय यह फसल को बचाए रखता है और भूजल स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होता है। बैंकों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। यह भी एक ऐसी गतिविधि है जिस पर अनुसंधान और सर्वेक्षण करते हुए एक ऐसा मॉडल बनाने की आवश्यकता है जिससे किसानों तक पहुंचा जा सके। इसी प्रकार सोलर पम्प-सेटों के लिए वित्तपोषण भी बैंकिंग कारोबार का एक नया क्षेत्र बन सकता है। छोटे और मझोले किसानों के लिए इस प्रकार के कदम बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो सकारात्मक परिणाम ला सकती हैं लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इनके साथ-साथ वित्तीय जागरूकता का प्रसार भी किया जाए।

(iv) एसएचजी बैंक संपर्क मॉडल

एक अन्य क्षेत्र है-एसएचजी मॉडल। बीते समय में एसएचजी मॉडल एक मजबूत मॉडल रह चुका है। यद्यपि हाल फिलहाल में इसका प्रभाव कुछ घटा है, फिर भी बैंकों को चाहिए कि वे एसएचजी मॉडल के माध्यम से ऋण प्रदान करने की संभावनाओं की समीक्षा करें।

(v) ग्रामीण पदस्थापन

विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन की पूरी नीति पर नये सिरे से विचार किया जाए। हालांकि इस संबंध में नियम बनाए गए हैं और विनियामकीय अपेक्षाएं भी हैं लेकिन इस ढाँचे के भीतर रहते हुए भी बैंकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग को लेकर अधिक सार्थक नीति बनायी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित बैंक स्टाफ वहाँ पर एक निर्धारित समयावधि तक रुके, और दूसरे यह कि जितनी भी अवधि तक वे वहाँ रहें, अपना अधिकतम संभव योगदान करें। मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं के कामकाज के संबंध में यह एक बड़ा मुद्दा है

और ऐसे में आप सभी प्रभारी अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि इस मामले की बारीकी से निगरानी करें।

(vi) लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसएफबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों पर एक विस्तृत सार-संग्रह तैयार किया है। परिचालन प्रारंभ कर देने के उपरांत एसएफबी को पीएसएलसी में ट्रेडिंग करने की अनुमति भी दी गयी है और इसके लिए उन्हें 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त हो जाने की प्रतीक्षा भी नहीं करनी है। पीएसएलसी में हो रही कुल ट्रेडिंग के 15% से अधिक की ट्रेडिंग एसएफबी के माध्यम से की जा रही है जो कि एक अच्छा रुझान है। अभी इसी वर्ष से एसएफबी को एसएलबीसी बैठकों में भाग लेने की अनुमति भी दी गयी है लेकिन अप्रैल 2018 तक उनके लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत कोई अपेक्षाएं निर्धारित नहीं की गयी हैं। एसएफबी के लिए भुगतान बैंक बीसी के रूप में कार्य करेंगे और यह इन दोनों का गठजोड़ बहुत अच्छा फल देगा क्योंकि बहुत से भुगतान बैंक ऐसे हैं जिनकी पहुंच बहुत व्यापक और भीतर तक है।

निष्कर्ष

22. निष्कर्ष रूप में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने-अपने बैंक में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संविभाग के मुखिया हैं और आप प्राथमिकता क्षेत्र जैसे बड़े क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव ला सकते हैं। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के तहत दिया जाना वाला हर एक ऋण किसी का जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है और समग्र रूप से देखें तो प्राथमिकता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के असंख्य लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकता है। आपको इस परिवर्तन को साकार करने का माध्यम बनना है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस सेमिनार के प्रमुख विचार-बिंदुओं को अपने उच्च प्रबंध तंत्र की जानकारी में लाएं और उनके माध्यम से इसे अपने बोर्ड तक पहुंचाएं।

मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सीएबी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया और आपको संबोधित करने का अवसर प्रदान किया।

भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री* विरल वी. आचार्य

गवर्नर, उप-गवर्नर एस.एस.मूंदड़ा, एन.एस.विश्वनाथन और बी.पी. कानुंगो, हमारे मुख्य अतिथि और सभी वक्तागण आप सभी को नमस्कार.

वार्षिक सांख्यिकी दिवस का परिचय

कल शाम को सम्मेलन से पहले हुए डिनर के समय श्री चेतन भगत की बातों से ही शुरुआत करें, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आज यहाँ आप सभी केवल 'उपस्थित' नहीं हैं बल्कि 'सोत्साह उपस्थित' हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इस वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आपको धन्यवाद। इस सभागार की क्षमता सीमित है और हमारे बहुत से युवा सहकर्मी इसी भवन में तीन अन्य स्थानों पर बैठे हुए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये इस सम्मेलन में शरीक हो रहे हैं।

2. रिज़र्व बैंक का यह सम्मेलन इस श्रृंखला में दसवां है, लेकिन मेरे लिए यह प्रथम सांख्यिकी दिवस सम्मेलन है। मैं भी इसमें होने वाली परिचर्चाओं का साक्षी बनने को उत्सुक हूँ।

3. भारत में स्वर्गीय प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस की जयंती पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रो.महालनोबिस ने सन 1912 में भौतिकी आनर्स में स्नातक की उपाधि पाई थी और बाद में इनकी रुचि सांख्यिकी में हो गई। आधुनिक प्रबंधन की भाषा में कहें तो प्रोफेसर महालनोबिस 'लीक से हटकर' सोचनेवाले व्यक्ति थे। तात्कालिक महत्व की सांख्यिकीय समस्याओं का अध्ययन करने के दौरान ही उनका समस्त योगदान हमें प्राप्त हुआ। गवर्नर महोदय ने भी अपने उद्घाटन भाषण में जिक्र किया था कि प्रो. महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) की स्थापना की थी और वहाँ पर स्थित सर्वे प्रयोगशाला ही बाद में विकसित होकर आज के राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (राप्रसका) का रूप ले चुकी है। सांख्यिकीय विषयों पर आईएसआई और मापन विषयों पर

राप्रसका के साथ समन्वय करके आर बी आई को बहुत लाभ पहुंचा है।

4. आज के इस सम्मेलन में बहुत से प्रतिष्ठित अतिथियों की मौजूदगी से हमें गौरव का अनुभव हो रहा है। हमारे प्रमुख वक्ता डॉ. मार्टिन ड्रेन्ड इस समय ओईसीडी स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टोरेट में चीफ स्टेटिस्टीशियन और डायरेक्टर हैं तथा वैश्विक सांख्यिकीय विषयों पर अग्रणी व्याख्याता हैं। वे आज सुबह ही पेरिस से आई हैं। भारत और रिज़र्व बैंक में आपका हार्दिक स्वागत है, मार्टिन - नमस्ते।

5. मैं, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य और रिज़र्व बैंक अकादमी में नियमित रूप से अध्यापन कर रहे आईएसआई दिल्ली के प्रोफेसर चेतन घाटे का और विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन के प्रो.एन.बालकृष्ण का भी स्वागत करता हूँ, जो आज के हमारे विशिष्ट वक्ता हैं।

6. दोपहर बाद हमारे साथ प्रो.दिलीप नाचाने भी होंगे जो आईजीआईआर, मुंबई में प्रोफेसर एमीरेट्स हैं, और काफी समय तक मौद्रिक नीति पर रिज़र्व बैंक की तकनीकी सलाहाकार समिति तथा प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहाकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इस सम्मेलन के केंद्रीय विषय पर पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता वही करेंगे। पैनल के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों- क्रिसिल के डॉ. डी.के. जोशी, एचएसबीसी की सुश्री प्रांजल भंडारी और सिटी बैंक के डॉ. समीरन चक्रवर्ती - का भी मैं स्वागत करता हूँ। सांख्यिकी दिवस के लिए अपना बहुमूल्य समय देने हेतु पैनल के सभी सदस्यों को धन्यवाद।

7. अब मैं आज के सम्मेलन के मुख्य विषय अर्थात् 'केन्द्रीय बैंकों के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों और सूचना आधार से संबद्ध नवीन अध्ययन क्षेत्र' पर आता हूँ। सांख्यिकीय तकनीकें आर्थिक विश्लेषणों का अभिन्न हिस्सा होती हैं। यह देखना अपने आप में बड़ा रोचक है कि आर्थिक विज्ञानों के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबल पुरस्कारों में बड़ी संख्या 'प्रविधि पुरस्कारों (मैथड अवार्ड्स)' की होती है जिससे इन तकनीकों के महत्व की पुष्टि होती है। अर्थशास्त्र में पहला नोबल पुरस्कार 1969 में रेग्नर फ्रिश्ख और जेन टिनबरजेन को अर्थमितीय मॉडल निर्माण विषयक उनके अनुसंधान कार्य के लिए दिया गया था जिसमें उन्होंने आर्थिक सिद्धान्त और सांख्यिकीय प्रविधियों का पारस्परिक संबंध स्थापित किया था। बाद के वर्षों में भी नोबल 'मैथड अवार्ड' कई कार्यों के लिए प्रदान किए गए जैसे- इनपुट आउटपुट प्रविधि, राष्ट्रीय बही खाते, व्यष्टि-

* 04 जुलाई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित 11 वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन के मुख्य विषय पर डॉ.विरल वी.आचार्य, उप गवर्नर द्वारा दिया गया भाषण। डॉ.ओ.पी.मल्ल और श्री अनुजित मित्रा द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आभार।

अर्थमिति, समाकलन और एआरसीएच (राबर्ट एन्जल को जो मेरे सहकर्मी, सहलेखक और प्रिय मित्र रहे जब मैं न्यूयार्क यूनिवर्सिटी स्टर्न में था) के लिए।

8. आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकीय प्रविधियों की केन्द्रीय भूमिका इस बात से भी प्रकट होती है कि अर्थशास्त्र और वित्त के अध्ययनकर्ताओं के पाठ्यक्रम में इसका अंश निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विश्वव्यापी वित्तीय संकट और इसके कुपरिणामों के बाद उत्पन्न संरचनागत अंतराल यह दर्शाता है कि कौन से नए दृष्टिकोण और प्रविधियाँ अब स्थापित हो रही हैं। विगत दशक के दौरान समष्टि आर्थिक अनुमानकर्ताओं के सामने रोचक सवाल आए क्योंकि बैंकिंग और सरकारों के समक्ष संकटों की शुरुआत ने अनुमानों के उल्लंघन के बाद मूलभूत धारणाओं की तरफ मोड़ दिया है। इसने प्रविधिगत सुधारों की तरफ प्रयासों की जरूरत को दर्शाया है, केवल आर्थिक सिद्धान्त की परीक्षा हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों में भी सुधार जरूरी है। मेरे विचार से अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है।

9. सन 2009 में G-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में जी-20 डाटा गैप प्रयासों (डीजीआई) का समर्थन किया गया जो (क) वित्तीय क्षेत्र में जोखिम बढ़ते जाने; (ख) सीमा-पार के वित्तीय सम्पर्क; (ग) घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की आघातसहनीयता में कमी आने, और (घ) आधिकारिक सांख्यिकी के संचरण को सुधारने - पर केंद्रित है। डीजीआई के प्रथम चरण के व्यापक कार्यान्वयन के बाद, सन 2015 में इसका दूसरा चरण इस प्रयोजन के साथ आरंभ किया गया कि विश्वव्यापी सांख्यिकीय प्रणालियों को मज़बूत बनाया जाए ताकि अधिक गहन आर्थिक विश्लेषण में सहायता मिल सके। इस दिशा में भारत की प्रगति अभी तक तो अच्छी रही है, और हम इस विश्वास के साथ आगे भी प्रयासरत हैं कि ऐसे प्रयासों से अलग-अलग देशों को तो फायदा मिलेगा ही, इनसे वैश्विक आर्थिक प्रणाली को भी मदद मिलेगी।

भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री हेतु अवस्थिति

10. अब मैं अपनी शेष चर्चा में उस विषय पर फोकस करूँगा, जो मेरी समझ में वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक को और खासतौर पर सांख्यिकी विभाग को और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यह लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) की स्थापना से संबंधित है जो कि भारत के लिए

ऋण सूचना का व्यापक डाटाबेस होगा और जो सभी हितधारकों की पहुंच में होगा। आमतौर पर पीसीआर का प्रबंधन एक लोक प्राधिकरण जैसे कि केन्द्रीय बैंक अथवा बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है और कर्जदारों एवं/ अथवा कर्जदाताओं द्वारा पीसीआर को कर्ज के विवरण प्रदान करना कानूनन अनिवार्य बनाया जाता है। अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में संविदाकारी शर्तें और शामिल परिणाम तथा एक निर्धारित सीमा से अधिक वाली संविदाओं की रिपोर्टिंग अलग-अलग हो सकती है, लेकिन धारणा यही है कि कर्जदारों से संबंधित डाटाबेस में सभी संबंधित जानकारी, खासतौर पर कर्जदारों की सभी कर्जदारी संविदाओं और परिणामों को हासिल कर लिया जाए।

11. यदि भारत में पीसीआर स्थापित कर दिया जाता है तो यह- (क) बैंकों द्वारा क्रेडिट आकलन और दर निर्धारण; (ख) बैंकों में जोखिम आधारित, गतिशील और प्रतिक्रमावर्ती प्रवधान; (ग) विनियामकों द्वारा पर्यवेक्षण और अग्रिम हस्तक्षेप ; (घ) यह समझना कि मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन प्रभावी है, और यदि नहीं तो अडचनें कहाँ हैं; और (ङ) दबावग्रस्त बैंक क्रेडिट की पुनर्संरचना कैसे की जाए - जैसे कार्यों में सहायक होगी। ऐसे मामलों पर स्पैनिश क्रेडिट रजिस्टर का प्रयोग करते हुए यूनिवर्सिस्टाट पॉम्प्यू फैब्रा (universitat pompeu fabra) के प्रोफेसर जोसे लुइस पैद्रा (Jose-Luis peydro) का व्यापक और मर्मभेदक अतिसूक्ष्म अध्ययन इसका प्रमाण है कि बुनियादी अर्थव्यवस्था को साफतौर पर समझने के लिए पीसीआर कितनी मूल्यवान हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप उनका शोध-कार्य अवश्य पढ़िए।

12. अब मैं उन चीजों पर बात करना चाहूँगा जहाँ से इस प्रकार का डाटाबेस तैयार करने की प्रेरणा मिली। अकादमीय साहित्य बहुतायत में क्रेडिट बाज़ारों में पारदर्शिता की वकालत करता है, और यह तर्क देता है कि इससे बाज़ार की कुशलता बढ़ती है और क्रेडिटर तथा कर्जदार दोनों को मदद मिलती है। इस क्रेडिट सूचना को “लोक हित” का नाम देने के कारणों में से एक यह भी है कि इसकी उपयोगिता बड़े पैमाने पर ऋण बाज़ार के लिए और आमतौर पर समाज के लिए है। क्रेडिट सूचना के लिए केन्द्रीय डाटाबेस की गैर मौजूदगी में ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों के बारे में सीमित जानकारी मिलती है, जो उनके सीमित लेनदेन अथवा अंतःक्रियाओं पर आधारित होती है और यह अधिकचरे परिणामों की तरफ भी ले जा सकती है।

13. एक केन्द्रीय आगार, उदाहरण के लिए जो जमानतों के विवरण लेकर सत्यापित करती है, ऐसी संविदाओं का लेखन सक्षम करती है जो कर्जदार द्वारा जमानतों को अतिगिरवी रखे जाने से बचाती है। ऐसे आगार की गैर मौजूदगी में प्रतिभूति पर ऋणदाता अपने प्रथम अधिकार के बारे में विश्वस्त नहीं हो सकता और हो सकता है कि कर्ज पर ज्यादा लागत लगाए या जरूरत से ज्यादा प्रतिभूतियों के लिए कहे ताकि अन्य ऋणदाताओं द्वारा जमानत के कमजोर किए जाने से बचाव हो सके। अर्थशास्त्र में इसे “आकस्मिक मालियत” कहा जाता है - इस मामले में किसी एक कर्ज-संविदा का प्रभाव दूसरी कर्ज-संविदाओं के परिणामों और शर्तों पर पड़ता है। इसके अलावा, लोक ऋण रजिस्ट्री की गैर मौजूदगी में “भले” कर्जदार अपारदर्शी क्रेडिट बाजारों में स्वयं को दूसरों से अलग नहीं दिखा पाते हैं, ऐसे में जानकारी का एकाधिकार रखनेवाले वर्तमान ऋणदाता उनसे अधिक लगान वसूलते हैं। ऋणदाता भी नए ग्राहक तलाशने में ऐसे लोगों को भी पा जाते हैं जिनके कदाचार सभी ऋणदाताओं को ज्ञात नहीं है, फलस्वरूप समग्र रूप से क्रेडिट जोखिम सामने आ जाता है।

भारत ऋण सूचना की वर्तमान प्रणाली

14. अब हम अपने देश में ऋण सूचना की वर्तमान प्रणालियों की बात करते हैं। भारत में कार्यरत निजी क्रेडिट ब्यूरो का नियन्त्रण रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण आसूचना कम्पनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत किया जाता है और इनमें क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल), इक्वीफैक्स, एक्सपेरियन और सीआरआईएफ हाईमार्क नामक संस्थाएँ शामिल हैं। क्रेडिट स्कोर और संबद्ध रिपोर्ट तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए इनमें से प्रत्येक फोकस डाटा विश्लेषण पर रहता है। बैंकों द्वारा इन विश्लेषणों का प्रयोग क्रेडिट कार्ड जारी करने और (मुख्य रूप से खुदरा ऋणों) के निर्णय लेने में किया जाता है।

15. रिज़र्व बैंक द्वारा सेन्ट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) की स्थापना 2014-15 में की गई। अब स्थानेत्तर पर्यवेक्षण के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण डाटाबेस है। भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने बड़े कर्जदारों की रिपोर्टिंग यहां पर करते हैं; अर्थात् जिनमें 5 करोड़ भारतीय रुपये और इससे अधिक का समग्र निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम है। अनुसूचित

वाणिज्य बैंकों के ऋण-पोर्टफोलियो का लगभग साठ प्रतिशत और गैर-निष्पादक ऋणों का लगभग अस्सी प्रतिशत इसके दायरे में है। इसके लिए तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है, लेकिन भूलचूक की रिपोर्टिंग जब और जैसे आधार पर अलहदा फार्मेट में करनी होती है। सीआरआईएलसी का डिजाइन पूरी तरह से पर्यवेक्षण प्रयोजनों से किया गया है और इसका फोकस विभिन्न शीर्षों के तहत कर्जदाता (अलग-अलग और/अथवा समूह के तौर पर) की वजह से प्रतिष्ठानों द्वारा अनावरण की रिपोर्टिंग पर रहता है, जैसे किसी बड़े कर्जदार के लिए बैंक की अनावृत्ति; कर्जदार के चालू खाते में शेषराशि; बैंक के बड़े खाते डाले जा चुके खाते; और अन्य के साथ-साथ असहयोगी कर्जदारों की पहचान करना। हालांकि सीआरआईएलसी में कर्जदारों के बारे में केवल सीमित विवरण ही लिए जाते हैं, जैसे कि उनका संबंध किस उद्योग से है और उनकी आंतरिक और बाह्य रेटिंग। सीआरआईएलसी के तहत जुटाई गई जानकारी रिपोर्टिंग करने वाले बैंकों को तो दी जाती है लेकिन सी बी, बृहद ऋणदाता समुदाय अथवा शोधकर्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जाती है।

16. डीएसआईएम में कार्यरत मेरे सहकर्मी बेसिक सांख्यिकीय विवरणी-1 अथवा बीएसआर1 से परिचित हैं। इसमें बैंकों द्वारा खाता स्तरीय क्रेडिट जानकारी (किसी खास कर्ज अथवा बैंक और कर्जदार के बीच सुविधा को “खाता” कहा गया है) की रिपोर्ट दी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक सांख्यिकीय विवरणी है जो खाते के लिए कुछ मेटाडाटा संकलित करती है, जैसे कि निधियों के उपयोग स्थान के जिले और जनसंख्या समूह; खाते का प्रकार जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, सावधि कर्ज, क्रेडिट कार्ड इत्यादि; संस्था का प्रकार जैसे कि निजी निगमित क्षेत्र, हाऊसहोल्ड क्षेत्र, सूक्ष्म वित्त संस्थान, गृहस्थ-सेवार्थ गैर-लाभ अर्जक संस्थाएँ और अनिवासी; तथा व्यवसाय प्रकार जैसे कि कृषि, विनिर्माण, भवन-निर्माण और विभिन्न वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सेवाएँ। इसी के साथ परिवर्तनशील बनाम निश्चित दर पर ली जाने वाली ब्याज दरें भी बताई जाती हैं। ये विवरण सीआरआईएलसी में नहीं होते, जो कर्जदार-स्तरीय डाटा सेट है न कि खाता-स्तरीय डाटासेट? यद्यपि बीएसआर1 में प्रत्येक खाते की “सेहत का कोड” भी रहता है, लेकिन यह इतना संपूर्ण नहीं होता जो पर्यवेक्षी जरूरतों को पूरा करे क्योंकि सभी रिपोर्टिंग बैंकों के लिए

विशिष्ट पहचानकर्ता की गैरमौजूदगी में एक कर्जदार द्वारा चलाये जा रहे सभी खातों को समेकित करना व्यावहारिक नहीं हो पाता है। बहुत से कारण हैं, जिससे बीएसआर1 में भूल-चूक के बैंक-स्तरीय संकलन भी सीआरआईएलसी के माध्यम से सूचित तथ्यों में सामान्य रूप से मेल नहीं रहेगा। स्पेशियल, टेम्पोरल और सेक्टरल वितरण सहित बीएसआर1 से जो समग्र सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त होती है वह शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और व्याख्याताओं के लिए सार्वजनिक मंच पर दी जाती है। हालांकि खाता-स्तरीय डाटा को गुप्त रखा जाता है लेकिन समुचित सुरक्षा रखते हुए रिज़र्व बैंक यह डाटा भी मामला-दर-मामला आधार पर शोधकर्ताओं को प्रदान करता है।

17. रिज़र्व बैंक में रखा गया यह डाटाबेस अलग-अलग बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल नहीं मिल पाता है, जिससे वे सूक्ष्म स्तर पर क्रेडिट निर्णय ले सकें। वे संस्था स्तर पर क्रेडिट डाटा को पूरी तरह से समेकित नहीं करते हैं। सटीक तौर पर कहे तो जितनी भी प्रणालियों का जिक्र हुआ है उनमें ऋणदाता को 360 डिग्री पहुंच नहीं मिल पाती। एकाकी तौर पर देखें तो इनमें से कुछ प्रणालियों को कुछ अतिरिक्त फील्ड जोड़कर आसानी से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बीएसआर1 में खाता-धारक का निर्धारण करने के लिए और कार्पोरेट अभिनिर्धारक संख्या (सीआइएन) का प्रयोग कम्पनियों के मामले में प्रत्येक कर्जदार के सभी खातों को देखना सम्भव हो सकेगा।

18. अब मैं आपका ध्यान रिज़र्व बैंक में और निगम कार्य मंत्रालय में उपलब्ध कम्पनी-वित्त-डाटाबेस की तरफ दिलाना चाहूँगा। इसमें कार्पोरेट द्वारा विभिन्न अंतरालों पर प्रस्तुत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संकलन किया जाता है। यहाँ भी महत्वपूर्ण अभिनिर्धारक सीआइएन ही है। यदि हम बीएसआर1 और सीआरआईएलसी में संवाद स्थापित कर सकें और कार्पोरेट क्षेत्र के वित्तीय परिणामों वाले एमसीए डाटाबेस के साथ दोनों को जोड़ सकें तो सूचना की शक्ति काफी बढ़ाई जा सकती है।

लोक ऋण रजिस्ट्रों के बारे में अंतरराष्ट्रीय अनुभव

19. अब मैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ आता हूँ। विश्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सन 2012 की स्थिति के अनुसार सर्वेक्षित 195 देशों में से 87

देशों में लोक ऋण रजिस्टर (पीसीआर) विद्यमान थे- और अब तक तो यह संख्या अवश्य बढ़ गई होगी। बहुत से विकसित देशों में निजी क्रेडिट ब्यूरो भी अच्छा काम कर रहे हैं और वे पीसीआर के साथ सह-अस्तित्व बनाए हुए हैं। यूएस में थॉमसन रियूटर्स द्वारा संचालित डीलस्कैन उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें सिन्डीकेटेड लोन ऑरिजिनेशन डाटा को दायरे में लाया गया है जिसमें व्यवस्थाकर्ताओं; कीमत और परिपक्वता शर्तों; क्रेडिट लाइंस अथवा सावधि ऋणों और कर्ज की विशेषताओं जैसे कि कोवर्नेट्स के बारे में भी जानकारी होती है। चूंकि ऋण देते समय ही बैंक स्वेच्छा से क्रेडिट डाटा प्रदान करते हैं, यह एक प्रकार से तत्काल उपलब्ध होने वाला डाटाबेस है और एक सप्ताह अथवा दो सप्ताह के भीतर ही किसी को भी यह जानकारी मिल जाती है कि क्या क्रेडिट-बाजार की स्थितियों में कोई बदलाव हुआ है।

20. डून एन्ड ब्रेडस्ट्रीट या संक्षेप में कहें तो डीएनबी लगभग दो शताब्दी पुराना है, और शायद विश्व में सबसे पुराना वाणिज्यिक डाटाबेस इसके पास है। उनकी वेबसाइट का दावा है कि वे 265 मिलियन कम्पनी रिकार्ड को ट्रैक करते हैं, यह रिकार्ड वे 30, 000 डाटा स्रोतों से हासिल करते हैं और इसे प्रतिदिन 50 लाख बार अपडेट किया जाता है। डीएनबी के अपने संवाददाता डाटा जुटाने के लिए फर्मों के प्रधानों को टेलिफोन करते हैं और स्वयं भी जाते हैं। यह जानना रोचक रहेगा कि 19 वीं शती में ये संवाददाता अक्सर वकील हुआ करते थे जिनमें अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन और कोल्विन कोलिज जैसे प्रख्यात लोग भी थे (संदर्भ जे.जी. कॉलबर्ग, जी.एफ.उडेल/ जर्नल ऑफ बैंकिंग एन्ड फिनान्स 27(2003)449-469)।

21. ऐसी सूचना प्रणाली की उपयोगिता को बताने के लिए अब मैं एक जीवंत उदाहरण देता हूँ। सितम्बर 2008 में लेहमेन ब्रदर्स के धराशायी होने के बाद ऐसे अर्थशास्त्री थे जो यह मानते थे कि संयुक्त राज्यों में क्रेडिट का प्रवाह अप्रभावित रहा क्योंकि बैंक-ऋणों में प्रबल क्रेडिट संवृद्धि रही। लेकिन थामसन रियूटर के डीलस्कैन डाटा के गहरे विश्लेषण से जात हुआ कि यह क्रेडिट संवृद्धि पूरी तरह से विद्यमान क्रेडिट लाइन का सहारा लेते हुए कार्पोरेटों द्वारा निकासी (एक प्रकार का बैंक-धाव) के कारण हुई। नए कर्जों की व्युत्पत्ति तो वस्तुतः उड़न छू हो गयी थी।

भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री किस प्रकार मदद कर सकती है

22. अब हम यह कल्पना करते हैं कि भारतीय परिस्थितियों में लोक ऋण रजिस्ट्री कितनी मददगार साबित होगी। सबसे पहले तो यह कि हमारे देश में क्रेडिट संस्कृति को सुधारने के लिए यह अपेक्षित है। “ड्रूइंग बिजनेस 2017” की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि क्रेडिट सूचना प्रणालियाँ क्रेडिट बाजार में पारदर्शिता लाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्रेडिट तक पहुँच में सुधार होता है और आर्थिक कदाचार कम हो जाते हैं। वर्तमान में बहुत से भारतीय बैंक एनपीए के बोझ तले दबे होने के कारण विश्वासपूर्वक क्रेडिट-निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पारदर्शी लोक ऋण रजिस्ट्री से बैंकर्स को वस्तुनिष्ठ डाटा पर निर्भर रहते हुए क्रेडिट निर्णय लेने में मदद मिलेगी और संवीक्षा के दौरान वे बाजार का साक्ष्य देते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव करने में सक्षम रहेंगे।

23. दूसरी बात यह कि क्रेडिट बाजार में बड़े कर्जदारों को सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान उनकी साख के कारण प्राथमिकता मिलती है। वे क्रेडिट हिस्ट्री, ब्रान्ड वैल्यू और जमानत प्रस्तुत करने के मामलों में अच्छी साख स्थापित कर चुके हैं। इसके विपरीत छोटे और सीमांत उद्यमी, स्टार्ट अप, नए उद्यमी और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र में छोटे कारोबारियों की स्थिति इस मामले में उतनी अनुकूल नहीं होती क्योंकि क्रेडिट के लिए निर्धारित कई शर्तें वे पूरी नहीं कर पाते। पारदर्शी क्रेडिट सूचना इन कर्जदारों के लिए “प्रतिष्ठागत जमानत” का काम करेगी। यह न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि भले-कर्जदारों को लाभान्वित भी करेगा जिससे क्रेडिट अनुशासन सृजित होगा। हम ईबे पर लेनदेन करने में अपनी तत्परता को देखें तो समझ जाएंगे कि वेबसाइट पर दिए गए अज्ञात विक्रेताओं के सौदों के रिकार्ड से ही किस तरह उनकी कारोबारी हैसियत बन जाती है। इस प्रकार यह लोक ऋण रजिस्ट्री विभिन्न हैसियत वाले कर्जदारों के लिए एक समान कारोबारी अवसर प्रदान करेगी।

24. तीसरी बात यह कि बहुत से देशों में लोक ऋण रजिस्ट्री की भूमिका कर्जदारों और विभिन्न संस्थानों के बीच क्रेडिट-सम्बन्ध से भी आगे निकल चुकी है। वे खुदरा ग्राहकों के संबंध में बिजली और फोन जैसी सुविधाओं हेतु भुगतानों और कारोबारियों के लिए व्यापारिक क्रेडिट डाटा सहित कर्जदारों के अन्य लेनदेन के आंकड़े भी जुटाते हैं। ऐसे डाटा क्या मदद करते हैं? औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता क्रेडिट स्कोर नहीं होने

के कारण नए ग्राहकों को लाइन क्रेडिट सुविधा प्रदान करने में बहुधा संकोच करते हैं। उपभोक्ता सेवाओं और व्यापारिक उधारदाताओं को भुगतान करने में नियमितता से ऐसे ग्राहकों की साख की कोटि का पता चल जाता है। बदले में औपचारिक क्षेत्र से नए कर्जदारों को भी क्रेडिट मिल जाता है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इससे लगे हाथ नीति निर्माताओं को यह लाभ मिलता है कि वे वित्तीय समावेशन के दायरे को और अधिक बारीकी से भाँप सकते हैं।

25. अंतिम बात यह कि विनियामकीय प्रयोजनों के लिए लोक ऋण रजिस्ट्री का प्रगाढ़ प्रभाव पड़ता है। इसकी गैर-मौजूदगी में क्रेडिट व्यवहार और ऋणग्रस्तता की केवल खंडित छवि प्राप्त करने में मदद करेगा जो पर्यवेक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है ताकि वे समस्त प्रणाली के क्रेडिट जोखिम का आकलन कर सकें। इसमें सुविधा के लिए पीसीआर वह सम्पूर्ण छवि प्राप्त करने में मदद करेगा जो पर्यवेक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है ताकि वे समस्त प्रणाली के क्रेडिट जोखिम का आकलन कर सकें। इसमें सुविधा के लिए पीसीआर को क्रेडिट डाटा के निम्नलिखित पहलुओं को अवश्य देखना होगा-प्रथम यह कि कर्जदार की आर्थिक और वित्तीय सेहत के बारे में डाटा के साथ-साथ शुरुआत के समय कर्ज की शर्तों का विवरण देते हुए बैंक कर्जदार के कर्जस्तरीय डाटा; द्वितीय यह कि आंतरिक और बाह्य रेटिंग (अथवा क्रेडिट स्कोर) और उनका क्रमागत विकास और जहाँ भी अनुमेय हो फर्मस्तरीय और क्षेत्र-स्तरीय क्रेडिट जोखिम हेतु बाजार-आधारित उपाय; तृतीय यह किस भी विवरणों सहित बैंक - कर्जदार कर्ज-स्तरीय पुनर्संरचना डाटा; चतुर्थ यह कि द्वितीयक कर्ज- विक्रय और कीमत सूचना; पंचम यह कि कर्जदार-देनदारी स्तरीय चूक और वसूली आंकड़े। यह एक अच्छी शुरुआत होगी।

लोक ऋण रजिस्ट्री का संचालन कौन करेगा?

26. बहुत से देशों में बड़े लोक ऋण रजिस्ट्रों का संचालन केन्द्रीय बैंकों या फिर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। इनका संचालन अमूमन निजी क्षेत्र द्वारा नहीं किया जाता है, तथापि कुछ अधिकारक्षेत्रों में हमने जिन मदों पर चर्चा की है, उनमें से बहुत सी मदों का समेकन सीबी में किया जाता है। कुछ अधिकार क्षेत्रों में केन्द्रीय पीसीआर द्वारा संकलित अपरिष्कृत डाटा सीबी को दिया जाता है जो अन्य स्रोतों से प्राप्त डाटा को सम्मिलित करके इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए अन्य विश्लेषण जैसे कि क्रेडिट स्कोर/ग्राहकों

अमूमन वाणिज्यिक उधारदाताओं को रिपोर्ट प्रदान करते हैं। क्योंकि हम ऐसे बड़े डाटाबेस की बात कर रहे हैं जिसमें काफी कुछ निजी सूचना होती है, इसलिए इसका रखरखाव ऐसे प्राधिकरण द्वारा करने की जरूरत है जो जनता की नजरों में विश्वसनीय हो और जिसके पास कानूनी शक्तियाँ भी हों ताकि सामयिक और समग्र डाटा संकलन सुनिश्चित हो सके। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही देखा गया है कि केवल कुछ अपवादों को छोड़ दें तो प्रायः पीसीआर का संचालन केन्द्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

सारांश

27. मैं अपनी बात के अंत में फिर से यही कहूँगा कि भारत के लिए पारदर्शी और सम्यक लोक ऋण रजिस्टर का होना समय की मांग है। अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में क्रेडिट संस्कृति को सुधारने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा देश इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे रजिस्टर क्रेडिट बाजार कि कुशलता बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, कारोबार में सहूलियत लाने और कारोबारी कदाचार पर नियंत्रण रखने में सहायक हैं। कर्जदारों के लिए विशिष्ट अभिनिर्धारकों (व्यक्तियों के लिए आधार तथा कम्पनियों के लिए सीआइएन) का प्रयोग करके रिज़र्व बैंक बीएसआर¹ और सीआरआईएलसी डाटा सेटों को शीघ्रता से पीसीआर में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें शुरुआती तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहकों को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भारत की अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। समय के साथ

पीसीआर में और भी समग्रता आएगी और यह क्रमशः अधिक प्रभावी होती जाएगी।

28. समग्र पीसीआर स्थापित करने के लिए हालांकि बहुत ज्यादा टीमवर्क और विज्ञान की जरूरत होगी। विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए विभिन्न प्रकार के डाटा की भारी मात्रा का रखरखाव करने के लिए विशेषज्ञता की जरूरत पड़ेगी। ऐसे रजिस्ट्रों की स्थापना के लिए विभिन्न लाभार्थी, अन्य विनियामक और विशेषज्ञता रखने वाली अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ मिलकर काम करना अपेक्षित होगा। यहां 11 वे सांख्यिकी दिवस के अवसर पर एकत्र हुए सांख्यिकी विदों के लिए यह बहुत अच्छी चुनौती होगी। गवर्नर महोदय को और मुझे यह आशा है कि हम एक उच्च स्तरीय कार्यबल स्थापित करने में सफल होंगे जो हमारे देश के लिए शक्तिशाली क्रेडिट सूचना प्रणाली विकसित करेगा और उसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

29. इस टीम के समक्ष एक अति विस्तृत फलक पर 'सूचना आधार' जुटाने की चुनौती होगी जिसमें कुछेक को इस प्रकार गिनाया जा सकता है- रोजगार सांख्यिकी; ग्रामीण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हाउसहोल्ड स्फीति अनुमान सर्वेक्षण; कीमतों और उपभोग के बिग डाटा तत्काल संकेतक; आर्थिक गतिविधि संकेतकों के लिए गूगल इमेजेज़ और मोबाइल फोन डाटा। यदि हम इनमें से कुछ तक भी अपनी पहुंच बना सके तो यह प्रोफेसर महालनोबिस के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, जिनका योगदान सार्वकालिक है और जिसके लिए वे मरणोपरांत भी हमेशा याद किए जाएंगे।

लेख

भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह लेखे : 2015-16

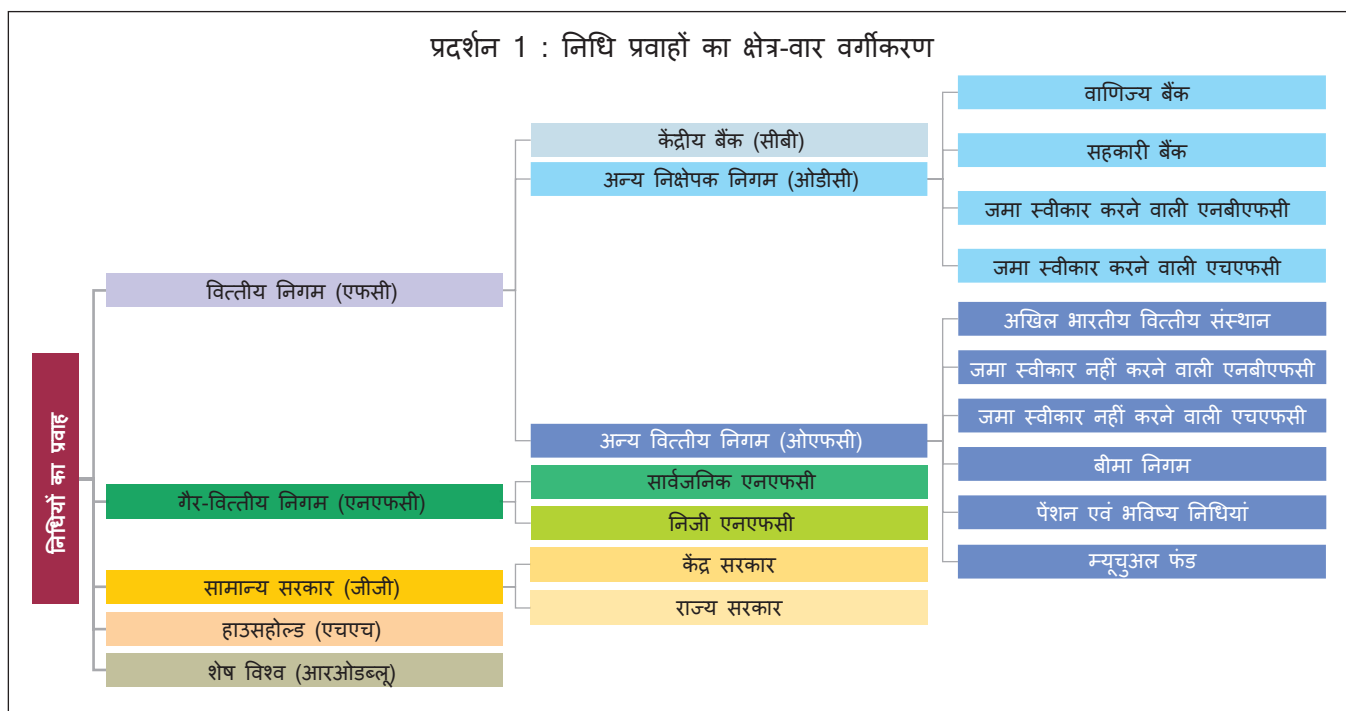
भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह लेखे : 2015-16*

पण्य मूल्यों में नमी और पूंजी निर्माण में कमी होने की विशेषताओं वाले माहौल में, 2015-16 में अर्थव्यवस्था का वित्तीय संसाधन अंतराल और अधिक संकीर्ण हुआ। सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले वित्तीय लिखतों में मुद्रा और जमाराशियों के स्थान पर 'ऋण और उधारियां' का शुमार हुआ। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत, जमा स्वीकार करने वाले निगमों, जिनमें मुख्यतः बैंक शामिल होते हैं, की देयताओं में कमी आई। इस कमी का मुख्य कारण समय जमाराशि में कमी होना रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त के आपूर्तिकर्ता के रूप में गैर-बैंक वित्तीय निगमों (एनबीएफसी) का महत्व बढ़ा। हाउसहोल्ड

क्षेत्र के वित्तीय अतिरेक में वर्ष के दौरान वृद्धि जारी रही।

I. प्रस्तावना

इस लेख में, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2015-16 से संबंधित निधि प्रवाहों (एफओएफ) तथा 2014-15 और 2013-14 से संबंधित अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) 2008¹ के अनुरूप है। एफओएफ लेखे लिखत-वार वित्तीय प्रवाह को भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पांच प्रमुख संस्थागत क्षेत्रों में 'किससे किसको' आधार पर दर्शाते हैं। इन संस्थागत क्षेत्रों² में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) वित्तीय निगम (एफसी); (ii) गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी); (iii) सामान्य सरकारी (जीजी), जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें-दोनों शामिल हैं; (iv) हाउसहोल्ड क्षेत्र (एचएच); एवं (v) शेष विश्व (आरओडब्लू) (प्रदर्शन 1)।



* यह लेख भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग में तैयार किया गया। निधि प्रवाह से संबंधित 1 से 9 तक के विस्तृत विवरण www.rbi.org.in में अलग से जारी किए गए हैं। इन विवरणों के हाइपरलिंक भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के अगस्त 2017 के अंक में प्रेस प्रकाशनी में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें यह लेख प्रकाशित किया गया है। इस तरह का पिछला लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के अगस्त 2016 अंक में प्रकाशित किया गया था।

¹ पहले के वर्गीकरण से इसमें आई प्रमुख भिन्नताएं निम्नलिखित हैं : (क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के तहत सार्वजनिक गैर-वित्तीय एवं वित्तीय निगमों को (सामान्य) सरकारी क्षेत्र से अलग वर्गीकृत किया गया है; (ख) जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पहले के अन्य वित्तीय संस्थान क्षेत्र के अधीन जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी के साथ दर्शाए जाने के स्थान पर बैंकों के साथ में अन्य जमा स्वीकार करने वाले निगमों (ओडीसी) के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, एसएनए 2008 के अनुरूप तथा पहले के एफओएफ खातों से भिन्न, क्षेत्र के अंदर होने वाले लेनदेन को विभिन्न क्षेत्रों के, यथा लागू, निधियों के स्रोत और उपयोग के तहत शामिल किया गया है।

² एसएनए, 2008, अध्याय 4, संस्थागत इकाइयां और क्षेत्र।

³ सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-विभागीय गैर-वित्तीय उद्यमों, राज्य ऊर्जा अनुप्रयोग एवं बंदरगाह न्यासां को शामिल किया गया है।

⁴ निजी गैर-वित्तीय निगमों से तात्पर्य सार्वजनिक और निजी लिमिटेड गैर-वित्तीय कंपनियों -दोनों से है।

⁵ स्थानीय निकायों और स्वायत्तशासी संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय लिखतों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं - मुद्रा, जमाराशियां, कर्ज प्रतिभूतियां, ऋण एवं उधारियां, इक्विटी निवेश फंड (यथा म्यूचुअल फंड), बीमा, पेंशन एवं भविष्य निधियां, मौद्रिक स्वर्ण, अन्य लेखे (व्यापार कर्ज सहित) तथा अन्य देयताएं/आस्तियां, जो कहीं और वर्गीकृत नहीं की गई हों (अन्य एन.ई.सी.)।

शेष लेख को पांच खंडों में प्रस्तुत किया गया है। खंड II में विभिन्न सभी क्षेत्रों के बीच वित्तीय संसाधन अंतरालों को दर्शाया गया है। खंड III में क्षेत्र-वार एवं लिखत-वार निधि प्रवाह में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। खंड IV में लिखत-वार वित्तीय प्रवाहों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। वित्तीय विकास के चुनिंदा सूचकों को खंड V में दर्शाया गया है तथा उन पर विचार-विमर्श किया गया है। समापक प्रेक्षणों को खंड VI में दर्शाया गया है।

II. क्षेत्रगत वित्तीय संसाधन अंतराल

भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी) एवं सामान्य सरकारी (जीजी) क्षेत्र घाटे वाले प्रमुख क्षेत्र को निर्मित करते हैं जबकि वित्तीय निगम (एफसी) एवं हाउसहोल्ड क्षेत्र (एचएच) अतिरेक वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। वर्तमान बाजार मूल्यों के स्तर पर निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) के अनुपात के रूप में अर्थव्यवस्था का समग्र वित्तीय संसाधन संतुलन - वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से देयताओं में निवल वृद्धि को घटाकर माप की गई - 2014-15 के मामूली अधिशेष जोन से 2015-16 में और अधिक अधिशेष जोन में चला गया। यह 2013-14 में घाटे में रहने के विपरीत है। इस सुधार का प्राथमिक कारण गैर-वित्तीय निगमों की निवल उधारियों में कमी तथा हाउसहोल्ड क्षेत्र से निवल उधार देने में हुए निरंतर सुधार रहे, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो भौतिक आस्तियों से वित्तीय आस्तियों में परिवर्तित हो गए, हालांकि यह परिवर्तन मामूली रहा (सारणी 1)। जहां, एनएफसी ने उनकी बचत में वृद्धि की जिससे अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में गिरावट के कारण निविष्टि लागत अपेक्षाकृत कम होने से उनको लाभ हुआ, वहीं वित्तीय निगमों के निवल ऋण प्रदान में कमी आई, जिसका कारण आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के बढ़ जाने से वाणिज्य बैंकों एवं गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत कम होना रहा। राज्यों के स्तर पर गिरावट आने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढीकरण किए जाने के कारण सामान्य सरकारी क्षेत्र के संसाधन अंतराल में थोड़ी कमी आई।

सारणी 1 : क्षेत्रगत वित्तीय संसाधन संतुलन (वर्तमान बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय आय या एनएनआई का प्रतिशत)

घटक	2013-14	2014-15	2015-16
1 गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी)	-6.4	-5.1	-4.6
क. सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगम (पीयूएनएफसी)	-2.6	-2.4	-2.9
ख. निजी गैर-वित्तीय निगम (पीवीएनएफसी)	-3.8	-2.7	-1.7
2 वित्तीय निगम (एफसी)	2.6	2.5	1.8
3 सामान्य सरकार (जीजी)	-5.8	-5.7	-5.5
4 हाउसहोल्ड क्षेत्र (एचएच)	8.4	8.4	9.0
5 कुल (1+2+3+4)	-1.2	0.1	0.7

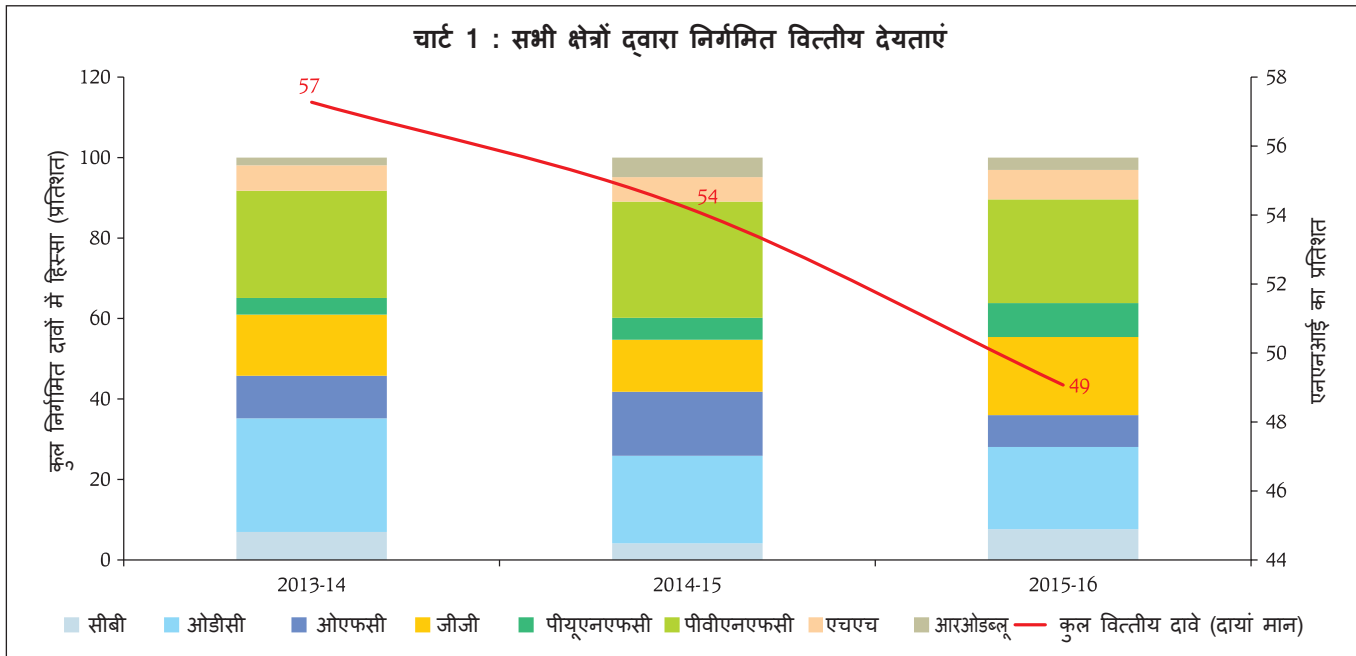
III. वित्तीय प्रवाहों⁶ में क्षेत्रीय परिवर्तन

इस खंड में, घाटे वाले क्षेत्रों, नामतः, एनएफसी एवं जीजी की ओर होने वाले वित्तीय प्रवाहों में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ने वाले असर को दर्शाया गया है, उसके बाद अधिशेष वाले क्षेत्रों, नामतः एफसी और एचएच⁷ से होने वाले प्रवाहों का विश्लेषण किया गया है। सभी क्षेत्रों (आरओडब्लू क्षेत्र सहित) द्वारा वित्तीय देयताओं के कुल अधिग्रहण में 2013-14 से 2015-16 तक निरंतर गिरावट आई (चार्ट 1)।

वित्तीय निगमों की वित्तीय देयताएं 2013-14 में एनएन1 का 26.2 प्रतिशत थीं जो 2014-15 में घटकर 22.7 प्रतिशत रह गई तथा 2015-16 में और अधिक गिरावट के साथ यह 17.7 प्रतिशत रह गई। इस गिरावट का कारण अन्य जमा स्वीकार करने वाले निगमों (ओडीसी) तथा अन्य वित्तीय निगमों (ओएफसी) द्वारा अपेक्षाकृत कम संसाधन जुटाया जाना रहा। दूसरी तरफ, एचएच द्वारा वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण में वृद्धि हुई, जिससे वित्तीय परिस्थितियों में सुधार का संकेत मिलता है।

⁶ वित्तीय आस्तियों और देयताओं का संदर्भ प्रवाह के अनुसार अर्थात् वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण में परिवर्तन एवं देयताओं में परिवर्तन के अनुसार दिया गया है।

⁷ विवरण की सुविधा की दृष्टि से, घरेलू गैर-वित्तीय क्षेत्रों, नामतः निजी गैर-वित्तीय निगमों (पीवीएनएफसी), सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों (पीयूएनएफसी), सामान्य सरकारी एवं हाउसहोल्ड क्षेत्रों से संबंधित विश्लेषण उनके वित्तीय संसाधन अंतरालों के आधार पर तैयार किया गया है, जबकि आरओडब्लू एवं घरेलू वित्तीय क्षेत्र, नामतः केंद्रीय बैंक, जमा स्वीकार करने वाले अन्य निगमों (ओडीसी) एवं अन्य वित्तीय निगमों (ओएफसी) से संबंधित विमर्श में वित्तीय स्रोतों और उनके अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



III.1 गैर-वित्तीय निगम

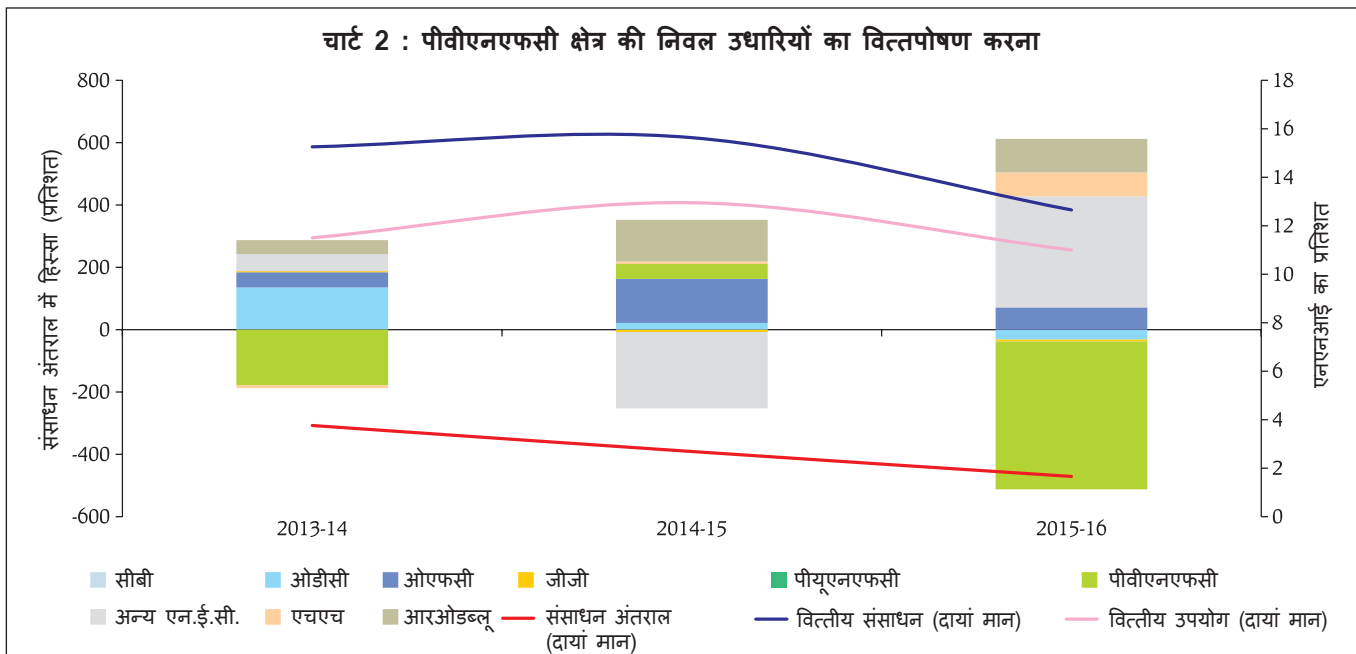
2015-16 में, कुल देयताओं में एनएफसी की वित्तीय देयताओं का हिस्सा लगभग 34.2 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रहा।

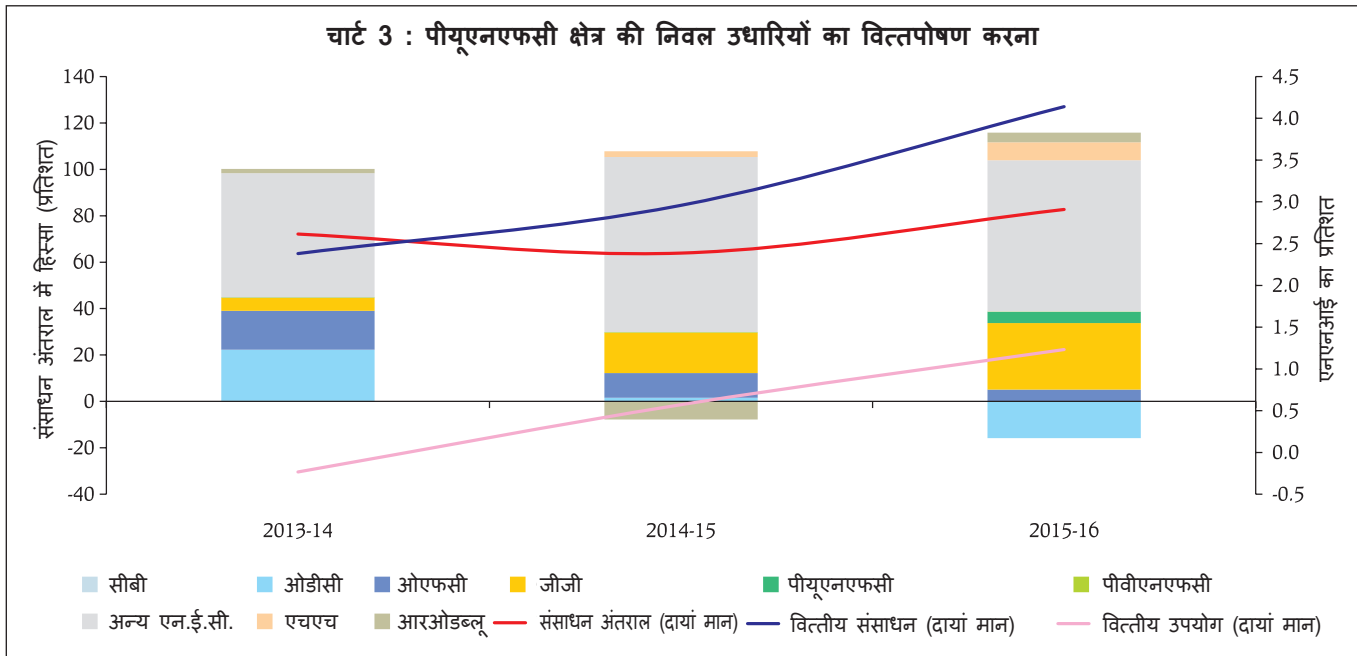
III.1.क निजी गैर-वित्तीय निगम

2015-16 में वैश्विक पण्य मूल्यों में मंदी होने का फायदा निजी गैर-वित्तीय निगमों के परिचालनों को मिलना

जारी रहा। बिक्री वृद्धि में होने वाली गिरावट को कच्चे माल एवं घटकों पर होने वाले व्यय में कमी के माध्यम से प्रभावी होने से रोका गया। परिणामस्वरूप, उनके परिचालनगत लाभों में तेजी से वृद्धि हुई तथा संसाधन अंतराल में एक वर्ष पहले की तुलना में और अधिक कमी आई (चार्ट 2 एवं विवरण 2.2)।

निजी गैर-वित्तीय निगमों के वित्तपोषण में बैंकों की घटती भूमिका से दोहरे तुलन-पत्र - कॉर्पोरेट और बैंकों के तुलन-पत्रों, की समस्या का पता चलता है। ओडीसी द्वारा तैयार





किए गए अंतर को अन्य अंतर-क्षेत्र प्रवाहों के माध्यम से पूरा किया गया। इसके अलावा, आरओडब्लू की भूमिका भी घटी, जो भारतीय कॉर्पोरेटों से संबंधित बढ़ी हुई जोखिम अनुभूतियों के विषय में निजी गैर-वित्तीय निगमों के परिचालनों में बाह्य वित्तीयन की घटी हुई भूमिका को इंगित करता है।

जहां तक वित्तीय आस्तियों का संबंध है, निजी गैर-वित्तीय निगमों से इक्विटी के प्रवाह में हुई वृद्धि लाभप्रदता में सुधार होने के चलते बनी रही। इसके कारण अन्य गैर-वित्तीय फर्मों में अधिक निवेश हो सकता था, किंतु इनमें निवेश की मांग पिछले वर्ष की तुलना में कम रही।

III.1.ख सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगम⁸

धारित लाभ अपेक्षाकृत कम होने के कारण सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों का वित्तीय संसाधन अंतराल बढ़ा क्योंकि इन संस्थाओं के निवल राजस्व में गिरावट जारी रही। इसके प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए, 2015-16 में पूंजीगत व्यय में कमी होने के बावजूद, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की समग्र उधारी में वृद्धि हुई - जो राजस्व व्यय के अपेक्षाकृत अधिक वित्तपोषण की जरूरत को दर्शाता है (चार्ट 3 एवं विवरण 2.1)।

⁸ 2015-16 के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 244 में से 223 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के परिचालनरत उद्यमों का संबंध गैर-वित्तीय गतिविधियों से रहा। निधियों के प्रवाह से संबंधित आंकड़े एकत्र करने में सर्वेक्षण में उपलब्ध कराई गई सूचना के अलावा, 51 राज्य ऊर्जा जनोपयोगी सेवाओं और 9 बंदरगाह न्यासों से अलग से प्राप्त हुई तुलन-पत्र से संबंधित सूचनाओं का भी प्रयोग किया गया।

III.2 सामान्य सरकारी (जीजी)

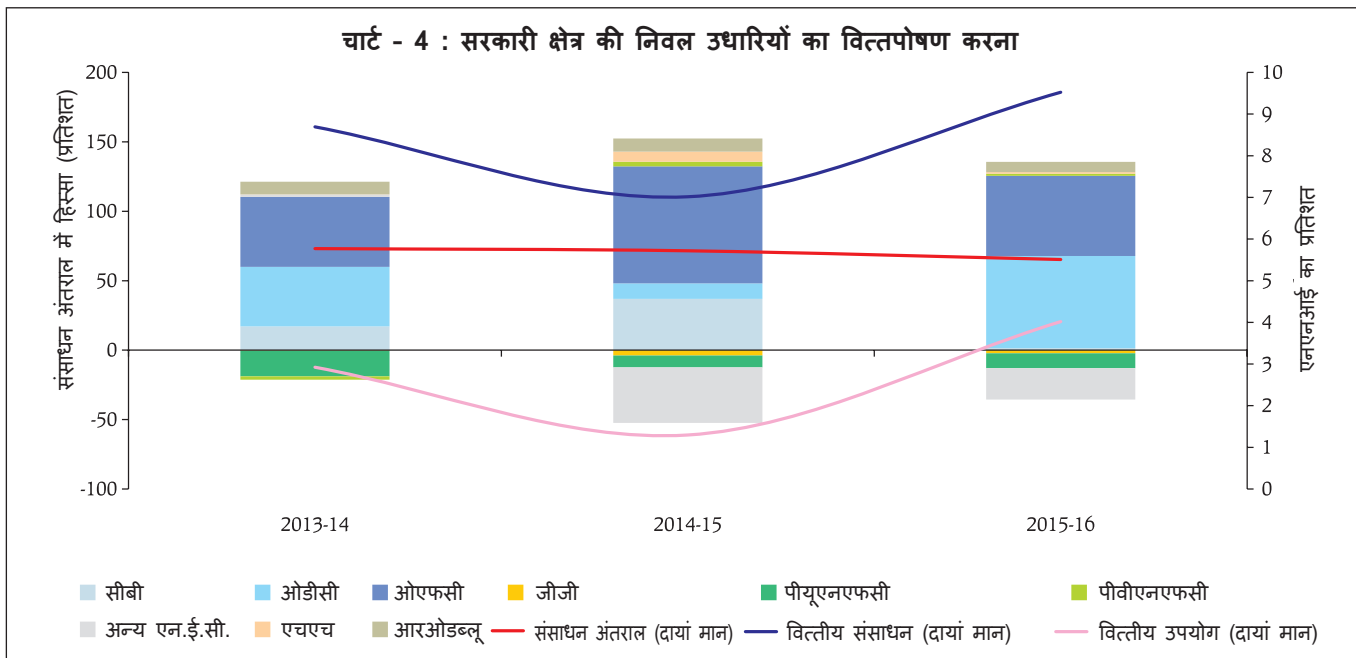
जीजी क्षेत्र के वित्तीय संसाधन अंतराल से 2015-16 में राज्य सरकारों के वित्त में महत्वपूर्ण गिरावट का पता चलता है। राज्यों के समेकित सकल राजकोषीय घाटों में बजट प्रावधान के स्तर की तुलना में कमी आई। इसका कारण पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि होने के साथ ही ऊर्जा परियोजनाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम (2015-16 के दौरान आठ राज्यों ने उज्ज्वल डीआईएससीओएम एथयोरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत लगभग ₹990 बिलियन राशि उधार ली)⁹ रहे (चार्ट 4 एवं विवरण 3)।

वित्त पोषण की दृष्टि से, ओडीसी ने जीजी क्षेत्र को बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए। इसके बाद ओएफसी की बारी रही, जिन्होंने प्राथमिक रूप से कर्ज प्रतिभूतियों के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराए। हालांकि, केंद्रीय बैंक के योगदान में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे अर्थापय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के अपेक्षाकृत कम होने और बाजार से उधार लेने के अपेक्षाकृत अधिक होने का पता चलता है।

III.3 शेष विश्व (आरओडब्लू)

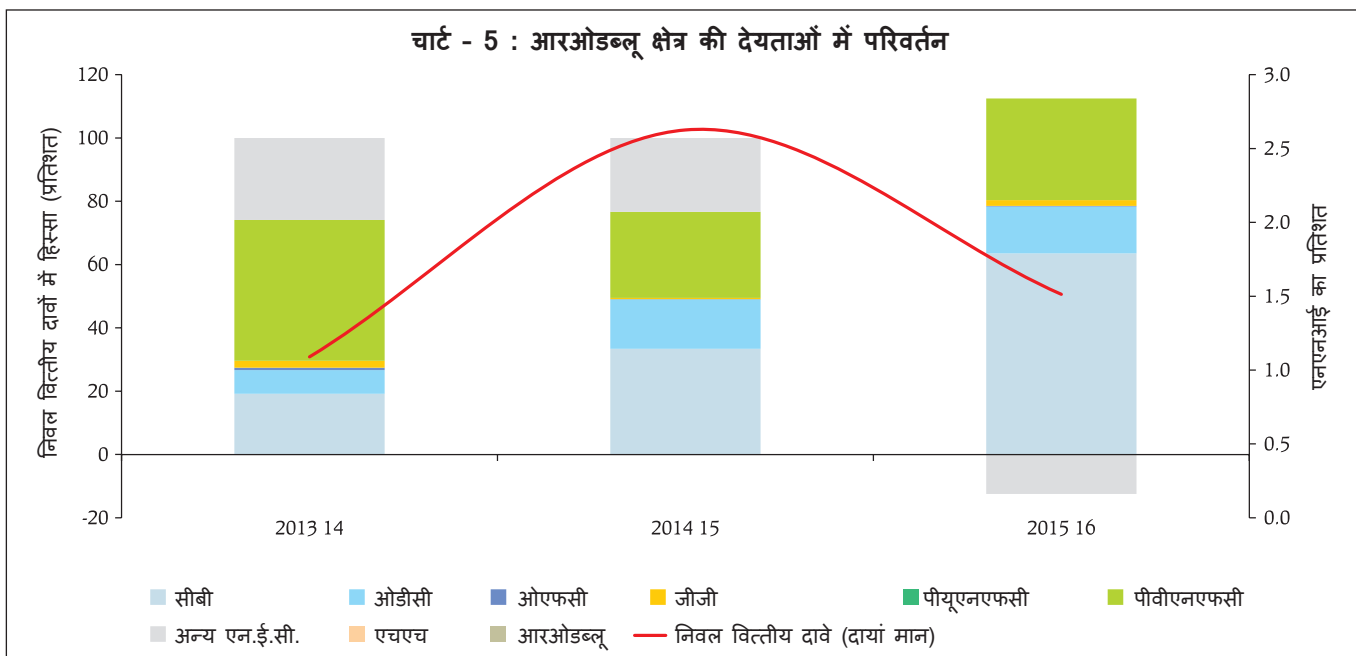
वित्तीय देयताओं और आस्तियों का शेष विश्व क्षेत्र द्वारा अधिग्रहण किए जाने की दशा का निर्धारण विविध प्रकार

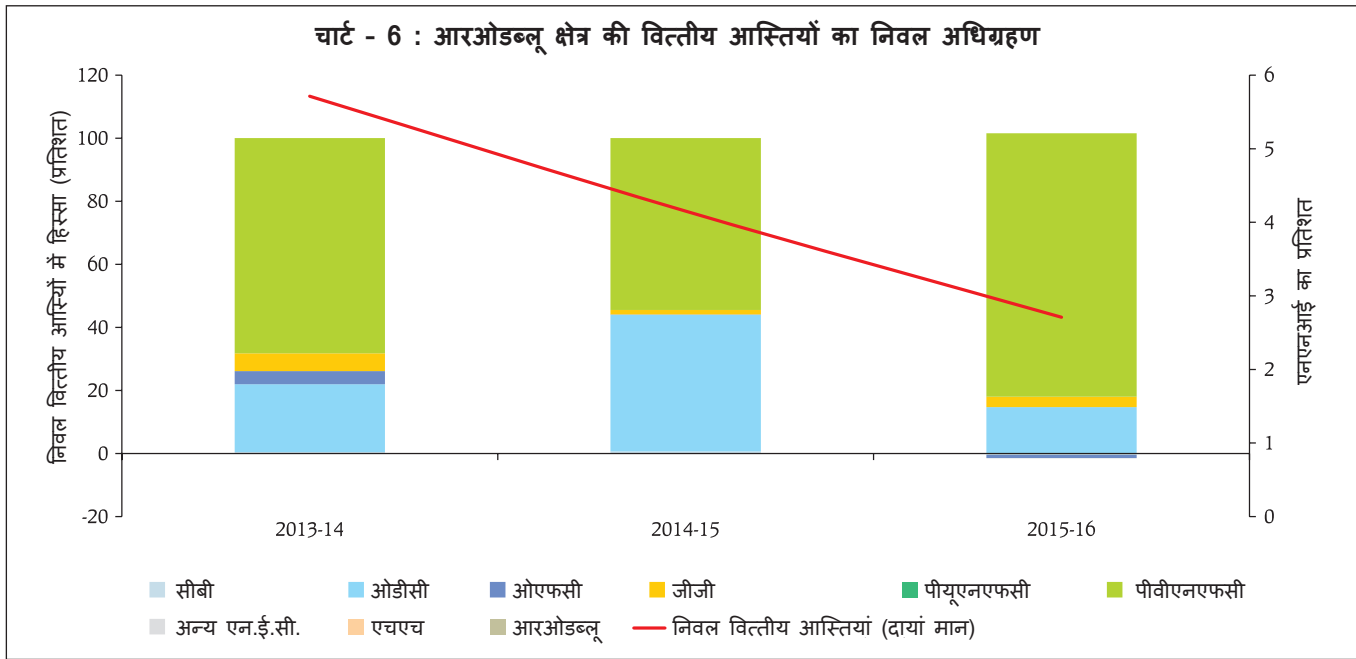
⁹ उदय (यूडीएवाई) योजना के अनुसार, 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार ऊर्जा वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम) के कर्ज के 75 प्रतिशत हिस्से का भार राज्य सरकारें उठाएंगी, जिसका वितरण दो वर्षों में इस प्रकार होगा-2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 50 प्रतिशत।



के खींच-तान पूर्ण कारकों से हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विविधतापूर्ण मौद्रिक नीतियों, चीन और अन्य उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) तथा वैश्विक वसूली से संबंधित अनिश्चितताएं बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक (पुश फैक्टर) थे। मजबूत घरेलू समष्टिगत आधारभूत संरचनाएं, सन्नहित समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से संबंधित मानकों को आसान बनाया जाना पीछे ले जाने वाले प्रमुख कारक (पुल फैक्टर) थे। 2015-16 के

दौरान, शेष विश्व क्षेत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाला निवल प्रवाह और अधिक कम हुआ। इसका कारण एफडीआई के वर्धित अंतर्वाह के बावजूद कर्ज और इक्विटी -दोनों में पोर्टफोलिया अंतर्वाह होना रहा। 2015-16 में पीवीएनएफसी को प्राप्त होने वाले निवल बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) में भी कमी आई क्योंकि डीलिवरेजिंग की प्रक्रिया में कॉर्पोरेटों ने बड़ी लागत वाली विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारियों का पुनर्भुगतान कर दिया (चार्ट 5 एवं विवरण 5)।

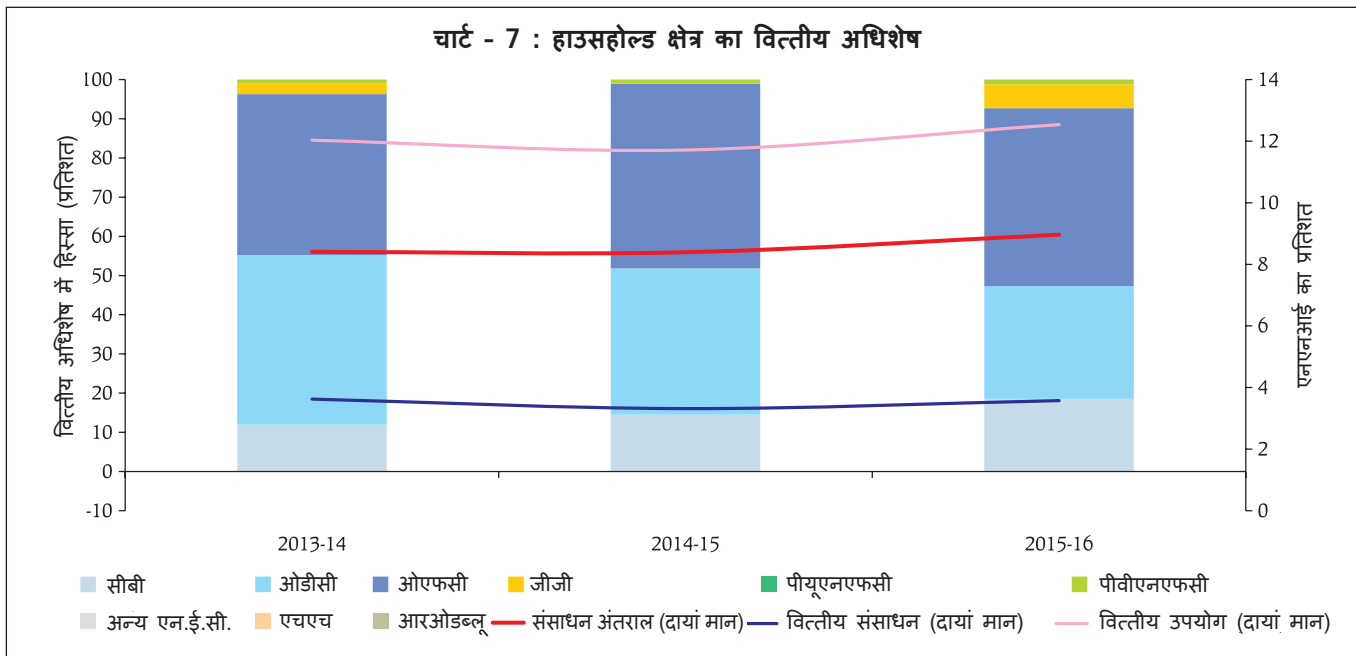




शेष विश्व क्षेत्र द्वारा निवल वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण में गिरावट होने के बावजूद 2015-16 के दौरान भारत की बाह्य वित्तपोषण करने संबंधी आवश्यकताओं को सहजतापूर्वक पूरा करने के लिए यह काफी रहा (चार्ट 6)। समग्ररूप से, एनएफसी और जीजी में शेष विश्व क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि हुई, जबकि ओडीसी में उनकी जमाराशियों में गिरावट आई।

III.4 हाउसहोल्ड क्षेत्र

2015-16 में हाउसहोल्ड क्षेत्र के वित्तीय अधिशेष में और अधिक वृद्धि हुई (चार्ट 7 एवं विवरण 4)। हाउसहोल्ड निधियों (मुख्य रूप से वाणिज्य बैंक जमाराशि) के प्रयोग में ओडीसी के हिस्से में बैंक जमा दरों में गिरावट आने और मुद्रा आस्तियों की अधिक मांग होने के कारण कमी आई। ओएफसी में धारित



हाउसहोल्ड आस्तियों में काफी वृद्धि हुई, जिससे हाउसहोल्ड निवेश का जीवन बीमा, सेवानिवृत्ति निधियों तथा म्यूचुअल फंडों में विविधीकरण होने का पता चलता है। हालांकि, पूर्व की भांति, हाउसहोल्ड की एकमुश्त देयताओं की देनदारी ओडीसी के प्रति रही।

III.5 वित्तीय निगम (एफसी)

भारतीय वित्तीय प्रणाली की अधिशेष-युक्त इकाइयों से कमी वाली इकाइयों में संसाधनों के प्रवाह की सुविधा उपलब्ध कराने में वित्तीय निगमों (एफसी) की प्रमुख भूमिका रही। भारतीय वित्तीय प्रणाली की बढ़ती विविधता, जो अभी तक व्यापक रूप से बैंक आधारित रही है, के साथ वित्तीय निगमों की वित्तीय देयताओं में कमी का दौर रहा है।

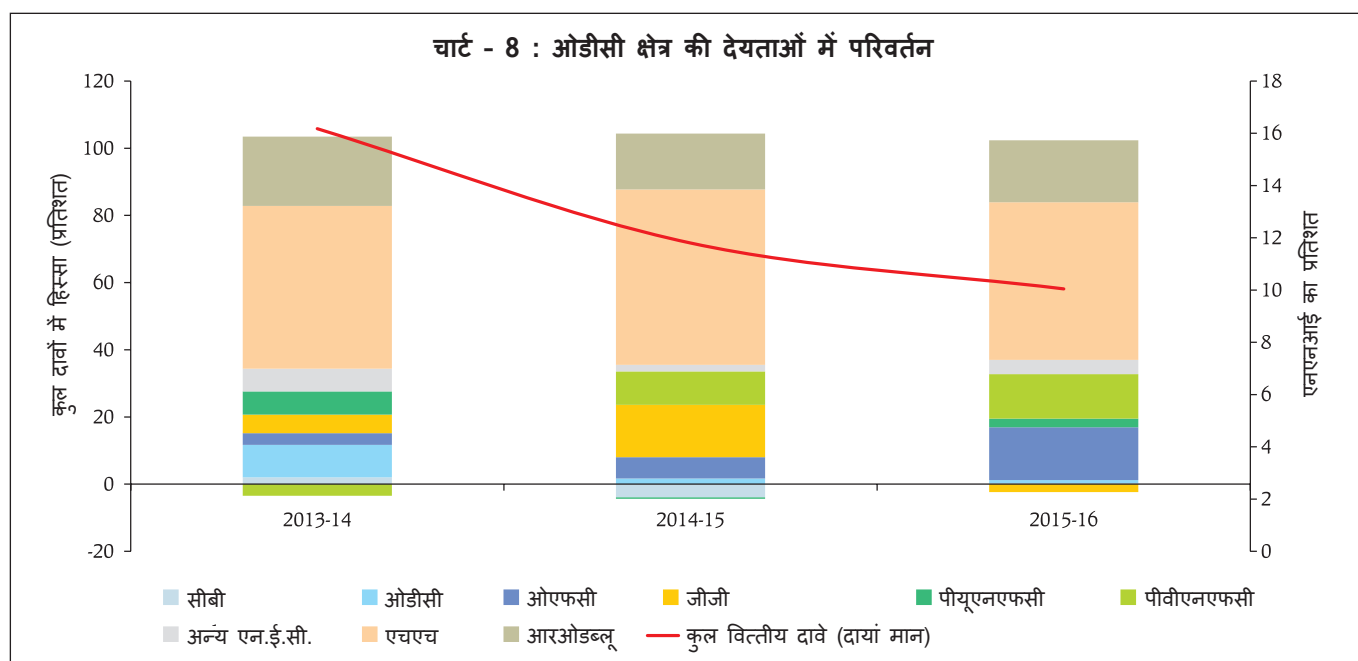
III.5.क निक्षेपी निगम : केंद्रीय बैंक

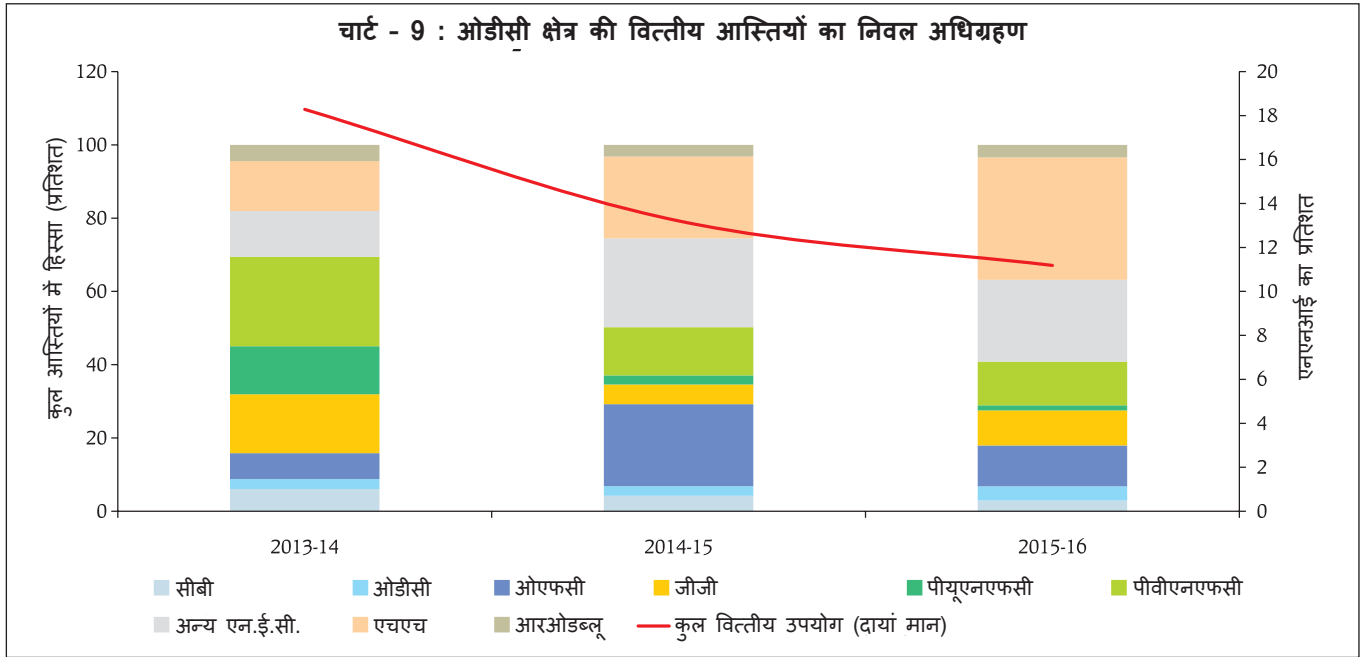
2015-16 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय देयताओं में काफी इज़ाफा हुआ, जिसका कारण हाउसहोल्ड क्षेत्र द्वारा मुद्रा की व्यापक मांग होना था। रिज़र्व बैंक के पास अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशि तथा 'अन्य देयताएं और प्रावधान' का भी इस वृद्धि में योगदान रहा। अन्य देयताओं में हुई वृद्धि मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता (सीजीआरए) में हुई वृद्धि के कारण थी।

वित्तीय आस्तियों के पक्ष में, कर्ज प्रतिभूतियों में निवेशित विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि हुई, जिसके तहत विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जमा हुई। केंद्र सरकारी की कर्ज प्रतिभूतियों में रिज़र्व बैंक के निवेश में काफी वृद्धि हुई, जिससे पूंजी के अधिक अंतर्वाह के संदर्भ में स्टेरिलाइजेशन परिचालनों का उपाय मिल गया।

III.5.ख अन्य निक्षेपी निगम (ओडीसी)

2015-16 के दौरान ओडीसी की कुल देयताओं में घटक-वार परिवर्तन देखे गए (चार्ट 8 एवं विवरण 1.2)। महत्व की दृष्टि से जमाराशियों की भूमिका कम हुई क्योंकि हाउसहोल्ड से होने वाला प्रवाह स्थिर रहा और जीजी क्षेत्र की जमा राशि में कमी आई, जबकि ओएफसी से लिए जाने वाले ऋणों में काफी वृद्धि हुई। 2015-16 में एनएफसी क्षेत्र की जमा राशि में और अधिक वृद्धि हुई, जो संसाधन से जुड़े दबावों में कमी का द्योतक है। संघ सरकार द्वारा पूंजी डाले जाने और बासेल पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा पूंजी उगाही किए जाने के कारण ओडीसी की इक्विटी देयताओं में भी वृद्धि हुई।

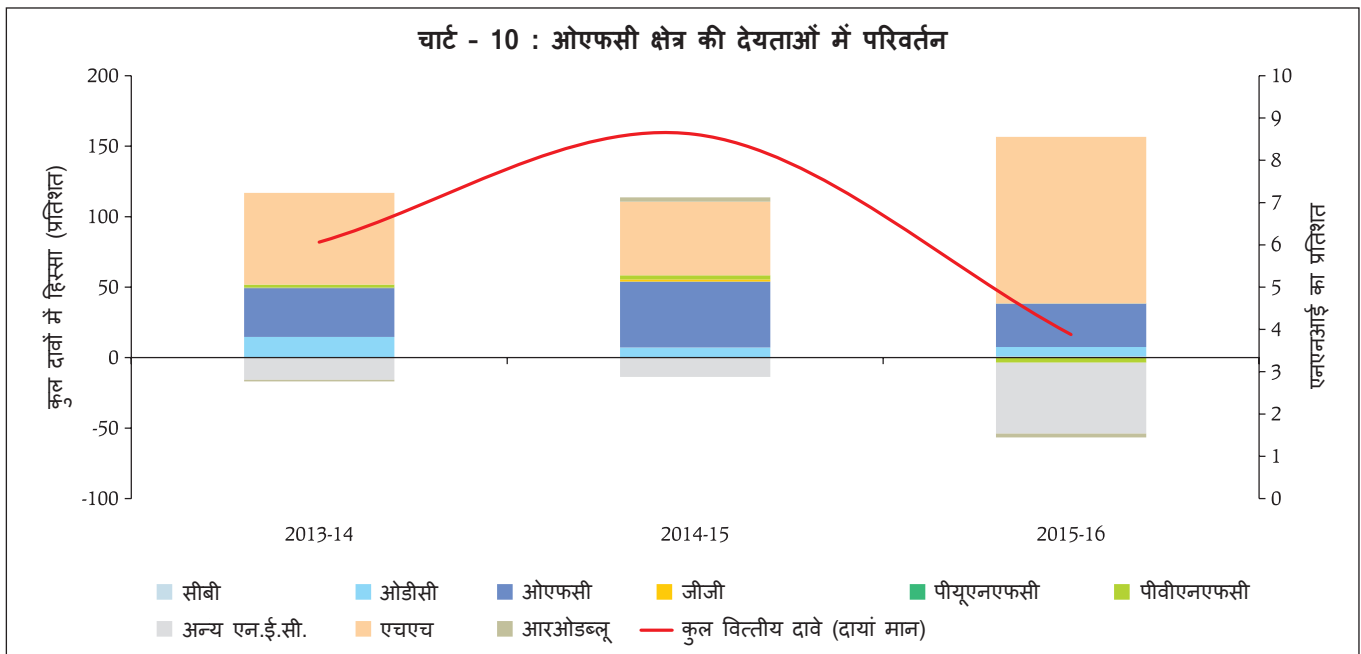


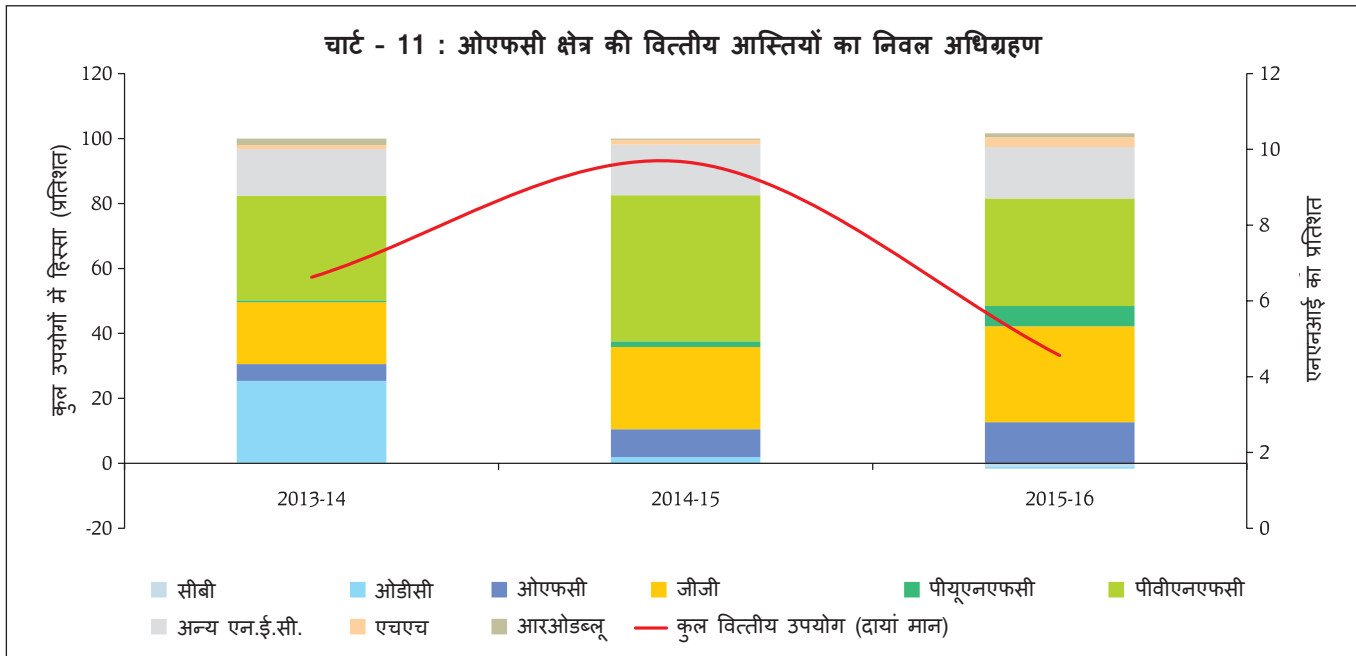


2015-16 के दौरान ओडीसी की वित्तीय आस्तियों में कमी आई, जिसका कारण हाउसहोल्ड एवं हाउसहोल्ड को सेवा प्रदान करने वाले गैर-लाभ संस्थानों (एनपीआईएसएच) को प्राप्त होने वाले ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद, सामान्यतः एनएफसी और ओएफसी को दिए जाने वाले ऋण में मंदी होना था (चार्ट 9)। ओडीसी क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों की संरचना भी कर्ज प्रतिभूतियों के पक्ष में रही, जो आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के कारण जोखिम टालने को दर्शाता है।

III.5.ग अन्य वित्तीय निगम (ओएफसी)

2015-16 में, जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी की देयताओं में कमी होने, म्यूचुअल फंड के प्रबंध के अधीन आस्तियों में कमी होने और बीमा कंपनियों के निवेशों के लाभ के अपेक्षाकृत कम होने के कारण ओएफसी की वित्तीय देयताओं में गिरावट आई (चार्ट 10 एवं विवरण 1.3)। एक अनूठी विशेषता यह है कि ओएफसी की देयताओं का अधिकांश हिस्सा क्षेत्रांतर्गत रहा, जिसकी उगाही बीमा, भविष्य निधि





और पेंशन निधियों तथा म्यूचुअल फंड इकाइयों के माध्यम से हाउसहोल्ड क्षेत्र से प्रभावी ढंग से की जाती है।

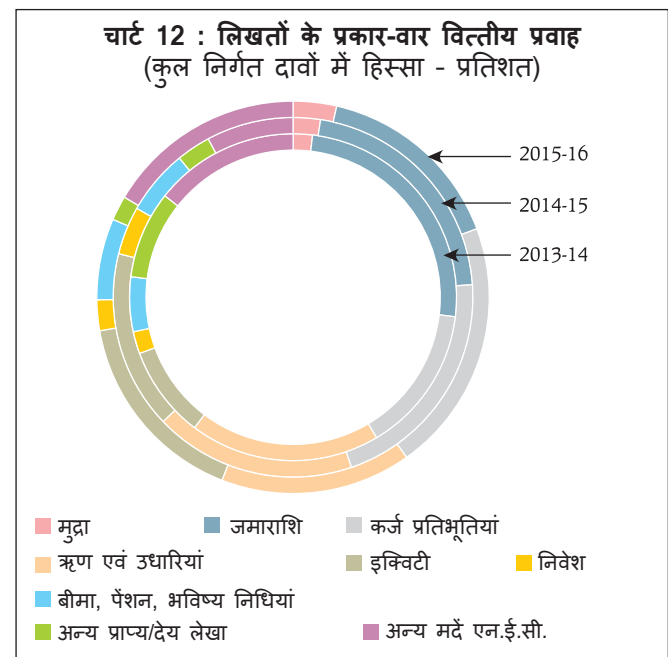
देयताओं के अनुरूप, ओएफसी क्षेत्र द्वारा वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण में बहुत अधिक गिरावट आई, और सरकारी बॉण्डों में निवेश किए जाने के बावजूद गैर वित्तीय निगमों द्वारा वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण में आश्चर्यजनक ढंग से गिरावट हुई। इससे, बाजार आधारित मूल्य वाले म्यूचुअल फंडों तथा बीमा कंपनियों को हानि होने एवं आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं को ऋण देने में एनबीएफसी द्वारा अपनाए गए सावधानीपूर्ण उपागम का पता चलता है (चाट 11)।

IV. लिखतों के माध्यम से वित्तीय प्रवाह

2015-16 में लिखत-वार निधि प्रवाह में संरचनागत परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे गए। मुद्रा और जमाराशियां, जो ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले वित्तीय लिखत रहे हैं, कर्ज प्रतिभूतियां द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गईं। वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के संदर्भ में, लिखतों की संरचना में काफी परिवर्तन आया, जिसके तहत इक्विटी लिखतों में काफी परिवर्तन आया जिसके अंतर्गत इक्विटी लिखत सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले लिखत बन गए। इनके बाद ऋणों एवं उधारियों का स्थान रहा (चाट 12 एवं विवरण 7)।

V. वित्तीय विकास के चुनिंदा सूचक

अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली की भूमिका की माप मुद्रों पर आधारित व्यावहारिक अनुपातों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा वित्तीय देयताओं की स्वीकृति के आधार पर किया जा सकता है क्योंकि वे एक दूसरे से उधार लेते-देते हैं। एकात्मक परिदृश्य में, ये अनुपात वित्तीय विकास तथा



समग्र आर्थिक वृद्धि के बीच संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

वित्त अनुपात, जो राष्ट्रीय आय की तुलना में कुल वित्तीय देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, 2014-15 के 0.54 के स्तर से लुढ़क कर 2015-16 में 0.49 के स्तर पर चला गया। इससे, अर्थव्यवस्था में वित्तीय गहनता की गति में थोड़ी मंदी का पता चलता है जिसका मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र द्वारा अपेक्षाकृत कम संसाधन जुटाया जाने को माना जा सकता है (सारणी 2)। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाना चाहिए कि पीवीएनएफसी के संबंध में यह मालूम पड़ता है कि बाह्य वित्त की भूमिका में कमी आई, और क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहों की भूमिका बढ़ी है।

मध्यस्थता अनुपात से वित्तीय क्षेत्र पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता का पता चलता है। गैर-वित्तीय क्षेत्र द्वारा जारी देयताओं (प्राथमिक निर्गम) की तुलना में वित्तीय क्षेत्र की देयताओं (या प्राथमिक निर्गम) के अनुपात के रूप में मापे जाने वाले इस अनुपात में तेजी से गिरावट आई और 2015-16 में यह 0.56 के स्तर पर पहुंच गया जो 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 0.72 और 0.84 के स्तर पर था। वित्त अनुपात की व्याख्या करने में यह भी एक कारक हो सकता है।

वित्तीय अंतर-संबंध अनुपात वित्तीय विकास और भौतिक निवेश वृद्धि के बीच संबंध की जानकारी देता है।

सारणी 2 : वित्तीय गतिविधियों के चुनिंदा सूचक : 2013-14 से 2015-16

(राशि ₹ बिलियन में)

	2013-14	2014-15	2015-16
1. द्वितीयक निर्गम #	25,956	24,811	21,333
2. प्राथमिक निर्गम ##	30,728	34,563	37,928
2.1 घरेलू क्षेत्र	29,650	31,688	36,101
2.2 शेष विश्व	1,078	2,875	1,827
3. कुल निर्गम (1+2)	56,684	59,374	59,261
4. निवल घरेलू पूंजी निर्माण @	25,940	29,331	31,130
5. राष्ट्रीय आय @	98,977	1,09,538	1,20,769
6. वित्त अनुपात (3 से 5 के अनुपात)	0.57	0.54	0.49
7. वित्तीय अंतर्निर्भरता अनुपात (3 से 4 के अनुपात)	2.19	2.02	1.90
8. नवीन निर्गम अनुपात (2 से 4 के अनुपात)	1.18	1.18	1.22
9. मध्यस्थता अनुपात (1 से 2 के अनुपात)	0.84	0.72	0.56

वित्तीय मध्यस्थों अर्थात् (ओडीसी एवं ओएफसी) द्वारा निर्गम के संदर्भ में है।

वित्तीय मध्यस्थों के अलावा सभी क्षेत्रों द्वारा निर्गम के संदर्भ में है।

@ वर्तमान मूल्यों पर।

निवल घरेलू पूंजी निर्माण की तुलना में कुल वित्तीय देयताओं के रूप में परिभाषित यह अनुपात घटकर 2015-16 में 1.9 के स्तर पर पहुंच गया जो 2014-15 में 2.0 और 2013-14 में 2.2 के स्तर पर था। संभवतः यह गैर-वित्तीय क्षेत्र की ओर से निविष्टि लागत के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रहने के कारण हुआ। निवल घरेलू पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में नवीन निर्गम अनुपात-प्राथमिक निर्गम में देखी गई तेजी भी एक वर्ष पूर्व की तुलना में 2015-16 में प्राथमिक निर्गम में हुई वृद्धि को दर्शाती है।

VI. समापन

2015-16 से संबंधित निधि प्रवाह लेखे (एफओएफ) से भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीयन के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण खास-खास बातों में से कुछ यहां नीचे प्रस्तुत हैं -

- पूरी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था में समग्र वित्तीय देयताओं में कमी से ओडीसी एवं एनएफसी क्षेत्र के तुलन पत्रों में बढ़े हुए दबाव का पता चलता है।
- आरओडब्लू क्षेत्र से निवल वित्तीय प्रवाह में कमी से भी घरेलू मांग परिस्थितियों के धीमे होने का पता चलता है।
- वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के सर्वाधिक प्रमुखता वाले लिखत के रूप में कर्ज प्रतिभूति का उदय हुआ, जबकि वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के मामले में इक्विटी सर्वाधिक पसंदीदा लिखत बनीं।
- वित्तीय क्षेत्र में, 2015-16 के दौरान ओडीसी की देयताएं घटीं, जिनका मुख्य कारण समग्र जमाराशि का अपेक्षाकृत कम रहना था, जबकि ओएफसी में कमी मुख्य रूप से मूल्यन में हुए परिवर्तनों के कारण हुई।
- गैर-वित्तीय निगमों के संबंध में, पीवीएनएफसी के संसाधन घाटे में गिरावट जारी रही, जिसे वैश्विक पण्य मूल्यों में निरंतर कमी होने का फायदा मिला। इसके विपरीत, पीयूएनएफसी का संसाधन अंतराल बढ़ा, जिसका मुख्य कारण राजस्व में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होना रहा। इसके अलावा, पीवीएनएफसी के परिचालनगत लाभ में भी काफी वृद्धि हुई।

- आरओडब्लू क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने के बावजूद इस क्षेत्र का पीवीएनएफसी के वित्तीयन का प्रमुख योगदान रहा।
- जहां तक हाउसहोल्ड का संबंध है, उनके वित्तीय अधिशेषों में वृद्धि 2015-16 में भी जारी रही, जिसके तहत बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जमाराशियों पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दर के अपेक्षाकृत कम रहने के कारण इनका झुकाव ओएफसी की तरफ रहा। हालांकि, ऋण के उद्देश्यों से हाउसहोल्ड की निर्भरता ओडीसी पर बड़ी।

2015-16 के दौरान, वित्तीय प्रवाहों की प्रवृत्ति से वित्तीय गतिविधियों की अवस्था और भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय वित्तीय प्रवाहों में हाउसहोल्ड अधिशेष की प्रमुख भूमिका बनी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली रही है और अब इसमें विविधता आ रही है, इसलिए इसमें कमजोर निवेश, विशेषरूप से निजी क्षेत्र में, को सहारा प्रदान करने के लिए वित्तीय बाजार के आकार, गहनता और चलनिधि में वृद्धि की आवश्यकता है किंतु वृद्धि के भले चक्र को गतिमान रखने के लिए इन पर अधिक दबाव नहीं डाला जा सकता।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खजाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक भारतीय रिज़र्व बैंक	37
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	38
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	39
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डालर का क्रय/विक्रय	40
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	41
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं मुद्रा और बैंकिंग	41
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	42
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	43
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	44
9	चलनिधि समुच्चय	44
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	45
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	45
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	46
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	46
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	47
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	48
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन	49
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक मूल्य और उत्पादन	50
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	51
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	51
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	51
21	थोक मूल्य सूचकांक	52
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100) सरकारी खाते और खज़ाना बिल	55
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	55
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	56
25	खज़ाना बिलों की नीलामी वित्तीय बाजार	56
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	57
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	58
28	वाणिज्यिक पत्र	58
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	58
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	59

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	60
32	विदेशी मुद्रा भंडार	60
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	60
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	61
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	61
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक	62
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	62
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	63
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	64
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	65
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹)	66
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	67
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	68
	प्रासंगिक शृंखला	
44	लघु बचत	
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
 - = शून्य/नगण्य
 प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2016-17	2015-16		2016-17	
		ति3	ति4	ति3	ति4
		1	2	3	4
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.3	8.7	6.7	5.6
1.1.1 कृषि	4.9	-2.1	1.5	6.9	5.2
1.1.2 उद्योग	7.0	12.0	11.9	7.2	5.5
1.1.3 सेवाएं	6.7	9.0	9.4	6.4	5.7
1.1क अंतिम खपत व्यय	10.5	5.8	10.6	12.5	10.2
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	2.4	7.0	3.9	1.7	-2.1
	2016-17	2016		2017	
		मई	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.0	8.0	8.9	1.7	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमा राशियां	11.3	8.9	9.1	10.4	13.3
2.1.2 ऋण	4.5	9.4	9.0	4.7	8.6
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.2	9.6	9.3	5.5	9.4
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	17.4	4.7	5.6	17.6	18.6
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	-12.9	12.5	14.3	-8.7	-7.1
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.6	9.9	10.3	7.0	7.4
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	20.50	21.25	21.25	20.50	20.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.3	4.7	4.8	4.7	-
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.9	76.0	75.7	72.1	72.6
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	41.4	-12.4	-10.0	105.4	17.8
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.2	28.7	28.8	30.6	30.1
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	28.4	57.1	55.8	-69.9	394.9
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.50	6.50	6.25	6.25
4.2 रिवर्स रिपो दर	5.75	6.00	6.00	6.00	6.00
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.75	7.00	7.00	6.50	6.50
4.4 बैंक दर	6.75	7.00	7.00	6.50	6.50
4.5 आधार दर	9.25/9.60	9.30/9.70	9.30/9.70	9.10/9.60	9.10/9.60
4.6 एमसीएलआर	7.75/8.20	8.90/9.15	8.9/9.2	7.8/8.1	7.8/8.1
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.50/7.00	7.0/7.5	7.0/7.6	6.3/6.9	6.3/6.9
4.8 बचत जमा दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.97	6.42	6.33	6.04	6.07
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.82	6.85	6.73	6.31	6.27
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.05	6.95	6.82	6.39	6.33
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.14	6.96	6.90	6.47	6.38
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय	7.08	7.48	7.51	6.69	6.57
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	64.84	67.06	68.01	64.59	64.74
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.25	75.09	75.10	72.33	74.00
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमरीकी डालर 1-माह (%)	5.09	6.35	6.35	4.92	5.19
3-माह (%)	4.97	6.44	6.32	4.83	4.76
6-माह (%)	4.90	6.32	6.12	4.71	4.70
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.5	5.8	5.8	2.2	1.5
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.1	6.6	6.1	1.1	1.1
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.7	-0.9	-0.1	2.2	0.9
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.4	4.4	5.7	-1.8	-3.9
6.3.2 ईंधन और पावर	-0.3	-14.9	-11.6	11.7	5.3
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	1.3	-0.6	-0.3	2.6	2.3
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	0.4	-13.4	-8.5	33.1	19.0
7.2 निर्यात	5.3	-1.6	1.1	8.3	4.4

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2016-17	2016	2017				
			जुला	जून 23	जुला 7	जुला 14	जुला 21
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	13,101.81	17,011.11	15,074.43	15,175.06	15,226.78	15,226.67	15,157.80
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	13,101.93	17,011.29	15,074.56	15,175.18	15,226.92	15,226.80	15,157.93
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	675.08	729.07	679.70	690.30	690.30	690.36	690.36
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	12,422.35	16,269.93	14,388.64	14,478.88	14,530.75	14,530.75	14,461.99
1.2.3 रुपया सिक्का	4.50	1.82	6.21	6.00	5.87	5.70	5.58
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	10.46	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	10,389.43	5,017.50	8,835.90	9,315.94	8,895.43	8,733.66	8,739.65
2.1.1.1 केंद्र सरकार	50.00	1.01	1.01	1.00	1.01	1.01	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	946.73	946.73	946.73	946.73	946.73
2.1.1.3 राज्य सरकारें	0.42	0.42	7.57	0.42	0.42	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5,087.73	4,025.35	4,295.11	4,286.52	4,384.41	4,306.27	4,432.63
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	55.13	35.61	37.13	37.60	44.13	35.78	35.74
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18.92	15.30	16.93	22.04	19.39	17.88	18.40
2.1.1.7 अन्य बैंक	279.49	214.76	250.13	250.02	252.30	252.28	251.98
2.1.1.8 अन्य	4,897.74	725.05	3,281.29	3,771.61	3,247.03	3,173.29	3,046.29
2.1.1.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	6.44
2.1.2 अन्य देयताएं	8,411.18	9,909.35	8,651.26	8,725.99	8,742.67	8,770.22	8,785.87
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,800.61	14,926.83	17,487.16	18,041.93	17,638.10	17,503.88	17,519.08
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	10,263.49	6,743.09	8,990.28	9,196.32	9,215.20	9,310.47	9,420.03
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	105.36	622.83	227.08	46.86	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	12.62	12.30	19.30	46.89	16.37	8.95	17.60
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	218.10	261.16	15.40	27.45	20.95	81.93	17.35
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	39.91	52.60	36.25	28.98	35.83	35.23	36.63
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	6.45
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	7,528.11	7,043.01	7,530.33	7,484.98	7,485.65	7,383.00	7,383.65
2.2.6 अन्य आस्तियां	738.26	814.57	790.11	634.36	636.88	637.31	643.68
2.2.6.1 सोना	613.19	662.23	617.39	627.02	627.02	627.01	627.02

* डाटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन- शील रिपो दर	परिवर्तन- शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
जून 1, 2017	17.50	236.74	-	970.56	-	-	-	-	-	-1,189.80
जून 2, 2017	19.75	86.97	2.00	859.51	4.00	-	-	-	-	-920.73
जून 3, 2017	-	116.00	-	-	0.40	-	-	-	-	-115.60
जून 5, 2017	19.60	51.56	-	236.25	3.75	-	-	-	-	-264.46
जून 6, 2017	92.96	59.39	2.50	134.95	3.75	-0.60	-	-	-	-95.73
जून 7, 2017	134.45	30.52	-	-	10.75	-	-	-	-	114.68
जून 8, 2017	23.40	49.16	-	327.31	4.00	-	-	-	-	-349.07
जून 9, 2017	23.70	154.19	5.25	317.40	1.40	-	-	-	-	-441.24
जून 12, 2017	19.65	116.62	-	260.58	-	-	-	-	-	-357.55
जून 13, 2017	19.25	76.05	2.25	255.11	-	-	-	-	-	-309.66
जून 14, 2017	33.95	32.69	-	194.87	10.03	-2.31	-	-	-	-185.89
जून 15, 2017	22.06	71.60	-	332.65	0.01	2.31	-	-	-	-379.87
जून 16, 2017	26.35	40.12	3.50	431.05	-	-	-	-	-	-441.32
जून 17, 2017	-	84.02	-	-	-	-	-	-	-	-84.02
जून 19, 2017	23.65	49.70	-	242.07	1.75	-	-	-	-	-266.37
जून 20, 2017	21.45	48.00	-	153.35	-	-	-	-	-	-179.90
जून 21, 2017	41.55	66.89	-	93.09	-	-	-	-	-	-118.43
जून 22, 2017	32.45	165.94	-	201.25	-	-	-	-	-	-334.74
जून 23, 2017	22.60	392.23	4.00	736.68	2.50	-0.50	-	-	-	-1,100.31
जून 27, 2017	21.45	183.42	1.50	99.45	1.00	-	-	-	-	-258.92
जून 28, 2017	20.52	175.48	-	148.11	-	1.10	-	-	-	-301.97
जून 29, 2017	22.75	439.75	-	397.72	-	-	-	-	-	-814.72
जून 30, 2017	24.75	529.93	4.75	576.15	70.00	-	-	-	-	-1,006.58

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डालर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डालर) (1.1-1.2)	12,351.00	1,918.00	5,006.00	3,291.00
1.1 क्रय (+)	71,764.00	3,948.00	7,020.00	4,971.00
1.2 विक्रय (-)	59,413.00	2,030.00	2,014.00	1,680.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	822.16	129.76	328.87	218.32
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डालर)	12,351.00	3,811.00	5,572.00	8,863.00
(बिलियन ₹)	822.17	255.32	366.94	585.26
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डालर)	10,835.00	-7,431.00	13,601.00	17,081.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	10,456.00	1,750.00	0.00	0.00
1.2 विक्रय (-)	10,456.00	1,750.00	0.00	0.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डालर)	0.00	0.00	0.00	0.00

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	30 जून 2017 तक		
	दीर्घ(+)	अल्प (-)	निवल(1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	2,078	1,940	138
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	3,354	1,335	2,019
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	17,136	79	17,057
4. 1 वर्ष से अधिक	0	2,133	-2,133
कुल (1+2+3+4)	22,568	5,487	17,081

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2016-17	2016	2017					जुल 21
			जुल 22	फर. 17	मार्च 31	अप्रै. 28	मई 26	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	19.3	2.8	-	19.3	2.9	0.4	2.5	6.8
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	14.8	19.0	10.6	14.8	11.6	17.8	16.7	15.4
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	34.1	21.9	10.6	34.1	14.5	18.2	19.2	22.1

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2016-17	2016	2017		
		जून 24	मई 26	जून 9	जून 23
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	12,637.1	16,618.9	14,130.2	14,463.5	14,521.5
1.1 संचलन में नोट	13,101.8	17,105.0	14,627.6	14,929.1	15,074.4
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	243.4	218.6	245.0	245.0	245.7
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	715.6	712.2	749.8	718.1	806.1
2 जनता की जमाराशियां	14,317.2	10,034.0	12,183.9	12,049.7	12,578.6
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	14,106.3	9,901.5	12,006.2	11,870.1	12,376.8
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	132.5	177.7	179.6	201.8
3 एम₁ (1 + 2)	26,954.3	26,653.0	26,314.1	26,513.2	27,100.1
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	910.4	678.4	910.4	910.4	910.4
5 एम₂ (3 + 4)	27,864.7	27,331.3	27,224.5	27,423.7	28,010.5
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	101,489.5	92,587.4	100,943.5	101,329.0	101,017.0
7 एम₃ (3 + 6)	128,443.9	119,240.4	127,257.6	127,842.2	128,117.0
8 कुल डाकघर जमाराशियां	2,551.8	2,181.6	2,551.8	2,551.8	2,551.8
9 एम₄ (7 + 8)	130,995.6	121,422.0	129,809.4	130,394.0	130,668.8

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुकवार/ नियत शुकवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		जून 24	मई 26	जून 9	जून 23
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	38,690.9	36,016.0	41,190.0	41,402.4	41,077.9
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	6,208.1	6,604.6	6,867.0	6,835.9	6,672.7
1.1.1 सरकार पर दावे	7,512.0	7,020.5	7,815.2	7,784.1	7,628.0
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	7,499.4	7,009.9	7,805.0	7,749.0	7,608.7
1.1.1.2 राज्य सरकारें	12.6	10.6	10.2	35.1	19.3
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,303.9	415.9	948.2	948.2	955.3
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,303.5	415.5	947.7	947.7	947.7
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	7.6
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	32,482.8	29,411.5	34,323.0	34,566.5	34,405.2
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	84,514.3	77,914.5	81,645.0	82,278.2	82,328.8
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	72.9	75.3	66.4	70.0	69.3
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	84,441.4	77,839.2	81,578.6	82,208.3	82,259.6
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	78,815.3	72,279.6	75,984.8	76,592.1	76,637.1
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,548.9	5,508.9	5,511.0	5,531.6	5,538.7
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	77.2	50.7	82.8	84.6	83.7
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	25,582.3	25,892.6	26,054.7	26,095.5	26,284.3
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	23,972.1	24,386.7	24,444.5	24,485.3	24,674.1
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	23,974.1	24,388.8	24,446.3	24,487.2	24,676.0
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,610.2	1,505.9	1,610.2	1,610.2	1,610.2
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	226.0	252.4	252.4	253.1
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	20,594.6	20,808.7	21,884.6	22,186.4	21,827.1
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	8,333.5	10,005.0	8,460.2	8,397.9	8,529.4
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,261.1	10,803.7	13,424.4	13,788.5	13,297.7
एम₃ (1+2+3+4-5)	128,443.9	119,240.4	127,257.6	127,842.2	128,117.0

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		जून 24	मई 26	जून 9	जून 23
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	26,954.4	26,653.0	26,314.1	26,513.2	27,100.1
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	72,005.3	66,926.4	71,112.4	71,486.3	71,933.5
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	130,222.1	119,104.5	128,891.3	129,312.9	129,639.8
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	12,637.2	16,618.9	14,130.2	14,463.5	14,521.5
1.2. निवासियों की कुल जमा राशियां	114,219.5	99,398.1	111,557.8	111,810.3	112,006.6
1.2.1 मांग जमा राशियां	14,106.3	9,901.5	12,006.2	11,870.1	12,376.8
1.2.2 निवासियों की सावधि जमा राशियां	100,113.2	89,496.6	99,551.6	99,940.2	99,629.8
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमा राशियां	45,050.9	40,273.5	44,798.2	44,973.1	44,833.4
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	3,211.6	1,557.0	1,302.3	1,267.7
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमा राशियां	55,062.2	49,223.1	54,753.4	54,967.1	54,796.4
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	210.9	132.5	177.7	179.6	201.8
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	3,154.5	2,954.9	3,025.5	2,859.5	2,909.9
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	129,709.2	119,920.0	129,771.8	130,709.1	130,469.1
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	38,691.0	36,016.0	41,190.0	41,402.4	41,077.9
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	6,208.1	6,604.6	6,867.0	6,835.9	6,672.7
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	32,482.9	29,411.5	34,323.0	34,566.5	34,405.2
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	91,018.3	83,904.0	88,581.8	89,306.7	89,391.2
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	72.9	75.3	66.4	70.0	69.3
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	90,945.4	83,828.7	88,515.4	89,236.8	89,322.0
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	6,462.5	5,909.5	6,856.8	6,947.2	6,970.6
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	226.0	252.4	252.4	253.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,819.8	22,324.9	23,899.5	23,914.0	24,194.1
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,386.7	24,444.5	24,485.3	24,674.1
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-152.3	-2,061.8	-545.0	-571.3	-480.0
2.4 पूंजी खाता	18,195.5	19,262.9	18,914.9	18,758.5	18,936.6
2.5 अन्य मदें (निवल)	5,362.3	4,103.5	6,117.6	6,804.1	6,340.0

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2016-17	2016	2017		
	1	जून	अप्रै.	मई	जून
		2	3	4	5
1 एन एम ₃	130,222.1	119,104.5	128,886.4	128,891.3	129,639.8
2 डाकघर जमा राशियां	2,551.8	2,181.6	2,551.8	2,551.8	2,551.8
3 एन ₁ (1 + 2)	132,773.9	121,286.1	131,438.2	131,443.1	132,191.5
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमा राशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एन ₂ (3 + 4)	132,803.2	121,315.4	131,467.5	131,472.4	132,220.9
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमा राशियां	451.5	418.5	451.5
7 एन ₃ (5 + 6)	133,254.6	121,733.9	132,672.3

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016		2017	
		जून 24	मई 26	जून 9	जून 23
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	17,331.1	14,880.0	15,181.6	15,327.6
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,441.3	4,200.3	4,638.2	4,731.2	4,599.3
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5,087.7	3,940.2	4,329.5	4,425.0	4,295.1
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	132.5	177.7	179.6	201.8
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	19,004.8	21,663.9	19,696.0	20,092.4	20,128.6
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	3,115.3	7,056.2	3,459.3	3,752.5	3,730.8
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	6,208.1	6,604.6	6,867.0	6,835.9	6,672.7
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	6,195.9	6,594.4	6,857.3	6,801.3	6,661.0
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	348.6	246.6	105.4
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	7,494.9	7,007.7	7,449.5	7,495.8	7,497.1
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	7,494.9	6,997.3	7,449.5	7,495.8	7,497.1
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	4.5	2.2	6.9	6.6	6.2
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,303.5	415.5	947.7	947.7	947.7
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	12.2	10.2	9.7	34.7	11.7
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-3,165.7	376.4	-3,474.1	-3,153.4	-3,011.1
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-3,165.7	376.4	-3,474.5	-3,153.4	-3,011.1
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	72.9	75.3	66.4	70.0	69.3
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	14.8	22.1	17.8	17.2	16.7
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	226.0	252.4	252.4	253.1
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,386.7	24,444.5	24,485.3	24,674.1
2.3.1 सोना	1,288.3	1,366.2	1,312.5	1,297.1	1,297.1
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	22,684.0	23,020.7	23,132.1	23,188.4	23,377.2
2.4 पूंजी खाता	7,512.8	9,033.9	7,583.7	7,455.9	7,568.5
2.5 अन्य मदें (निवल)	820.6	971.1	876.5	942.0	960.9

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2016-17	2016		2017			
		जून 24	मई 26	जून 2	जून 9	जून 16	जून 23
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	19,004.8	21,663.9	19,696.0	19,825.4	20,092.4	20,207.0	20,128.6
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	17,331.1	14,880.0	14,951.8	15,181.6	15,288.5	15,327.6
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	5,441.3	4,200.3	4,638.2	4,688.6	4,731.2	4,701.2	4,599.3
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	132.5	177.7	185.0	179.6	217.3	201.8
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	6,208.1	6,604.6	6,867.0	7,436.2	6,835.9	6,522.0	6,672.7
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-3,165.7	376.4	-3,474.1	-4,007.9	-3,153.4	-2,727.5	-3,011.1
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	72.9	75.3	66.4	70.7	70.0	70.9	69.3
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,386.7	24,444.5	24,544.2	24,485.3	24,655.4	24,674.1
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	226.0	252.4	252.4	252.4	252.4	253.1
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	8,333.5	10,005.0	8,460.2	8,470.3	8,397.9	8,566.3	8,529.4

सं. 12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		जून 24	मई 26	जून 9	जून 23
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	106,728.9	92,344.3	104,147.1	104,390.6	104,669.4
1.1.1 मांग जमाराशियां	12,953.3	8,847.1	10,873.4	10,736.3	11,245.9
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	93,775.6	83,497.2	93,273.6	93,654.3	93,423.5
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	42,199.0	37,573.8	41,973.1	42,144.4	42,040.6
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	3,211.6	1,557.0	1,302.3	1,267.7
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	51,576.6	45,923.5	51,300.5	51,509.9	51,382.9
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	3,154.5	2,954.9	3,025.5	2,859.5	2,909.9
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	115,665.6	105,644.7	115,093.2	116,039.2	115,949.9
2.1.1 सरकार को ऋण	30,422.4	27,445.8	32,242.7	32,488.8	32,320.0
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	85,243.2	78,198.9	82,850.5	83,550.4	83,629.9
2.1.2.1 बैंक ऋण	78,815.3	72,279.6	75,984.8	76,592.1	76,637.1
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	78,279.6	71,275.8	75,377.8	76,012.6	76,053.7
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	44.2	82.6	82.6	83.8	94.4
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10.9	16.8	15.9	16.8	17.3
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	6,372.9	5,819.9	6,767.2	6,857.6	6,881.0
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-152.3	-2,061.8	-545.0	-571.3	-480.0
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,983.5	2,034.5	1,583.1	1,479.7	1,561.2
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,376.3	3,090.9	1,391.8	1,388.8	1,387.2
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	759.5	1,005.4	736.2	662.2	654.1
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	8,871.2	4,182.9	8,453.8	8,197.5	8,013.7
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,087.7	3,940.2	4,329.5	4,425.0	4,295.1
2.3.2 उपलब्ध नकदी	617.7	619.1	649.8	619.2	707.4
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-3,165.7	376.4	-3,474.5	-3,153.4	-3,011.1
2.4 पूंजी खाता	10,441.0	9,987.3	11,089.4	11,060.9	11,126.4
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	4,060.1	2,479.2	4,740.0	5,354.4	4,777.8
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	3,995.0	3,810.2	4,313.4	3,999.8	4,193.9
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-108.8	-192.0	-361.3	-382.2	-447.5

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31, 2017 की स्थिति	2016	2017		
		जून 24	मई 26	जून 9	जून 23
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	30,309.6	27,462.6	32,119.7	32,505.7	32,337.3
2 वाणिज्यिक पत्र	1,159.6	887.5	1,148.5	1,258.5	1,291.6
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	91.9	77.8	92.0	95.7	97.0
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	567.3	454.4	588.2	597.5	616.2
3.3 अन्य	51.8	42.9	47.0	49.7	46.9
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,118.7	1,168.8	1,089.0	1,033.7	1,055.6
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	1,680.0	1,270.0	1,551.0	1,548.5	1,606.1
4.3 अन्य	810.9	681.9	778.4	742.2	731.3
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	134.0	715.3	726.5	720.6	632.6
5.2 वित्तीय संस्थाएं	844.0	625.7	855.8	811.2	803.7

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2016-17	2016	2017		2016-17	2016	2017	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	221	218	215	215	150	147	144	144
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,397.7	2,243.2	2,241.3	2,170.5	2,330.7	2,113.1	2,179.5	2,111.4
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	1,765.5	1,472.3	1,658.1	1,672.0	1,698.6	1,405.8	1,598.0	1,615.4
1.2 बैंकों से उधार राशि	573.6	639.6	536.0	450.4	573.5	604.9	535.1	449.9
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	58.6	131.3	47.2	48.1	58.6	102.5	46.4	46.1
2 अन्य के प्रति देयताएं	118,405.3	106,274.8	115,998.4	118,243.0	115,376.8	103,205.8	113,058.0	116,151.2
2.1 कुल जमाराशियां	110,485.7	98,035.8	107,810.5	110,138.6	107,576.6	95,435.2	104,995.6	108,148.9
2.1.1 मांग	13,105.3	9,059.4	11,030.3	12,762.5	12,814.9	8,847.1	10,776.4	12,573.6
2.1.2 मीयादी	97,380.5	88,976.4	96,780.2	97,376.1	94,761.7	86,588.1	94,219.3	95,575.3
2.2 उधार	3,192.8	3,311.1	3,063.3	3,275.9	3,163.2	2,954.9	3,025.5	3,239.5
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	4,726.7	4,927.8	5,124.7	4,828.5	4,637.0	4,815.6	5,036.8	4,762.9
3 रिज़र्व बैंक से उधार	218.1	827.4	23.2	-	218.1	827.4	22.9	-
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	218.1	827.4	23.2	-	218.1	827.4	22.9	-
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,869.3	4,683.8	5,120.5	773.2	5,701.3	4,559.3	4,976.4	755.6
4.1 उपलब्ध नकदी	630.5	634.3	666.1	773.2	613.60	619.1	646.9	755.6
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,238.8	4,049.5	4,454.4	-	5,087.7	3,940.2	4,329.5	-
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	2,934.7	2,900.4	2,904.1	2,816.6	2,437.5	2,387.8	2,453.8	2,634.7
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	1,898.2	1,684.2	1,923.7	2,053.6	1,700.2	1,523.5	1,745.5	1,901.8
5.1.1 चालू खाते में	197.5	148.9	126.7	162.9	160.8	131.5	107.4	140.8
5.1.2 अन्य खातों में	1,700.7	1,535.3	1,797.1	1,890.7	1,539.5	1,392.0	1,638.1	1,761.0
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	296.9	517.0	313.4	147.8	77.0	304.3	135.9	137.1
5.3 बैंकों को अग्रिम	380.4	302.5	350.9	364.5	379.5	262.5	350.1	364.5
5.4 अन्य आस्तियां	359.1	396.7	316.0	250.7	280.7	297.4	222.3	231.4
6 निवेश	31,161.1	28,514.1	32,982.8	33,206.1	30,309.6	27,462.6	32,119.7	32,573.7
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	31,144.8	28,216.2	32,958.5	33,184.4	30,297.5	27,445.8	32,102.0	32,557.5
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	16.4	297.9	24.3	21.7	12.2	16.8	17.7	16.3
7 बैंक ऋण	80,818.2	74,511.4	78,025.0	79,768.6	78,415.1	72,279.6	75,694.6	78,516.5
7क खाद्यान्न ऋण	652.4	1,166.5	799.4	701.2	539.3	1,003.8	607.0	508.9
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	78,491.4	72,348.1	75,943.0	77,585.2	76,149.7	70,196.9	73,686.4	76,391.8
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	263.0	277.8	235.8	225.1	245.4	253.7	208.5	209.9
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,402.8	1,268.6	1,287.9	1,344.2	1,365.9	1,222.9	1,247.5	1,306.8
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	248.6	223.7	196.2	216.4	246.4	218.2	194.5	214.7
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	412.4	393.2	362.0	397.6	407.6	387.9	357.7	393.4

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक 2017-18	वर्ष-दर- वर्ष 2017
		जून 24	मई 26	जून 23		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	71,347	66,295	68,776	69,209	-3.0	4.4
1.1 खाद्यान्न ऋण	400	757	533	511	27.7	-32.5
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	70,947	65,538	68,243	68,698	-3.2	4.8
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	9,924	9,044	9,657	9,719	-2.1	7.5
1.2.2 उद्योग	26,800	26,469	26,068	26,185	-2.3	-1.1
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,697	3,598	3,605	3,616	-2.2	0.5
1.2.2.2 मझौले	1,048	1,090	983	1,002	-4.4	-8.1
1.2.2.3 बड़े	22,055	21,782	21,480	21,567	-2.2	-1.0
1.2.3 सेवाएं	18,022	15,651	16,345	16,393	-9.0	4.7
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,104	1,055	1,094	1,102	-0.2	4.4
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	179	192	172	169	-5.7	-11.9
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	375	376	361	361	-3.7	-4.0
1.2.3.4 नौवहन	84	100	75	76	-9.6	-24.6
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,377	1,135	1,296	1,278	-7.2	12.6
1.2.3.6 व्यापार	4,279	3,872	4,095	4,078	-4.7	5.3
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	1,932	1,711	1,806	1,787	-7.5	4.5
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,347	2,161	2,289	2,291	-2.4	6.0
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,856	1,832	1,781	1,771	-4.6	-3.3
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	3,910	3,451	3,415	3,410	-12.8	-1.2
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	4,859	3,639	4,057	4,149	-14.6	14.0
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	16,200	14,374	16,173	16,401	1.2	14.1
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	208	187	172	173	-16.9	-7.7
1.2.4.2 आवास	8,601	7,734	8,588	8,619	0.2	11.4
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	661	613	572	597	-9.6	-2.5
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	48	56	51	52	10.3	-7.0
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	521	425	558	567	8.7	33.4
1.2.4.6 शिक्षा	701	683	697	695	-0.8	1.8
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,705	1,564	1,731	1,716	0.6	9.7
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	3,755	3,112	3,804	3,982	6.0	28.0
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	24,357	22,588	23,379	23,492	-3.5	4.0
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	9,909	9,034	9,640	9,698	-2.1	7.3
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,020	8,495	8,728	8,733	-3.2	2.8
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,697	3,598	3,605	3,616	-2.2	0.5
1.2अ.2.2 सेवाएं	5,322	4,898	5,123	5,117	-3.9	4.5
1.2अ.3 आवास	3,683	3,473	3,526	3,571	-3.1	2.8
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	189	184	142	142	-24.8	-22.8
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	604	599	593	582	-3.7	-2.9
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	6	6	3	3	-60.8	-57.5
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,546	4,927	5,153	5,258	-5.2	6.7
1.2अ.8 निर्यात ऋण	425	475	401	390	-8.2	-17.8

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 24	मई 26	जून 23		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	26,800	26,469	26,068	26,185	-2.3	-1.1
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	345	338	322	327	-5.3	-3.5
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,455	1,460	1,424	1,450	-0.4	-0.7
1.2.1 चीनी	327	372	310	297	-9.2	-20.1
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	184	194	180	183	-0.1	-5.5
1.2.3 चाय	35	33	37	39	11.6	18.1
1.2.4 अन्य	909	861	898	930	2.3	8.1
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	173	166	158	166	-3.8	-0.1
1.4 वस्त्र	1,963	1,992	1,930	1,927	-1.8	-3.2
1.4.1 सूती वस्त्र	964	977	961	971	0.8	-0.6
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	23	20	22	22	-3.3	14.1
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	204	199	211	216	5.9	8.2
1.4.4 अन्य वस्त्र	773	796	735	718	-7.1	-9.7
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	107	105	105	106	-1.1	0.6
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	105	103	100	101	-3.8	-2.2
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	326	341	320	319	-2.3	-6.5
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	596	523	534	525	-11.9	0.3
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,724	1,558	1,547	1,536	-10.9	-1.4
1.9.1 उर्वरक	335	251	253	272	-18.6	8.6
1.9.2 औषधि और दवाइयां	464	522	437	427	-7.9	-18.2
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	507	336	457	436	-14.1	29.5
1.9.4 अन्य	419	448	399	401	-4.1	-10.5
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	392	366	379	389	-0.8	6.3
1.11 कांच और कांच के सामान	79	84	77	76	-4.0	-9.6
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	542	548	501	506	-6.7	-7.7
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	4,211	4,195	4,130	4,154	-1.3	-1.0
1.13.1 लोहा और स्टील	3,192	3,139	3,183	3,213	0.6	2.3
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	1,018	1,056	947	941	-7.5	-10.9
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,496	1,529	1,445	1,463	-2.2	-4.3
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	336	377	316	318	-5.4	-15.6
1.14.2 अन्य	1,160	1,152	1,129	1,146	-1.3	-0.6
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	736	686	716	706	-4.0	3.0
1.16 रत्न और आभूषण	690	695	698	689	-0.1	-0.8
1.17 निर्माण	822	755	833	849	3.2	12.4
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,064	9,140	8,898	8,915	-1.6	-2.5
1.18.1 पावर	5,254	5,288	5,194	5,203	-1.0	-1.6
1.18.2 दूरसंचार	851	910	820	827	-2.8	-9.1
1.18.3 सड़क	1,800	1,840	1,723	1,721	-4.4	-6.5
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,160	1,102	1,161	1,164	0.3	5.6
1.19 अन्य उद्योग	1,973	1,884	1,951	1,981	0.4	5.1

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति					
	2016-17	2016	2017			
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 03	मार्च 17	मार्च 31
	1	2	3	4	5	6
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	31	32	30	31	32	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	508.7	420.2	462.4	472.6	489.8	508.7
2 मांग और मीयादी देयताएं						
2.1 मांग देयताएं	181.4	152.3	145.7	149.6	157.1	181.4
2.1.1 जमाराशियां						
2.1.1.1 अंतर-बैंक	45.0	34.2	33.8	32.7	37.2	45.0
2.1.1.2 अन्य	104.4	77.8	83.7	87.9	86.5	104.4
2.1.2 बैंकों से उधार	2.0	9.5	0.3	0.0	0.0	2.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	30.0	30.9	27.9	28.9	33.3	30.0
2.2 मीयादी देयताएं	930.5	840.5	877.2	879.1	899.5	930.5
2.2.1 जमाराशियां						
2.2.1.1 अंतर-बैंक	512.6	491.8	491.1	487.2	489.0	512.6
2.2.1.2 अन्य	404.3	342.4	378.8	384.7	403.3	404.3
2.2.2 बैंकों से उधार	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	9.2	6.3	7.3	7.2	7.3	9.2
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	517.2	435.4	517.2	502.7	494.3	517.2
4.1 मांग	180.4	164.0	171.7	170.5	173.4	180.4
4.2 मीयादी	336.8	271.5	345.6	332.2	320.8	336.8
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	66.5	46.1	47.2	47.4	49.8	66.5
5.1 उपलब्ध नकदी	3.7	2.4	3.2	3.6	4.5	3.7
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	62.9	43.8	44.0	43.8	45.3	62.9
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	16.8	6.8	8.3	9.2	9.0	16.8
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	327.1	298.8	309.3	317.9	330.2	327.1
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	254.1	191.3	281.8	264.1	251.6	254.1
9 बैंक ऋण (10.1+11)	458.7	446.8	452.6	456.9	453.3	458.7
10 अग्रिम						
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	458.6	446.8	452.6	456.8	453.2	458.6
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	777.0	727.9	749.5	747.9	767.3	777.0
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2016-17			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जून 16	मई 17	जून 17	जून 16	मई 17	जून 17	जून 16	मई 17	जून 17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	135.3	134.9	135.2	136.0	133.8	134.9	138.2	133.6	135.7	136.8	133.7	135.2
1.1 अनाज और उत्पाद	130.8	128.9	130.2	128.6	133.1	133.5	125.9	132.6	132.9	127.7	132.9	133.3
1.2 मांस और मछली	137.9	140.1	138.7	138.6	140.3	143.6	143.9	144.1	148.7	140.5	141.6	145.4
1.3 अंडा	128.9	130.7	129.6	126.6	126.8	128.1	130.9	125.6	128.3	128.3	126.3	128.2
1.4 दूध और उत्पाद	135.2	132.4	134.1	133.6	138.2	138.6	131.0	136.8	137.3	132.6	137.7	138.1
1.5 तेल और चर्बी	120.3	112.0	117.3	118.6	120.8	120.9	110.2	113.4	113.5	115.5	118.1	118.2
1.6 फल	138.1	132.8	135.6	137.4	140.2	140.9	135.5	135.2	137.2	136.5	137.9	139.2
1.7 सब्जी	139.2	144.8	141.1	152.5	123.8	128.8	173.7	129.2	142.2	159.7	125.6	133.3
1.8 दाल और उत्पाद	165.6	170.3	167.2	169.2	141.8	140.1	184.4	131.5	128.2	174.3	138.3	136.1
1.9 चीनी और उत्पाद	112.1	114.9	113.0	108.8	118.6	118.8	112.0	121.0	120.9	109.9	119.4	119.5
1.10 मसाले	135.1	143.8	138.0	133.1	134.0	133.6	142.8	139.9	138.8	136.3	136.0	135.3
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	128.1	122.4	125.7	126.4	130.3	130.6	121.6	123.8	124.2	124.4	127.6	127.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	141.7	139.2	140.5	139.2	145.8	146.5	136.9	142.9	143.1	138.1	144.5	144.9
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	140.1	144.2	141.2	137.2	145.5	145.8	142.7	148.3	148.6	138.7	146.2	146.5
3 कपड़ा और जूते	137.9	127.8	133.9	135.6	141.8	142.3	126.6	130.2	130.2	132.0	137.2	137.5
3.1 कपड़ा	138.6	128.9	134.8	136.3	142.5	143.1	127.6	131.5	131.5	132.9	138.2	138.5
3.2 जूते	133.7	121.7	128.7	131.6	137.3	137.7	121.1	123.2	123.2	127.2	131.4	131.7
4 आवास	--	128.0	128.0	--	--	--	125.5	132.1	131.4	125.5	132.1	131.4
5 ईंधन और लाइट	130.1	116.4	124.9	128.0	135.0	134.9	115.5	120.1	119.0	123.3	129.4	128.9
6 विविध	125.0	120.6	122.9	123.3	127.9	128.1	119.6	122.6	122.7	121.5	125.3	125.5
6.1 घरेलू सामान और सेवा	131.3	124.3	128.0	129.3	134.9	135.2	123.2	126.5	126.8	126.4	130.9	131.2
6.2 स्वास्थ्य	128.1	121.6	125.6	126.2	131.4	131.3	120.6	123.6	123.8	124.1	128.4	128.5
6.3 परिवहन और संचार	117.4	112.8	114.9	116.3	119.4	119.4	112.3	114.3	113.9	114.2	116.7	116.5
6.4 मनोरंजन	125.9	121.0	123.2	124.1	129.4	129.8	119.9	122.8	122.9	121.7	125.7	125.9
6.5 शिक्षा	132.3	131.1	131.6	130.2	136.3	136.9	129.3	133.8	134.3	129.7	134.8	135.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	121.7	120.3	121.1	119.9	123.7	124.2	118.8	122.0	122.5	119.4	123.0	123.5
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	132.4	127.9	130.3	131.9	133.3	134.0	128.1	129.3	129.9	130.1	131.4	132.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2016-17	2016		2017	
				जून	मई	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	276	277	278	280	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	870	869	872	877	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	875	874	878	884	

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2016-17	2016		2017	
		जून	मई	मई	जून
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	29,665	29,745	28,471	28,823	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42,748	41,196	39,366	39,492	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड/बिजनेस लाइन/द इकोनॉमिक टाइम्स, मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2016-17	2016	2017		
			जून	अप्रै.	मई (अ)	जून (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	111.6	111.7	113.2	112.8	112.7
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	128.9	132.0	127.4	126.5	126.9
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	140.3	144.0	138.6	137.7	139.0
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	152.0	150.6	146.6	144.8	143.5
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	138.7	157.0	130.8	129.0	137.3
1.1.1.3 दूध	4.440	134.3	133.4	137.7	138.0	138.9
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	133.0	135.3	135.2	136.4	137.9
1.1.1.5 मसाले	0.529	140.5	142.2	126.6	121.4	118.3
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	150.5	145.8	157.0	154.6	143.7
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	122.2	124.2	121.3	119.8	117.8
1.1.2.1 फाइबर	0.839	117.1	116.8	122.1	119.5	120.4
1.1.2.2 तिलहन	1.115	136.0	144.2	129.9	127.4	125.4
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	114.9	116.1	114.7	112.9	112.0
1.1.2.4 फूल	0.204	137.4	121.7	134.4	145.4	120.3
1.1.3 खनिज	0.833	113.1	118.7	116.3	114.8	116.3
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	98.4	105.2	103.2	101.3	103.2
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	164.4	166.0	162.4	162.1	162.4
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	73.1	73.9	71.1	71.1	69.4
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	86.3	85.2	91.7	90.8	89.7
1.2.1 कोल	2.138	109.0	107.0	117.5	116.6	117.5
1.2.1.1 कोकिंग कोल	0.647	108.2	101.4	135.5	132.3	135.5
1.2.1.2 गैर-कोकिंग कोल	1.401	110.5	110.7	110.7	110.7	110.7
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	90.2	90.7	95.0	95.0	95.0
1.2.2 खनिज तेल	7.950	73.3	72.5	80.3	79.3	77.5
1.2.3 बिजली	3.064	104.2	102.8	103.3	102.7	102.0
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	110.7	110.0	112.6	112.6	112.5
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	125.4	122.9	127.2	127.2	126.7
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.1	140.1	136.6	134.7	135.9
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	127.7	127.7	128.4	129.3	130.8
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	120.9	120.0	120.1	120.8
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	107.0	104.1	107.2	106.7	105.7
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	132.3	128.1	141.0	141.7	141.1
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	136.2	133.1	136.9	137.3	136.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	114.6	114.5	113.8	113.8	113.5
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	127.0	125.9	129.2	129.4	130.6
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	124.8	118.9	132.5	133.5	132.1
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	125.5	124.5	123.3	125.7	124.0
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	137.1	131.7	140.8	133.3	137.0
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	125.9	132.1	125.6	120.4	127.7
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	124.5	126.4	115.0	115.7	116.6
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	126.3	125.0	126.3	126.3	127.2
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.2	143.0	143.1	142.3	142.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	165.4	168.1	158.4	158.0	156.8
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	116.1	115.1	117.8	117.5	117.6
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.3	111.0	114.7	114.5	114.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	114.2	112.9	116.6	116.8	116.6
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	121.8	123.0	123.5	122.7	123.3
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	141.6	141.3	143.1	142.9	144.3
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	141.6	141.3	143.1	142.9	144.3
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	111.2	110.2	113.8	113.6	113.7
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	103.3	101.6	107.7	107.2	107.2
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	120.9	121.1	120.6	120.4	121.0
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	107.1	106.4	108.4	107.5	107.1
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र लेख	0.299	121.7	120.1	124.1	124.5	124.6
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी और नेटिंग	0.098	143.0	144.6	145.1	145.4	145.8
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	112.9	110.8	116.2	118.4	117.6
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	131.0	130.8	134.1	133.5	133.2
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	133.9	134.9	137.5	136.2	135.3
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	123.3	120.0	125.2	126.1	127.5

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारंक्र	2016-17	2016	2017			
		1	2	जून	अप्रै.	मई (अ)	जून (अ)
				3	4	5	6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद	0.535	122.6	123.8	119.1	119.5	119.9	
1.3.6.1 चमड़ेकी टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	119.9	121.6	112.9	112.1	114.0	
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	132.3	133.5	129.8	129.8	131.1	
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.5	122.4	119.4	120.3	119.9	
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	129.8	128.3	130.7	130.6	130.5	
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.9	123.2	120.7	121.9	120.9	
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल बोर्ड	0.493	127.3	125.6	128.9	128.6	129.0	
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	153.8	147.0	160.5	160.5	159.9	
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	140.3	139.0	139.3	138.9	137.9	
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद	1.113	113.6	113.2	116.4	116.4	115.7	
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	117.7	117.2	121.4	121.2	121.6	
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	114.7	113.6	115.4	115.6	112.6	
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	105.9	106.4	109.6	109.6	109.3	
1.3.9 मुद्रण और रिकार्ड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	141.1	138.1	142.7	141.7	142.4	
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	141.1	138.1	142.7	141.7	142.4	
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	111.0	111.3	111.6	111.7	111.6	
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	104.7	104.1	107.1	107.2	107.1	
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	118.7	121.0	117.1	117.1	117.3	
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	113.7	114.5	113.3	113.4	111.4	
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एगोकेमिकल उत्पाद	0.454	116.8	117.7	116.8	117.2	118.1	
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	108.5	107.4	110.3	110.6	112.0	
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	113.7	112.7	115.0	115.4	115.3	
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	106.5	106.5	107.9	107.6	108.6	
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	94.1	92.9	95.8	95.7	95.2	
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	119.7	120.5	120.4	120.8	120.2	
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	119.7	120.5	120.4	120.8	120.2	
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	107.5	107.0	108.6	108.6	108.5	
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	101.4	100.9	103.9	104.0	103.4	
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	90.4	89.7	91.1	91.5	91.3	
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	113.3	112.9	114.0	113.8	114.0	
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	109.8	110.7	111.2	111.4	112.3	
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	116.6	116.3	117.2	117.1	116.8	
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	116.2	116.2	119.7	119.9	119.9	
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	94.3	101.5	91.7	92.2	93.7	
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	111.8	111.5	112.8	112.7	112.8	
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	110.6	111.5	112.6	113.1	114.2	
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	115.3	115.6	116.5	116.7	117.8	
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और सवारना	0.234	117.4	117.2	118.2	117.3	118.2	
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	70.9	74.0	69.1	69.1	70.9	
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	91.1	89.6	97.4	96.8	96.7	
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	82.9	79.0	92.8	92.9	93.5	
1.3.14.2 मेटलिक आयरन	0.653	79.4	77.6	94.3	90.3	90.0	
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	89.8	89.6	90.1	91.3	89.0	
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	85.3	84.4	90.8	90.7	90.1	
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	89.4	87.4	99.8	97.8	97.5	
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	85.6	83.3	96.3	95.7	94.7	
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	84.1	81.2	92.9	91.9	94.8	
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	107.8	107.7	109.8	108.8	109.3	
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	100.1	97.7	105.0	104.4	104.1	
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	102.2	104.9	102.8	102.6	103.4	
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	118.2	116.9	118.0	118.0	118.0	
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	105.1	104.2	108.4	108.1	108.0	
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	102.5	101.1	104.3	104.1	104.7	
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	109.2	107.2	120.2	119.9	117.3	
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	108.5	108.7	107.7	107.7	107.8	
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, रोल बनाना, स्टाम्प लगाना, पाउडर धातु विज्ञान	0.383	94.7	96.7	91.3	91.7	91.4	
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	111.5	108.2	114.6	114.7	113.3	
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	108.1	108.0	110.9	109.7	111.6	
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	108.3	108.4	109.2	109.1	108.5	
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.7	108.2	105.4	106.4	105.3	
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	127.3	127.3	127.3	127.3	127.3	

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2016-17	2017			
			जून	अप्रै.		
				अप्रै.	मई (अ)	जून (अ)
1	2	3	4	5	6	
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	104.1	104.1	104.1	104.1	104.1
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	100.0	99.3	102.8	101.9	100.2
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	103.1	101.5	103.7	103.7	106.6
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	139.8	141.9	141.8	139.1
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	104.3	104.4	105.1	105.1	103.5
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	96.6	97.2	98.5	99.7	98.2
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	108.2	107.6	108.4	108.3	108.3
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	105.0	105.1	104.6	104.2	104.4
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	120.4	119.3	121.7	122.6	121.8
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	118.8	119.8	116.3	116.3	117.5
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	99.7	97.7	102.3	103.2	102.0
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.5	106.5	107.4	107.0	105.6
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.4	119.3	119.8	120.1	120.9
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	104.4	103.9	105.3	104.4	105.8
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	107.9	108.0	108.3	108.3	107.8
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.1	104.7	103.3	103.1	102.0
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	114.3	114.9	114.1	114.1	114.4
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	106.6	106.2	107.5	107.3	108.0
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	104.5	105.5	105.8	105.6	103.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	77.8	83.5	74.9	74.9	74.9
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने -उतारने वाले उपकरण	0.285	103.2	102.5	104.5	104.5	103.5
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	124.9	123.5	124.8	125.1	125.1
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	112.3	112.2	112.0	112.4	112.1
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	100.1	102.0	101.2	100.2	101.2
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	79.6	84.0	76.3	76.6	75.4
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	116.9	113.8	124.5	124.3	120.4
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	116.2	115.4	117.4	117.4	117.6
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	115.8	115.1	117.3	117.1	117.5
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	73.7	75.6	72.0	71.2	69.8
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	110.4	110.9	110.9	111.3	111.6
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.4	114.0	113.6	114.2	114.9
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	107.2	107.4	107.9	108.1	108.0
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	107.7	106.7	108.0	109.0	109.7
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.7	158.7	158.7	158.7	158.7
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	100.6	95.6	102.3	102.3	102.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	102.8	102.0	102.8	104.0	104.9
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	118.0	117.1	120.5	120.4	120.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	116.5	115.9	119.8	119.8	118.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	114.1	112.5	114.0	114.2	116.2
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	114.1	112.5	114.0	114.2	116.2
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	119.7	121.0	115.0	114.6	110.3
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	118.4	119.6	113.5	113.2	108.1
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	158.0	147.2	148.9	147.7	147.7
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	124.7	123.3	126.9	127.1	127.1
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	125.2	125.2	127.4	127.4	127.7
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	143.3	147.3	139.1	139.1	148.0
2 खाद्य सूचकांक	24.378	134.7	136.1	134.3	133.8	134.4

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2015-16	2016-17	अप्रैल-मई		मई	
				2016-17	2017-18	2016	2017
	1	2	3	4	5	4	5
सामान्य सूचकांक	100.00	114.9	120.6	118.3	121.0	122.2	124.3
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	97.3	102.6	98.7	99.8	101.4	100.5
1.2 विनिर्माण	77.63	116.2	121.8	119.3	121.4	123.6	125.1
1.3 बिजली	7.99	133.8	141.6	144.5	154.7	146.0	158.7
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	112.0	117.5	115.4	119.1	117.6	121.6
2.2 पूंजीगत माल	8.22	98.0	101.1	96.8	93.5	100.6	96.7
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	118.4	122.4	119.2	122.0	122.7	123.5
2.4 मुलभूत/निर्माण माल	12.34	120.3	125.0	125.3	128.4	130.9	131.0
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	120.3	126.4	127.9	121.5	129.8	123.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	117.6	127.6	122.0	132.0	130.2	140.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-जून			
	2017-18 बजट अनुमान	2017-18 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2017-18	2016-17
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	15,157.7	1,993.0	1,807.9	13.1	13.1
1.1 कर राजस्व (निवल)	12,270.1	1,773.4	1,573.0	14.5	14.9
1.2 करेतर राजस्व	2,887.6	219.7	234.8	7.6	7.3
2 पूंजीगत प्राप्तियां	6,309.6	4,514.3	3,310.5	71.5	55.1
2.1 ऋण की वसूली	119.3	20.5	17.4	17.2	16.4
2.2 अन्य प्राप्तियां	725.0	76.9	29.8	10.6	5.3
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	5,465.3	4,416.9	3,263.2	80.8	61.1
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	21,467.4	6,507.3	5,118.3	30.3	25.9
4 राजस्व व्यय	18,369.3	5,824.0	4,628.4	31.7	26.7
4.1 ब्याज भुगतान	5,230.8	1,334.1	1,088.0	25.5	22.1
5 पूंजी व्यय	3,098.0	683.3	490.0	22.1	19.8
6 कुल व्यय (4+5)	21,467.4	6,507.3	5,118.3	30.3	25.9
7 राजस्व घाटा (4-1)	3,211.6	3,831.0	2,820.5	119.3	79.7
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	5,465.3	4,416.9	3,263.2	80.8	61.1
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	234.5	3,082.8	2,175.2	1,314.4	527.5

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016	2017					
		जुल 1	मई 26	जून 2	जून 9	जून 16	जून 23	जून 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	323.7	333.2	262.7	284.3	247.5	271.1	244.8	280.9
1.2 प्राथमिक व्यापारी	243.5	281.6	235.0	281.5	251.6	249.5	222.7	247.5
1.3 राज्य सरकारें	146.2	666.2	711.7	711.7	766.7	771.7	771.7	776.7
1.4 अन्य	343.4	669.4	572.6	515.5	604.1	606.5	681.7	641.3
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	216.2	236.2	363.4	340.1	339.1	331.6	324.5	378.1
2.2 प्राथमिक व्यापारी	316.5	331.1	152.5	184.8	171.8	204.0	215.4	218.3
2.3 राज्य सरकारें	193.6	95.7	218.8	218.7	218.7	218.7	218.7	218.7
2.4 अन्य	120.9	151.6	137.5	128.3	141.8	117.0	113.5	56.9
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	512.3	464.9	567.8	636.7	647.2	640.7	645.2	643.8
3.2 प्राथमिक व्यापारी	551.8	652.8	489.9	465.4	443.5	474.9	458.0	465.1
3.3 राज्य सरकारें	26.3	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	29.7	29.7
3.4 अन्य	326.4	401.6	329.5	286.0	297.6	272.8	284.6	280.5
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 प्राथमिक व्यापारी	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3 राज्य सरकारें	1,560.6	1,113.5	1,308.5	1,388.0	1,064.8	1,092.9	1,152.0	1,178.8
4.4 अन्य	5.1	10.5	5.5	9.5	4.5	6.4	3.3	5.8
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)	3,320.8	4,309.5	4,066.5	4,078.3	4,154.9	4,183.7	4,210.4	4,237.5

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
मई 31	80	58	826.38	20.05	44	80.00	20.05	100.05	98.45	6.3149		
जून 7	80	67	878.18	67.71	29	80.00	67.71	147.71	98.46	6.2735		
जून 14	80	57	1,109.23	31.40	43	80.00	31.40	111.40	98.46	6.2735		
जून 21	80	63	1,309.02	8.88	53	80.00	8.88	88.88	98.46	6.2735		
जून 28	80	47	1,135.49	17.56	36	80.00	17.56	97.56	98.46	6.2735		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
मई 31	60	68	318.40	30.00	12	60.00	30.00	90.00	96.91	6.3946		
जून 14	60	64	327.08	39.10	32	60.00	39.10	99.10	96.94	6.3305		
जून 28	60	56	327.03	15.03	36	60.00	15.03	75.03	96.94	6.3305		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2017-18												
मई 9	60	68	249.80	—	28	60.00	—	60.00	93.93	6.4800		
मई 24	60	72	292.57	—	22	60.00	—	60.00	93.94	6.4686		
जून 7	60	64	312.37	—	19	60.00	—	60.00	93.97	6.4346		
जून 21	60	78	370.26	29.74	18	60.00	29.74	89.74	94.02	6.3778		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
जून	1, 2017	4.55-6.25	6.04
जून	2, 2017	5.00-6.25	6.03
जून	3, 2017	4.50-6.25	5.67
जून	5, 2017	5.00-6.25	6.06
जून	6, 2017	5.00-6.35	6.10
जून	7, 2017	5.00-6.40	6.18
जून	8, 2017	5.00-6.30	6.13
जून	9, 2017	5.00-6.30	6.13
जून	12, 2017	5.00-6.25	6.04
जून	13, 2017	5.00-6.30	6.04
जून	14, 2017	5.00-6.40	6.13
जून	15, 2017	5.00-6.25	6.06
जून	16, 2017	5.00-6.30	6.08
जून	17, 2017	4.00-6.25	5.87
जून	19, 2017	5.00-6.25	6.09
जून	20, 2017	5.00-6.30	6.08
जून	21, 2017	5.00-6.30	6.09
जून	22, 2017	5.00-6.30	6.09
जून	23, 2017	5.00-6.25	6.08
जून	27, 2017	5.00-6.25	6.07
जून	28, 2017	5.00-6.25	6.05
जून	29, 2017	5.00-6.25	6.05
जून	30, 2017	5.00-6.25	6.10
जुलाई	1, 2017	4.70-6.25	5.97
जुलाई	3, 2017	5.00-6.26	6.07
जुलाई	4, 2017	5.00-6.26	6.04
जुलाई	5, 2017	5.00-6.25	6.03
जुलाई	6, 2017	5.00-6.25	6.03
जुलाई	7, 2017	4.95-6.25	6.08
जुलाई	10, 2017	5.00-6.27	6.10
जुलाई	11, 2017	5.10-6.30	6.04
जुलाई	12, 2017	5.10-6.25	6.05
जुलाई	13, 2017	5.00-6.25	6.05
जुलाई	14, 2017	5.00-6.25	6.07
जुलाई	15, 2017	4.70-6.13	5.91

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2016	2017			
	जून 24	मई 12	मई 26	जून 9	जून 23
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,802.4	1,734.1	1,539.4	1,251.6	1,111.1
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	170.1	89.9	132.2	63.6	130.3
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.76-7.56	6.40-6.95	6.38-6.99	6.40-7.05	6.20-6.70

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2016	2017			
	जून 30	मई 15	मई 31	जून 15	जून 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	3,376.4	4,672.2	3,913.3	3,885.2	3,294.2
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	959.4	941.8	757.6	725.6	972.4
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.54-13.84	6.16-11.95	6.20-11.94	6.18-11.97	6.23-11.95

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016	2017					
		जुला 1	मई 26	जून 2	जून 9	जून 16	जून 23	जून 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	259.0	213.7	234.1	177.1	286.4	190.7	267.7	168.5
2 नोटिस मुद्रा	46.8	74.1	11.5	48.3	5.1	51.9	5.0	56.8
3 मीयादी मुद्रा	8.4	13.1	6.4	7.9	5.5	10.9	6.8	11.6
4 सीबीएलओ	1,700.2	1,825.3	1,642.3	2,239.1	1,656.2	1,971.3	1,742.5	2,326.9
5 बाजार रिपो	1,753.3	1,771.5	1,851.1	1,895.6	1,920.2	2,131.6	2,070.3	2,022.1
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2.5	1.2	2.8	2.0	3.1	3.2	13.1	1.1
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	71,563	53,597	56,032	50,693	52,579	51,970	72,009
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,249.1	1,709.0	923.1	751.4	1,268.7	1,191.7	1,089.9	878.8
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	50.7	64.9	42.3	42.7	66.3	74.7	59.8	103.1
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	45.1	52.9	33.1	23.7	36.8	41.3	46.3	93.6
10.2 182-दिवसीय	11.8	12.5	14.0	6.6	11.8	14.3	6.4	31.6
10.3 364-दिवसीय	18.5	28.5	10.0	14.2	4.5	7.6	9.0	8.0
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13.8	—	3.6	87.3	87.0	23.0	8.1	90.4
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	1388.8	1,867.8	1,026.1	925.9	1,475.1	1,352.7	1,219.5	1,205.6
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	—	5.2	0.0	4.5	0.4	1.5	0.1	1.6

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2016-17 *		2016-17 (अप्रै.-जून)		2017-18 (अप्रै.-जून)*		जून 2016		जून 2017*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	116	303.6	19	49.0	32	71.2	9	4.8	15	56.3
1ए प्रीमियम	113	291.3	18	45.5	32	68.5	9	4.5	15	54.4
1.1 पब्लिक	105	280.7	18	48.2	29	66.3	9	4.8	14	55.1
1.1.1 प्रीमियम	102	270.4	17	44.9	29	64.1	9	4.5	14	53.5
1.2 राइट्स	11	22.9	1	0.8	3	4.9	-	-	1	1.2
1.2.1 प्रीमियम	11	20.9	1	0.7	3	4.4	-	-	1	0.9
2 अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 डिबेंचर	16	295.5	4	19.0	1	19.7	-	-	-	-
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	16	295.5	4	19.0	1	19.7	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	16	295.5	4	19.0	1	19.7	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल (1+2+3+4)	132	599.0	23	68.0	33	90.9	9	4.8	15	56.3
5.1 पब्लिक	121	576.1	22	67.2	30	86.0	9	4.8	14	55.1
5.2 राइट्स	11	22.9	1	0.8	3	4.9	-	-	1	1.2

* आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2016-17	2016		2017			
			जून	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून
			1	2	3	4	5	6
1 निर्यात	बिलियन ₹	18,541.0	1,519.0	1,713.3	1,919.9	1,589.1	1,547.1	1,518.4
	अमरीकी मिलियन डालर	276,547.0	22,572.3	25,543.5	29,144.5	24,635.2	24,014.6	23,562.6
1.1 तेल	बिलियन ₹	2,120.3	173.3	171.0	245.0	191.0	165.0	171.9
	अमरीकी मिलियन डालर	31,622.3	2,575.0	2,549.6	3,718.4	2,960.5	2,561.7	2,667.7
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	16,420.7	1,345.8	1,542.3	1,675.0	1,398.2	1,382.1	1,346.5
	अमरीकी मिलियन डालर	244,924.7	19,997.3	22,993.9	25,426.1	21,674.7	21,452.9	20,894.9
2 आयात	बिलियन ₹	25,668.2	2,065.2	2,229.0	2,613.3	2,458.6	2,438.9	2,353.6
	अमरीकी मिलियन डालर	382,740.9	30,688.5	33,231.4	39,668.9	38,113.6	37,856.3	36,522.5
2.1 तेल	बिलियन ₹	5,825.6	488.0	516.7	639.9	474.8	495.6	523.6
	अमरीकी मिलियन डालर	86,865.7	7,252.1	7,703.3	9,714.0	7,360.3	7,692.7	8,125.5
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	19,842.6	1,577.2	1,712.3	1,973.3	1,983.8	1,943.3	1,830.0
	अमरीकी मिलियन डालर	295,875.2	23,436.4	25,528.1	29,954.9	30,753.3	30,163.6	28,397.0
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-7,127.2	-546.2	-515.7	-693.3	-869.5	-891.8	-835.2
	अमरीकी मिलियन डालर	-106,193.9	-8,116.2	-7,687.9	-10,524.4	-13,478.4	-13,841.7	-12,959.9
3.1 तेल	बिलियन ₹	-3,705.4	-314.8	-345.7	-395.0	-283.8	-330.6	-351.7
	अमरीकी मिलियन डालर	-55,243.4	-4,677.1	-5,153.7	-5,995.6	-4,399.8	-5,131.0	-5,457.8
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-3,421.9	-231.4	-170.0	-298.3	-585.6	-561.2	-483.5
	अमरीकी मिलियन डालर	-50,950.6	-3,439.1	-2,534.2	-4,528.8	-9,078.6	-8,710.7	-7,502.0

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2016	2017					
		जुला 22	जून 16	जून 23	जुला 30	जुला 7	जुला 14	जुला 21
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	24,234	24,664	24,683	25,019	25,007	25,078	25,174
	अमरीकी मिलियन डालर	362,687	381,955	382,532	386,539	386,378	389,059	391,331
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	22,584	23,123	23,142	23,455	23,444	23,515	23,610
	अमरीकी मिलियन डालर	338,257	358,084	358,665	362,389	362,232	364,909	367,149
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,391	1,297	1,297	1,317	1,317	1,317	1,317
	अमरीकी मिलियन डालर	20,576	20,096	20,096	20,349	20,349	20,349	20,349
1.3 एसडीआर	बिलियन ₹	1,066	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
	अमरीकी मिलियन डालर	99	95	95	96	96	95	96
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	1,476	1,469	1,468	1,480	1,478	1,480	1,492
	अमरीकी मिलियन डालर	160	149	149	150	150	150	151
	अमरीकी मिलियन डालर	2,377	2,306	2,304	2,322	2,319	2,322	2,341

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2016-17	2016	2017		2016-17	2017-18
		जून	मई	जून	अप्रै.-जून	अप्रै.-जून
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	116,867	126,266	117,456	118,131	1,377	1,120
1.1 एफसीएनआर (बी)	21,002	45,075	21,212	20,923	-241	-79
1.2 एनआर (ई) आरए	83,213	71,226	83,704	84,470	1,547	1,133
1.3 एनआरओ	12,652	9,965	12,540	12,737	71	66

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2016-17	2016-17	2017-18	2016	2017	
		अप्रै.-जून	अप्रै.-जून	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	35,612	3,882	8,039	1,260	3,752	2,544
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	42,215	5,896	10,877	1,681	4,189	3,347
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	60,220	11,748	14,550	3,631	5,370	4,529
1.1.1.1.1 ईक्विटी	44,701	7,874	10,692	2,340	4,155	3,214
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	5,900	708	266	126	109	121
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	30,417	3,985	8,461	1,800	3,368	2,572
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,161	2,898	1,681	319	583	426
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1,223	284	284	95	95	95
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	12,343	3,169	3,169	1,056	1,056	1,056
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,176	705	689	235	159	258
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	18,005	5,852	3,673	1,951	1,181	1,181
1.1.1.2.1 ईक्विटी	17,318	5,784	3,524	1,928	1,117	1,117
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	687	69	149	23	64	64
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	6,603	2,014	2,838	420	437	803
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	9,792	2,427	1,764	611	429	537
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,925	731	731	244	244	244
1.1.2.3 अन्य पूंजी	4,450	1,281	1,197	373	121	378
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	10,564	2,425	854	808	356	356
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	7,612	2,103	12,377	9	4,626	4,533
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	7,766	1,241	11,921	-279	4,681	4,587
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	154	-863	-456	-288	55	55
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	43,224	5,985	20,416	1,269	8,378	7,077

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2016-17	2016	2017		
		जून	अप्रै.	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	8,170.7	683.7	761.3	847.1	905.1
1.1 जमाराशियां	283.8	16.3	49.0	27.9	26.3
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	92.9	7.5	6.7	6.7	10.1
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	443.6	26.4	43.1	30.7	44.3
1.4 उपहार	749.5	56.3	105.3	95.9	83.5
1.5 दान	8.8	0.9	2.5	0.6	0.3
1.6 यात्रा	2,568.0	221.9	200.4	285.2	352.6
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,169.5	169.7	244.8	256.5	229.5
1.8 चिकित्सा उपचार	17.3	1.2	2.2	1.6	2.4
1.9 विदेश में शिक्षा	1,536.4	103.7	90.3	133.0	144.8
1.10 अन्य	300.8	79.8	17.0	9.0	11.3

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2015-16	2016-17	2016		2017	
			जुला	जून	जुला	जून
	1	2	3	4	5	6
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)						
1 व्यापार आधारित भारांक						
1.1 नीर	74.76	74.66	73.96	77.85	77.61	
1.2 रीर	112.07	114.50	114.17	118.25	117.89	
2 निर्यात आधारित भारांक						
2.1 नीर	76.45	76.39	75.51	79.76	79.49	
2.2 रीर	114.44	116.44	116.10	120.25	119.86	
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक						
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100						
1.1 नीर	67.52	67.17	66.53	69.85	69.26	
1.2 रीर	122.71	125.99	125.28	131.19	130.07	
2 आधार : 2015-16 (अप्रैल-मार्च) =100						
2.1 नीर	100.00	99.47	98.53	103.45	102.57	
2.2 रीर	100.00	102.67	102.09	106.90	105.99	

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

मद	2016-17	2016		2017	
		जून	मई	जून	मई
	1	2	3	4	5
1 स्वचालित मार्ग					
1.1 संख्या	729	65	44	76	
1.2 राशि	16,247	908	1,049	1,335	
2 अनुमोदन मार्ग					
2.1 संख्या	37	3	1	2	
2.2 राशि	5,738	164	1	299	
3 कुल (1+2)					
3.1 संख्या	766	68	45	78	
3.2 राशि	21,985	1,072	1,050	1,634	
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.30	4.90	5.20	6.00	
5 ब्याज दर (प्रतिशत)					
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.62	1.65	1.56	2.50	
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-14.75	0.00-12.00	0.00-11.00	0.00-12.00	

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	जन.-मार्च 2016 (आं.सं)			जन.-मार्च 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	252,123	248,848	3,274	283,799	276,488	7,312
1 चालू खाता (1.1+1.2)	124,652	124,990	-338	138,288	141,741	-3,452
1.1 पण्य	65,831	90,586	-24,755	77,354	107,076	-29,722
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	58,821	34,404	24,417	60,934	34,665	26,270
1.2.1 सेवाएं	39,413	23,336	16,077	40,717	23,081	17,636
1.2.1.1 यात्रा	5,904	3,580	2,324	6,720	3,630	3,090
1.2.1.2 परिवहन	3,550	3,666	-115	4,226	3,694	533
1.2.1.3 बीमा	520	249	271	591	439	153
1.2.1.4 जीएनआईई	133	230	-97	136	146	-10
1.2.1.5 विविध	29,306	15,611	13,695	29,043	15,173	13,871
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	18,064	736	17,328	17,813	974	16,839
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	7,291	8,664	-1,373	8,320	8,176	144
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	983	596	387	1,007	1,431	-424
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	601	344	257	666	204	462
1.2.2 अंतरण	15,729	768	14,961	15,735	1,549	14,186
1.2.2.1 आधिकारिक	41	225	-185	34	216	-183
1.2.2.2 निजी	15,689	542	15,146	15,701	1,333	14,368
1.2.3 आय	3,679	10,300	-6,621	4,482	10,034	-5,552
1.2.3.1 निवेश आय	2,839	9,749	-6,910	3,366	9,399	-6,033
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	839	551	288	1,116	635	481
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	127,313	123,858	3,455	145,139	134,747	10,392
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	66,942	59,683	7,259	85,079	69,283	15,796
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	16,114	7,318	8,797	13,999	9,001	4,997
2.1.1.1 भारत में	14,752	3,367	11,384	12,342	3,201	9,141
2.1.1.1.1 इक्विटी	10,895	3,343	7,553	7,968	2,818	5,149
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,098	-	3,098	3,241	-	3,241
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	758	25	733	1,133	383	750
2.1.1.2 विदेश में	1,363	3,950	-2,588	1,657	5,800	-4,143
2.1.1.2.1 इक्विटी	1,363	2,367	-1,004	1,657	3,471	-1,814
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	834	-834	0	731	-731
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	749	-749	0	1,598	-1,598
2.1.2 संविभाग निवेश	50,828	52,366	-1,538	71,080	60,282	10,799
2.1.2.1 भारत में	50,540	51,327	-787	70,858	59,727	11,131
2.1.2.1.1 एफआईआई	50,540	51,327	-787	70,858	59,727	11,131
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	40,988	40,805	183	57,118	50,678	6,440
2.1.2.1.1.2 ऋण	9,552	10,522	-970	13,739	9,049	4,691
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	288	1,038	-751	223	554	-332
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	32,714	31,444	1,270	34,267	30,279	3,987
2.2.1 बाह्य सहायता	2,134	1,147	987	2,020	1,154	866
2.2.1.1 भारत द्वारा	15	126	-111	14	58	-43
2.2.1.2 भारत को	2,119	1,021	1,098	2,005	1,096	909
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	7,025	9,381	-2,356	6,976	7,851	-875
2.2.2.1 भारत द्वारा	1,926	1,646	280	1,736	1,675	61
2.2.2.2 भारत को	5,099	7,735	-2,636	5,240	6,176	-936
2.2.3 भारत को अल्पावधि	23,556	20,917	2,639	25,270	21,274	3,996
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	22,505	20,917	1,588	24,645	21,274	3,371
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1,051	0	1,051	625	0	625
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	18,939	27,941	-9,002	16,039	29,081	-13,042
2.3.1 वाणिज्य बैंक	18,904	27,941	-9,036	16,034	29,081	-13,047
2.3.1.1 आस्तियां	3,001	12,954	-9,952	163	11,215	-11,053
2.3.1.2 देयताएं	15,903	14,987	916	15,872	17,866	-1,994
2.3.1.2.1 अनिवासी जमा राशियां	15,052	10,664	4,388	15,006	12,308	2,698
2.3.2 अन्य	34	0	34	5	0	5
2.4 रुपया ऋण चुकौती	-	22	-22	0	48	-48
2.5 अन्य पूंजी	8,718	4,767	3,951	9,755	6,056	3,698
3 भूल-चूक	158	-	158	372	-	372
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	3,274	-3,274	0	7,312	-7,312
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	-	3,274	-3,274	0	7,312	-7,312

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	जन.-मार्च 2016 (आं.सं)			जन.-मार्च 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	17,019	16,798	221	19,018	18,528	490
1 चालू खाता (1.1+1.2)	8,414	8,437	-23	9,267	9,498	-231
1.1 पण्य	4,444	6,115	-1,671	5,184	7,175	-1,992
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	3,971	2,322	1,648	4,083	2,323	1,760
1.2.1 सेवाएं	2,661	1,575	1,085	2,728	1,547	1,182
1.2.1.1 यात्रा	399	242	157	450	243	207
1.2.1.2 परिवहन	240	247	-8	283	248	36
1.2.1.3 बीमा	35	17	18	40	29	10
1.2.1.4 जीएनआईई	9	16	-7	9	10	-1
1.2.1.5 विविध	1,978	1,054	924	1,946	1,017	929
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,219	50	1,170	1,194	65	1,128
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	492	585	-93	558	548	10
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	66	40	26	67	96	-28
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	41	23	17	45	14	31
1.2.2 अंतरण	1,062	52	1,010	1,054	104	951
1.2.2.1 आधिकारिक	3	15	-12	2	14	-12
1.2.2.2 निजी	1,059	37	1,022	1,052	89	963
1.2.3 आय	248	695	-447	300	672	-372
1.2.3.1 निवेश आय	192	658	-466	226	630	-404
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	57	37	19	75	43	32
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8,594	8,361	233	9,726	9,030	696
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	4,519	4,029	490	5,701	4,643	1,059
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	1,088	494	594	938	603	335
2.1.1.1 भारत में	996	227	768	827	214	613
2.1.1.1.1 इक्विटी	735	226	510	534	189	345
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	209	0	209	217	0	217
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	51	2	50	76	26	50
2.1.1.2 विदेश में	92	267	-175	111	389	-278
2.1.1.2.1 इक्विटी	92	160	-68	111	233	-122
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	56	-56	0	49	-49
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	51	-51	0	107	-107
2.1.2 संविभाग निवेश	3,431	3,535	-104	4,763	4,040	724
2.1.2.1 भारत में	3,412	3,465	-53	4,748	4,002	746
2.1.2.1.1 एफआईआई	3,412	3,465	-53	4,748	4,002	746
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	2,767	2,755	12	3,828	3,396	432
2.1.2.1.1.2 ऋण	645	710	-65	921	606	314
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	19	70	-51	15	37	-22
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	2,208	2,123	86	2,296	2,029	267
2.2.1 बाह्य सहायता	144	77	67	135	77	58
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	8	-7	1	4	-3
2.2.1.2 भारत को	143	69	74	134	73	61
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	474	633	-159	467	526	-59
2.2.2.1 भारत द्वारा	130	111	19	116	112	4
2.2.2.2 भारत को	344	522	-178	351	414	-63
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,590	1,412	178	1,693	1,426	268
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,519	1,412	107	1,652	1,426	226
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	71	0	71	42	0	42
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	1,278	1,886	-608	1,075	1,949	-874
2.3.1 वाणिज्य बैंक	1,276	1,886	-610	1,074	1,949	-874
2.3.1.1 आस्तियां	203	874	-672	11	752	-741
2.3.1.2 देयताएं	1,074	1,012	62	1,064	1,197	-134
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	1,016	720	296	1,006	825	181
2.3.2 अन्य	2	0	2	0	0	0
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	3	-3
2.5 अन्य पूंजी	589	322	267	654	406	248
3 भूल-चूक	11	0	11	25	-	25
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	221	-221	0	490	-490
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	221	-221	0	490	-490

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	जन.-मार्च 2016 (आ.स)			जन.-मार्च 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	8,414	8,436	-21	9,267	9,497	-230
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	7,104	7,690	-586	7,912	8,722	-810
1.अ.क.माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	4,444	6,115	-1,671	5,184	7,175	-1,992
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	4,594	5,758	-1,164	5,202	6,525	-1,324
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-150	0	-150	-18	0	-18
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	357	-357	-	650	-650
1.अ.ख.सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	2,661	1,575	1,085	2,728	1,547	1,182
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	3	2	1	2	1	1
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	2	6	-3	5	8	-3
1.अ.ख.3 परिवहन	240	247	-8	283	248	36
1.अ.ख.4 यात्रा	399	242	157	450	243	207
1.अ.ख.5 निर्माण	34	21	12	38	16	21
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	35	17	18	40	29	10
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	66	40	26	67	96	-28
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	7	73	-67	9	90	-81
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,266	80	1,185	1,243	86	1,158
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	492	585	-93	558	548	10
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	23	10	13	22	30	-8
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	9	16	-7	9	10	-1
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	86	236	-150	3	142	-139
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	248	695	-447	300	672	-372
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	57	37	19	75	43	32
1.आ.2 निवेश आय	163	647	-484	176	615	-439
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	95	305	-211	88	293	-205
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	2	127	-126	3	112	-109
1.आ.2.3 अन्य निवेश	11	214	-204	16	210	-193
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	56	0	56	68	0	68
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	28	11	18	50	15	35
1.इ दिवतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,062	50	1,011	1,054	102	952
1.इ.1 वित्तीय निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,059	37	1,022	1,052	89	963
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	1,023	31	992	1,016	72	944
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	36	5	31	37	17	19
1.इ.2 सामान्य सरकार	3	14	-11	2	13	-11
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	5	4	1	6	5	2
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	2	0	1	3	1	2
2.2 पूंजी अंतरण	3	4	-1	3	4	-1
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	8,589	8,579	10	9,720	9,516	204
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	1,088	494	594	938	603	335
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	996	227	768	827	214	613
3.1अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	945	226	719	751	189	562
3.1अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	735	226	510	534	189	345
3.1अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	209	0	209	217	0	217
3.1अ.2 ऋण लिखत	51	2	50	76	26	50
3.1अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	51	2	50	76	26	50
3.1आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	92	267	-175	111	389	-278
3.1आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	92	216	-124	111	282	-171
3.1आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	92	160	-68	111	233	-122
3.1आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	56	-56	0	49	-49
3.1आ.2 ऋण लिखत	0	51	-51	0	107	-107
3.1आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	51	-51	0	107	-107
3.2 संविभाग निवेश	3,431	3,535	-104	4,763	4,040	724
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	3,412	3,465	-53	4,748	4,002	746
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	2,767	2,755	12	3,828	3,396	432
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	645	710	-65	921	606	314
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	19	70	-51	15	37	-22
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	328	157	171	293	98	195
3.4 अन्य निवेश	3,742	4,172	-429	3,725	4,286	-560
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	1,018	720	299	1,006	825	181
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मुवमेंट; एनआरजी)	2	0	2	0	0	0
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	1,016	720	296	1,006	825	181
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	878	1,877	-999	672	1,727	-1,056
3.4.3अ भारत को ऋण	747	1,757	-1,010	554	1,611	-1,057
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	131	120	11	117	116	1
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	2	48	-46	2	11	-10
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,590	1,412	178	1,693	1,426	268
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	254	115	138	352	296	56
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	221	-221	0	490	-490
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	221	-221	0	490	-490
4. कुल आस्तियां / देयताएं	8,589	8,579	10	9,720	9,516	204
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	4,153	3,471	681	5,000	4,013	987
4.2 ऋण लिखत	4,183	4,771	-589	4,368	4,717	-349
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	254	336	-83	352	786	-434
5. निवल भूल-चूक	11	-	11	25	-	25

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2016-17		2016				2017	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	148,229	342,651	141,626	293,862	144,086	318,519	148,229	342,651
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	99,114	327,845	96,961	280,267	96,569	304,538	99,114	327,845
1.2 अन्य पूंजी	49,115	14,806	44,665	13,595	47,516	13,981	49,115	14,806
2 संविभाग निवेश	2,615	238,678	2,461	224,788	2,283	221,189	2,615	238,678
2.1 इक्विटी	1,593	153,978	1,541	141,864	2,280	140,567	1,593	153,978
2.2 ऋण	1,022	84,700	919	82,924	4	80,622	1,022	84,700
3 अन्य निवेश	45,032	377,339	47,460	392,523	37,734	365,341	45,032	377,339
3.1 व्यापार ऋण	3,429	88,821	4,548	82,283	3,585	84,779	3,429	88,821
3.2 ऋण	7,306	159,893	6,688	170,426	4,220	160,216	7,306	159,893
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,073	117,110	20,861	127,109	14,594	110,020	20,073	117,110
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	14,223	11,515	15,363	12,705	15,335	10,327	14,223	11,515
4 रिज़र्व्स	369,955	–	360,177	–	358,898	–	369,955	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	565,830	958,668	551,724	911,174	543,001	905,049	565,830	958,668
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-392,838		-359,450		-362,048		-392,838

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2016-17	2017			2016-17	2017		
		अप्रै.	मई	जून		अप्रै.	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	107.86	9.54	10.43	9.83	1,253,652.08	111,743.70	113,312.69	116,200.57
1.1 ग्राहक लेनदेन	103.66	9.23	10.09	9.51	849,950.51	73,603.70	80,716.62	83,330.95
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	4.17	0.31	0.35	0.32	131,953.25	14,908.49	9,453.90	9,481.63
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.018	0.002	0.002	0.002	271,748.31	23,231.51	23,142.16	23,387.99
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.65	0.25	0.29	0.30	1,056,173.36	80,878.53	86,202.69	90,919.03
2.1 सीबीएलओ	0.22	0.01	0.02	0.02	229,528.33	21,151.19	21,769.86	21,892.28
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.51	0.08	0.10	0.12	404,389.08	24,111.22	31,150.92	36,913.97
2.2.1 एकमुश्त	1.34	0.07	0.08	0.11	168,741.46	7,482.65	9,926.66	13,709.92
2.2.2 रिपो	0.168	0.014	0.016	0.017	235,647.62	16,628.57	21,224.26	23,204.05
2.3 विदेशी समाशोधन	1.93	0.16	0.17	0.16	422,255.95	35,616.13	33,281.91	32,112.78
3 पेपर समाशोधन	1,206.69	99.97	101.63	95.47	80,958.15	7,351.49	7,100.00	6,669.43
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	1,111.86	95.26	97.08	91.85	74,035.22	6,990.65	6,745.89	6,409.95
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2 अन्य केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	94.83	4.71	4.55	3.61	6,922.93	360.84	354.10	259.48
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	4,204.96	431.10	427.36	426.75	132,250.12	13,700.63	13,768.40	14,113.17
4.1 ईसीएस नामे	8.76	0.19	0.17	0.13	39.14	1.21	1.06	0.89
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	10.10	0.49	0.62	0.64	144.08	9.68	10.36	10.49
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	1,622.10	143.17	155.82	152.34	120,039.68	12,156.17	12,410.81	12,694.20
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	506.73	65.08	66.72	65.84	4,111.06	562.06	585.59	596.55
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	2,057.27	222.17	204.03	207.79	7,916.17	971.50	760.58	811.05
5 कार्ड	12,055.87	1,035.38	1,036.07	1,025.60	30,214.00	2,877.17	2,899.56	2,953.60
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,093.51	107.06	115.88	110.03	3,312.21	333.76	364.02	357.50
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	6.37	0.48	0.55	0.55	28.39	2.33	2.61	2.67
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,087.13	106.58	115.33	109.47	3,283.82	331.43	361.41	354.83
5.2 डेबिट कार्ड	10,962.36	928.32	920.20	915.57	26,901.79	2,543.41	2,535.54	2,596.09
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	8,563.06	660.32	655.47	660.91	23,602.73	2,168.60	2,163.92	2,220.86
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	2,399.30	268.00	264.72	254.66	3,299.07	374.82	371.62	375.24
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	1,963.66	352.23	278.08	255.65	838.01	103.71	106.69	85.07
6.1 एम-वॉलेट	1,629.98	320.87	241.72	221.63	532.42	74.42	71.94	53.10
6.2 पीपीआई कार्ड	333.11	31.32	36.32	33.97	277.52	27.45	32.75	29.87
6.3 पेपर वाउचर	0.51	0.04	0.04	0.05	25.36	1.85	2.01	2.10
7 मोबाइल बैंकिंग	976.85	106.27	114.26	115.73	13,104.76	1,612.65	2,134.20	1,807.65
8 कार्ड बकाया	884.72	897.38	910.88	825.31	-	-	-	-
8.1 क्रेडिट कार्ड	29.84	30.37	30.86	31.48	-	-	-	-
8.2 डेबिट कार्ड	854.87	867.00	880.03	793.83	-	-	-	-
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	222475	221959	222813	222926	-	-	-	-
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	2529141	2614584	2692986	2776949	-	-	-	-
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	19,542.66	1,928.48	1,853.86	1,813.60	2,282,337.40	193,423.72	200,247.86	207,552.89

टिप्पणिया: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8.4.12 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.9 से 4.11 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वता वार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं.7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं.8

एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं.9

वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनःदिए गए हैं।

सारणी सं.13

कालम सं (1),(2) और (3) के सामने दर्शाए गए आंकड़े अंतिम (आरआरबी सहित) हैं और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं.15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 95 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका. प्लान.बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

चूँकि भारतीय स्टेट बैंक से समामेलन के उपरांत के समेकित आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः 28 अप्रैल 2017 के आंकड़ों के लिए इसकी चारों पूर्व अनुषंगियों यथा- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से प्राप्त 31 मार्च 2017 के आंकड़ों को ही दोहराया गया है।

सारणी सं.17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं.24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं.30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी-अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं.32

आईआईएफ सी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमरीकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर-यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमरीकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं.34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आंकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं.35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं.36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2012-13 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं.37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं.38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं.43

1.3 : बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3 : 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल हैं। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

इस तिमाही में, संशोधित टेबल फार्मेट केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पहली बार राज्य सरकारों की धारित प्रतिभूतियों को अलग श्रेणी में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां, न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल हैं।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2017	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का अभिदान) ₹3150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3360 (एक वर्ष का अंशदान - डाक प्रभार सहित ^o) ₹2520 (एक वर्ष का रियायती दर*)	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का अभिदान) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय स्टेट 2016-17 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹550 एक प्रति (सामान्य) ₹600 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय इकोनॉमी 2015-16 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹500 एक प्रति (सामान्य) ₹550 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹375 एक प्रति (रियायती) ₹425 एक प्रति (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त : 2016-17 के बजटों का अध्ययन	₹500 एक प्रति (काउंटर पर) ₹550 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 23 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मिंट रोड माइलस्टोन्स : आरबीआई ऐट 75	₹1650 एक प्रति (काउंटर पर)	अमरीकी डॉलर 50 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 25 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. भारत में अनसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकी विवरणियां, खंड 41 मार्च 2012	₹270 एक प्रति (काउंटर पर) ₹310 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 10 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणिया:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों/ व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई- 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. अभिदान मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषण पत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुम्बई- 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रतापूर्वक भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपना अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई मेल आईडी to spsdcs@rbi.org.in को प्रेषित करें ताकि हम सुचारु रूप से आपके साथ संपर्क कर सकें।

